रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1975/कार्तिक 3, 1897
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1975/KARTIKA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 4541.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षा के परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में,

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात्—

(1) यह सरकारी सेवक जो अधिवर्षता पर निवृत्त होता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या आगे सेवा के लिये अक्षमता घोषित कर दिया जाता है,—

(क) उस दशा में अपनी सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास के आधे वेतन की दर से उपदान पाने का पात्र होगा जब कि उसने निवृत्ति सेवामुक्त किये जाने या अक्षमत किये जाने के समय पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है ।

(ख) 15 मास के वेतन या 15 हजार रुपए, जो भी कम हो, को अधिकतम सीमा में रहते हुए अपनी सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास की वेतन की दर से उपदान पाने का उस दशा में पात्र होगा जब कि सेवा

निवृत्ति, सेवान्मुक्त किये जाने या अशक्त किए जाने के समय पर उसने कम से कम दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं कर ली है ।

यह इस शर्त के अधीन होगा कि सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को उसे नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद मान लिया जाए,

(ख) उप-नियम (2) में, —

(i) खण्ड (ग) में "यदि मृत्यु पांच वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद हो जाती है तो," शब्दों के स्थान पर "यदि मृत्यु पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद किन्तु दस वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले होती है" शब्द रखे जायेंगे ।

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा—

(घ) यदि मृत्यु दस वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के के बाद हो जाती है, तो 15 मास के वेतन या पन्द्रह हजार रुपये, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास के वेतन के बराबर उपदान,

यह इस शर्त के अधीन होगा कि सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को उसे नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद मान लिया जाये ।

(iii) परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को, उसको नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद नहीं माना जाता है वहां ऐसा प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा उनमें उल्लिखित कारणों के आधार पर उपदान की रकम में ऐसी कमी कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे,

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन संदेय सेवान्त उपदान की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जिसे सरकारी सेवक भविष्य निधि में अनुरूप सरकारी अभिदाय के रूप में उस दशा में पाता जब कि वह, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अनुरूप अभिदाय किसी भी दशा में उसके वेतन के 8½ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, निरन्तर अस्थायी सेवा की तारीख से अभिदायी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य रहता।"

(ग) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्—

(3) इस नियम के अधीन ऐसे सरकारी सेवक को,

(क) कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा जो अपने पद से त्याग-पत्र देता है या जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में सेवा से हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है,

(ख) कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा जिसे निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजित किया जाता है ।

(4) जहां कोई सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 द्वारा शासित होता है, वहां सरकारी सेवक को संदेय उपदान में से अभिदाय के रूप में दो मास के वेतन के बराबर रकम वसूल की जायेगी ।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक को जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 द्वारा शासित नहीं होता है, इस नियम के अधीन कोई उपदान दिया जाता है वहां कोई अन्य उपदान या पेंशन के फायदे संदेय नहीं होंगे ।

(6) इस नियम या नियम 11 के प्रयोजनार्थ :—

(क) उपदान की संगणना पिछले बारह मास के वेतन के आधार पर की जायेगी,

(ख) वेतन से मूल नियमों में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है, और

(ग) सम्पूरित सेवा की गणना करने के लिये सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि उसी आधार पर हिसाब में ली जायेगी जिस आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 21 के अधीन पेंशन और मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिये उसे हिसाब में लिया जाता है ।"

3 उक्त नियमों के नियम 11 में—

"(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात्—

(i) स्थायीवत्, सेवाधीन सरकारी सेवक, यदि उसकी सेवाएं किसी अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में या त्यागपत्र देने के कारण समाप्त की गई हो ।

(क) अपनी सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये उस दशा में एक मास के वेतन के आधे की दर से उपदान पाने का पात्र होगा जब कि समाप्ति के समय उसने कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर स्थायीवत् सेवा पूरी कर ली हो,

(ख) पन्द्रह मास के वेतन या पन्द्रह हजार रुपए, जो भी कम हो की अधिकतम सीमा में रहते हुए, अपनी सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास के वेतन की दर से उपदान पाने का पात्र उस दशा में होगा जब कि समाप्ति के समय उसने कम से कम दस वर्ष की निरन्तर स्थायीवत् सेवा पूरी कर ली हो,

यह इस शर्त के अधीन होगा कि सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को उसको नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोष-प्रद मान लिया जाये।"

(ख) उप-नियम (2) में,—

(i) खण्ड (ii) में "यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के पांच वर्ष या उससे अधिक पूरा होने के बाद होती है" शब्दों के स्थान पर "यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के पांच वर्ष के बाद किन्तु दस वर्ष पूरा होने से पहले होती है" शब्द रखे जायेंगे।

(ii) खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

(iii) यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के दस वर्ष या उससे अधिक पूरा होने के बाद हो जाती है, तो पन्द्रह मास के वेतन या

पन्द्रह हजार रुपये जो भी कम हो की अधिकतम सीमा में रहते हुए निरन्तर सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये एक मास के वेतन के बराबर उपदान,

यह इस शर्त के अधीन होगा कि सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के उसको नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सन्तोषप्रद मान लिया जाये ।

(iii) परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु जहां सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा, उसको नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद नहीं माना जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा उसमें उल्लिखित कारणों के आधार पर उपदान की रकम में ऐसी कटौती कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन संदेय सेवान्त उपदान की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जिसे सरकारी सेवक उस दशा में भविष्य निधि में अनुरूप सरकारी अभिदाय के रूप में पाता जब कि वह, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी भी दशा में अनुरूप अभिदाय उसके वेतन के 8⅓ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । अपनी निरन्तर अस्थायी सेवा की तारीख से अभिदायी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य रहता ।

(ग) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखे जायेंगे—

"(3) इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा जब कि,—

(क) वह अपने पद से त्यागपत्र देता है या अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में उसे हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है ।

(ख) निवृत्ति के पश्चात उसे पुनः नियोजित किया जाता है ।

(4) जहां कोई सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 द्वारा शासित होता है वहां ऐसे सरकारी सेवक को संदेय उपदान में से अभिदाय के रूप में दो मास के वेतन के बराबर की रकम वसूल की जाएगी ।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक को, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 द्वारा शासित होता है, इस नियम के अधीन कोई उपदान दिया जाता है । वहां कोई अन्य उपदान, पेंशन के फायदे संदेय नहीं होंगे ।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिये—

(क) "स्थायिवत् सेवा" के अन्तर्गत बिल्कुल अस्थायी सेवा का दो तिहाई उस दशा में सम्मिलित होगा जब कि निवृत्ति सेवान्मुक्त किये जाने, मृत्यु या अशक्त किये जाने की तारीख पर निरन्तर सेवा की कुल अवधि पांच वर्ष से कम न हो,

(ख) "निरन्तर सेवा" से कुल सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत स्थायीवत् और अस्थायी सेवा के अल्पकाल भी सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1975 का स्पष्टीकारक ज्ञापन ।

अस्थायी तथा स्थायीवत् कर्मचारियों को सेवान्त प्रसुविधाओं की मंजूरी के लिये दरों और शर्तों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट के अध्याय 60 के पैरा 63 से 65 में की गई सिफारिशों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 1 नवम्बर, 1973 के संकल्प संख्या 70 (39)—74-आई० सी० तथा 1 मई, 1974 के संकल्प संख्या एफ० 11(35)/74-आई० सी० द्वारा, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । एक नवम्बर, 1973 के संकल्प में यह निर्धारित किया गया है कि वेतन तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधायों के संबंध में आयोग की सिफारिशों को एक मार्च, 1973 के बजाय, जैसा कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी 1 जनवरी, 1974 से लागू किया जायेगा । इस लिये केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1975 को जिनमें अस्थायी तथा स्थायीवत् कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं की मंजूरी के सम्बंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया है, 1 जनवरी, 1973 से लागू किया जाता है। इस संशोधन से किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 4/2/65-स्था(सी)]

एस० कृष्णन्, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4541.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1973.

2. In rule 10 of Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 (thereinafter referred to as the said rules),—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) A temporary government servant who retires on superannuation or is discharged from service or is declared invalid for further service shall be eligible for gratuity at the rate of—

(a) one-half of a month's pay for each completed year of his service, if he had completed not less than five years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment ;

(b) one month's pay for each completed year or his service, subject to a maximum of fifteen months' pay or fifteen thousand rupees, whichever is less, if he had completed not less than ten years continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment, subject to the condition of service rendered by the government servant concerned being held by the

authority competent to appoint him to be satisfactory." ;

(b) in sub-rule (2),—

(i) in clause (c), for the words "if the death takes place after completion of five years service or more" the words "if the death takes place after completion of five years but before completion of ten years' service shall be substituted;

(ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely :—

"(d) if the death takes place after completion of ten years' service or more, a gratuity equal to one month's pay for each completed year of service subject to a maximum of fifteen months' pay or fifteen thousand rupees, whichever is less, subject to the condition of service rendered by the government servant concerned being held by the authority competent to appoint him to be satisfactory" ;

(iii) for the provisos and the Explanation, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that where the service rendered by the government servant concerned is not held by the authority competent to appoint him to be satisfactory, such authority may, by order and for reasons to be mentioned therein, make such reduction in the amount of gratuity as it may consider proper :

Provided further that the amount of terminal gratuity payable under this rule shall not be less than the amount which the government servant would have got as a matching government contribution to the provident fund if he were a member of a Contributory Provident Fund Scheme from the date of his continuous temporary service, subject to the condition that the maching contribution shall not in any case exceed 8-1/3 per cent of his pay." ;

(c) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

(3) No gratuity shall be admissible under this rule to a government servant,—

(a) who resigns his post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure ;

(b) who is re-employed after retirement.

(4) Where a government servant is covered by rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 an amount equal to two months' pay shall be recovered as a contribution out of the gratuity payable to the government servant.

(5) Where gratuity under this rule is paid to or in respect of a government servant who is not covered by rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, no other gratuity or pensionary benefits is payable.

(6) For the purpose of this rule and rule 11,—

(a) gratuity shall be calculated on the basis of the last twelve months' pay ;

(b) 'pay' shall mean pay as defined in the Fundamental Rules ; and

(c) period of extraordinary leave, if any, availed of by the government servant concerned shall be taken into account for computing the completed service on the same basis as it is taken into account for the purposes of the calculation of pension and death-cum-retirement gratuity under rule 21 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time." ;

3. In rule 11 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) A government servant in quasi-permanent service shall, if his services are terminated otherwise than as a disciplinary measure or by resignation, be eligible for gratuity at the rate of—

(a) one-half of a month's pay for each completed year of his service, if he had completed not less than five years' continuous quasi-permanent service at the time of termination ;

(b) one month's pay for each completed year of his service, subject to a maximum of fifteen months' pay or fifteen thousand rupees, whichever is less, if he had completed not less than ten years continuous quasi-permanent service at the time of termination,

subject to the condition of service rendered by the government servant concerned being held by the authority competent to appoint him to be satisfactory." ;

(b) in sub-rule (2),—

(i) in clause (ii), for the words, "if the death takes place after completion of five years total continuous service or more", the words "if the death takes place after completion of five years but before completion of ten years total continuous service" shall be substituted ;

(ii) after clause (ii), the following shall be inserted, namely :—

'(iii) if the death takes place after completion of ten years of total continuous service or more, a gratuity equal to one month's pay for each completed year of continuous service subject to a maximum of fifteen months' pay or fifteen thousand rupees, whichever is less subject to the condition of service rendered by the government servant concerned being held by the authority competent to appoint him to be satisfactory." ;

"(iii) if the death takes place after completion of ing provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that where the service rendered by the government servant concerned is not held by the authority competent to appoint him to be satisfactory, such authority may, by order and for reasons to be mentioned therein, make such reduction in the amount of gratuity as it may consider proper :

Provided further that the amount of terminal gratuity payable under this rule shall not be less than the amount which the government servant would have got as a matching government contribution to the provident fund if he were a member of a Contributory Provident Fund Scheme from the date of his continuous temporary service subject to the condition that the matching contribution shall not in any case exceed 8-1/3 of his pay." ;

(c) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3) No gratuity shall be admissible under this rule to a government servant,—

(a) who resigns his post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure ;

(b) who is re-employed after retirement.

(4) Where a government servant is covered by rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, an amount equal to two months pay shall be recovered as a contribution out of the gratuity payable to the government servant.

(5) Where gratuity under this rule is paid to or in respect of a government servant who is not covered by rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, no other gratuity of pensionary benefits is payable."

(6) For the purpose of this rule—

(a) "quasi-permanent service" shall include two thirds of purely temporary service, if the total period of continuous service on the date of retirement, discharge, death or invalidment is not less than 5 years;

(b) "continuous service" means the total service including spells of quasi-permanent and temporary service."

Explanatory Memorandum to Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1975:

The recommendations of the Third Pay Commission regarding rates and conditions for the grant of terminal benefits for temporary and quasi-permanent employees in paras 63 to 65 of Chapter 60 of their Report, were accepted by Government vide Ministry of Finance, Department of Expenditure, Resolution No. 70(34)/73-I.C. dated the 1st November, 1973 and Resolution No. F. 11(35)/74-I.C. dated the 1st May, 1974. In the Resolution dated 1st November, 1973, it has been laid down that the Commission's recommendations relating to pay and retirement benefits shall be made effective from 1st January, 1973 instead of 1st March, 1973, as recommended by the Commission. Therefore, The CCS(TS) Amendment Rules, 1975, which have incorporated the recommendations of the Third Pay Commission regarding grant of retirement benefits to temporary and quasi-permanent employees are made effective from 1st January, 1973. This amendment will not adversely affect the rights of any person.

[No. 4/2/65-Ests.(C)]

S. KRISHNAN, Director.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का०आ० 4542.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी अफिसर को, उस सरकारी अफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 282/मेघा०/75, तारीख 8 फरवरी, 1975 में यथा अवधारित मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	रिटर्निंग अफिसर
1	2
1. शिलांग	उपायुक्त, खासी हिल्स, शिलांग।
2. तुरा	उपायुक्त, गारो हिल्स, तुरा।

[सं० 434/मेघा०/75]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4542.—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Meghalaya, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya as determined by the Delimitation Commission in its Notification No.282/MEG/75 dated the 8 February, 1975 and specified in column 1 of the said Table against such officer of Government:—

Table

S.l. No. and Name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Shillong	Deputy Commissioner, Khasi Hills, Shillong.
2. Tura	Deputy Commissioner, Garo Hills, Tura.

[No. 434/MEG/75]

का०आ० 4543.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी 2 में विनिर्दिष्ट मेघालय सरकार के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 282/मेघा०/75, तारीख 8 फरवरी, 1975 द्वारा यथा अवधारित मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिये नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. 1-शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अपर उपायुक्त, खासी हिल्स, शिलांग। 2. उपायुक्त, जैन्तिया हिल्स, जोवाई। 3. उपखण्ड आफिसर, नोंगस्टोइन। 4. प्रशासनिक आफिसर, रिभोइ यूनिट।
2. 2-तुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अपर उपायुक्त, गारो हिल्स, तुरा। 2. उपखण्ड आफिसर, सिम्सांगिरि, विलियम नगर

[सं० 434/मेघा०/75(1)]

S.O.4543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints each of the officers of Government of Meghalaya as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya as determined by the Delimitation Commission in its Notification No. 282/MEG/75, dated the 8 February, 1975 and specified in column 1 of the said Table against such officer or officers of Government, in the performance of the functions of such Returning Officer :—

Table

Returning Officer of Parliamentary Constituency.	Assistant Retunrning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1-Shillong Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner. Khasi Hills, Shillong. 2. Deputy Commissioner, Jaintia Hills, Jowai. 3. Sub-Divisional Officer, Nongstoin. 4. Administrative Officer, Ribhoi Unit.
2. Returning Officer of 2-Tura Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Garo Hills, Tura. 2. Sub-Divisionnal Officer, Simsanggiri, Williamanagar

[No. 434/MEG/75(1)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का०आ० 4544—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 74-बेहटा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्गा ग्राम पीतपुर, डाकखाना सहसापुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुर्गा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० /74/74(169)]

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 4544.—Whereas the Election Commission is satisfied that that Shri Durga, Village Peetpur, Post, Sahsapur, District Sitapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 74-Behta assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Comission hereby declares the said Shri Durga to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/74/74 (169)]

आदेश

का०आ० 4545.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 151-भिनगा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल हफीज खां, ग्राम व पोस्ट तकिया, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल हफीज खां को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० /151/74(170)]

ORDER

S.O. 4545.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Hafiz Khan, Vill. & P.O. Takiya, District Bahraich, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 151-Bhinga assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Hafiz Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/151/74 (170)]

आदेश

का०आ० 4546.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 153-इकौना (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोला, ग्राम सचौली, पोस्ट पयागपुर, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोला को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/153/74(171)]

ORDER

S.O. 4546.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhola, Village Sachauli, Post Payagpur, District Bahraich Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 153-Ikauna (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhola to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/153/74 (171)]

आदेश

का०आ० 4547.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 153-इकौना (अ०जा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शोभाराम, ग्राम व पोस्ट सेमगढ़ा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शोभा राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/153/74(172)]

ORDER

S.O. 4547.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shobha Ram, Village and Post Semgarha, District Bahraich Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 153-Ikauna (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shobha Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/153/74(172)]

आदेश

का०आ० 4548.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 156-बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदम्बा प्रसाद, बलूहा बलरामपुर, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगदम्बा प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्

के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र० वि०स०/156/74(173)]

ORDER

S.O. 4548.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdamba Prasad Baluha Balrampur, District Gonda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 156-Balrampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagramba Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/156/74 (173)]

आदेश

का० आ० 4549.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 156-बलरामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लौटन, ग्राम सिंह मोहानी, तहसील बलरामपुर, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लौटन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०वि० स०/156/74 (174)]

ORDER

S.O. 4549.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lautan, Village Singhmohini, Tehsil Balrampur District Gonda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 156-Balrampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lautan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/156/74 (174)]

आदेश

का०आ० 4550.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-उतरोला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सजन, ग्राम साहपुर इटई, पोस्ट चमरूपुर जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सजन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/157/74 (175)]

ORDER

S.O. 4550.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sajan, Vill. Sahpur Itace, Post Chamrupur Distt. Gonda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 157-Utraula Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sajan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/157/74 (175)]

आदेश

का०आ० 4551.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 160-मुजेहना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उत्तरी सिंह, ग्राम गुंगो देई, पोस्ट मेह नौन, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उत्तरी सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/160/74/176]

ORDER

S.O. 4551.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Uttari Singh, Vill. Goongidei, Post, Mehanam District Gonda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 160-Mujehna assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Uttari Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/160/74/176]

आदेश

का० आ० 4552.— यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 215 (सगड़ीमीर आ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भुक्खल, ग्राम इब्राहीमपुर, पोस्ट गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भुक्खल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/215/74 (173)]

ORDER

S.O. 4552.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhukkhal, Village Ibrahimpur, P.O. Gambhirpur, District Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 215-Saraimir (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhukkhal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/215/74 (177)]

आदेश

का० आ० 4553.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 237-धानापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री केदार नाथ, ग्राम कांधरपुर, पोस्ट खरान, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री केदार नाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र० वि०स०/237/74(179)]

ORDER

S.O. 4553.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kedar Nath, Village Kandharpur, P.O., Kharan, District Varanasi Uttar Pradesh, contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 237-Dhanapur assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kedar Nath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/237/74 (179)]

आदेश

का० आ० 4554.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 311-कमालगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुल्तान अहमद, गांधी वार्ड, कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है,

और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुल्तान अहमद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प०-वि० स०/311/74(180)]

ORDER

S.O. 4554.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sultan Ahmad, Gandhi Ward, Kamalganj District Bulandshahr Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 311-Kamalganj assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sultan Ahmad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/311/74(180)]

आदेश

दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

का०आ० 4555.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 290-कानपुर कैंटोनमेन्ट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनोद कुमार निषाद, 29 गोलाघाट जिला कानपुर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विनोद कुमार निषाद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/290/74(181)]

ORDER

New Delhi, the 17th September, 1975

S.O. 4555.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vinod Kumar Nishad, 29 Gola Ghat, District Kanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 290-Kanpur Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vinod Kumar Nishad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/290/74 (181)]

आदेश

का०आ० 4556—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 175-खेसरहा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लाल विजय सिंह, ग्राम किठरी, पोस्ट भगौसा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल विजय सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/175/74(182)]

ORDER

S.O. 4556.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Vijai Singh, Village Kithri, Post Bhagausa, District Basti, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 175-Khesraha assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Vijai Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/175/74 (182)]

आदेश

का०आ० 4557.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 167-नगर पूरब(अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रूपिया प्रसाद, ग्राम गौसपुर, पोस्ट गाय घाट, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए

नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री करिया प्रसाद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/167/74(183)]

ORDER

S.O. 4557.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karya Prasad, Village Gauspur, Post Gaighat District Basti, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 167-Nagar East (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ,

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karya Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/167/74 (183)]

आदेश

का०आ० 4558.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130–अकबर पुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जीतू, ग्राम रावीपुर बहा उद्दीन पुर, पोस्ट अकबर पुर, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जीतू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि स०/130/74(181)]

ORDER

S.O. 4558.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jeetoo, Village Ravipur Bahauddinpur, P.O. Akbarpur, District Faizabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 130-Akbarpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ,

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jeetoo to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/130/74 (184)]

आदेश

का०आ० 4559.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 165-हर्रैया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जैसराज, ग्राम व डाकखाना बरदिया कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जैसराज को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/165/74(185)]

ORDER

S.O.4559.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaisraj, Village & Post Bardiya Kunwar, District Basti, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 165-Harraiya assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaisraj to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/165/74 (185)]

आदेश

का०आ० 4560.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 165—हर्रैया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती मालती, ग्राम व डाकखाना परसरामपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती मालती को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/165/74 (186)]

ORDER

S.O. 4560.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Malti, Village & P.O. Parasrampur, District Basti, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 165-Haraiya assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People, Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Malti, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/165/74 (186)]

आदेश

का०आ० 4561.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 165—हर्रैया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव पूजन, ग्राम बेलवा, डाकखाना जाजपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव पूजन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/165/71 (187)]

ORDER

S.O. 4561.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheopujan, Village Belwa, Post Jajoopur, District Basti Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 165-Harraiya assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheopujan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/165/74 (187)]

आदेश

का० आ० 4562—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 166-कप्तानगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राज किशोर ग्राम व पोस्ट अमरौली शुमाली, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राज किशोर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/166/71 (188)]

ORDER

S.O. 4562.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raj Kishor, Village & Post Amrauli Shumali, District Basti, Uttar Pradesh, a contestig candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 166-Captainganj assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and

the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raj Kishor to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/166/74(188)]

आदेश

का०आ० 4563.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 189-फरेन्दा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कमलेश्वर, ग्राम व पोस्ट बजरहा सोन बरसा बाया नूजमन गंज, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कमलेश्वर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य के चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/189/74 (189)]

ए० एन० सैन, सचिव ।

ORDER

S.O. 4563.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamleshwar, Village & Post Banjarha Sonbarsa via Brijamanaganj, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 189-Pharenda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Comission hereby declares the said **Shri Kamleshwar to be disqualified for being chosen as** and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/189/74(189]

आदेश

का०आ० 4564.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 171-इटवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जिकरी, ग्राम परसा, पोस्ट इटवा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जिकरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/171/74 (190)]

ORDER

S.O. 4564.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Zikri, Vill. Parsa, Post Itwa, District Basti, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 171-Itwa, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Comission hereby declares the said Shri Zikri to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/171/74 (190)]

आदेश

का०आ० 4565.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए असम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 167-डिब्रुगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निवारन चन्द्र बोरा, पत्रालय मोहनाघाट डिब्रुगढ़ (असम) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनायें दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री निवारन चन्द्र बोरा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० असम-वि०स०/117/72]

ORDER

S.O. 4565.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Nibaran Chandra Bora, P.O. Mohanaghat, Dibugarh, District Dibrugarh (Assam) a contesting candidate for election to the Assam Legislative Assembly from 117-Dibrugarh constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nibaran Chandra Bora to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/LA/117/72]

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

का०आ० 4566.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 180-धुरियापार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मसी उद्दीन, ग्राम बिरुई खुर्द, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मसी उद्दीन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०—वि० स०/180/71(191)]

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1975

S.O. 4566.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Masiuddin, Village Birui Khurd, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 180-Dhuriapar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Masiuddin to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/180/74(191)]

आदेश

का०आ० 4567.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 180-धुरियापार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्यामाचरण, ग्राम झउआ खुर्द, डा० औजी बाजार, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्यामाचरण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/180/74 (192)]

ORDER

S.O. 4567.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyamacharan, Village Jhawa Khurd, Post Auji Bazar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 180-Dhuriapar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyamcharan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/180/74(192)]

आदेश

का०आ० 4568.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 180-धुरियापार निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव पति, ग्राम बेलाव उर्फ शाहपुर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव पति को संसद के किसी भी सदन के

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/180/74 (193)]

ORDER

S.O. 4568.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheopati, Village Belaon urf Shahpur, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 180-Dhuriapar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made there under;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheopati to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

3. Now, therefore, in pursuance of section 10O of the said

[No. UP-LA/180/74(193)]

आदेश

का०आ० 4569.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 184-पिपराइच निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम आसरे, ग्राम दहला, डा० धोहारिया, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम आसरे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/184/74 (194)]

ORDER

S.O. 4569.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Asrey, Vill. Dahala, P.O. Doharia, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 184-Pipraich assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Asrey to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/184/74(194)]

आदेश

का०आ० 4570.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 193-श्याम देउरवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनजान ग्राम व डाकखाना श्याम देउरवा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनजान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/193/74 (195)]

ORDER

S.O. 4570.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anjan, Village & Post Shyamdeurwa, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 193-Shyamdeurwa assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anjan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/193/74(195)]

आदेश

का० आ० 4571.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 193-श्याम देउरवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अर्ण राज, गांव पौहरिया, डाकखाना धुसकली, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं

दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास उस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/193/74 (196)]

ORDER

S.O. 4571.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Banshraj, Village Pauharia, Post Ghughuli, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 193-Shyam Deurwa assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Banshraj to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/193/74(196)]

आदेश

का० आ० 4572.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 193-श्याम देउरवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम स्वार्थ, गांव व डाकघर हसुपुर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम स्वार्थ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि लिए निरर्हित घोषित करती है ।

[सं० उ०प्र० वि० स०/193/74(197)]

ORDER

S.O. 4572.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Swarath, Village & Post Hansupur, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P Legislative Assembly from 193-Shyam Deurwa assembly consituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Swarath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/193/74(197)]

आदेश

का० आ० 4573.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 194-नौरंगिया (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लाल चन्द, राजा बाजार, खड्डा, पोस्ट खड्डा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई भी कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल चन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/194/74(198)]

ORDER

S.O. 4573.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Chand, Raja Bazar Khadda, Post Khadda, Distt. Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 194-Naurangia (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/194/74(198)]

आदेश

का० आ० 4574.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन

के लिए 318-तिन्दवारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरिमर्दन सिंह, ग्राम व पोस्ट दुरेन्डी, जिला बांदा उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अरिमर्दन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/318/74(199)]

ORDER

S.O. 4574.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arimardan Singh, Village and Post Durendi, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 318 Tindwari assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arimardan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/318/74(199)]

आदेश

का. आ. 4575.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 318-तिंदवारी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री स्वामी कमलाश्रम, ग्राम इण्डी क्षेत्र, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री स्वामी कमलाश्रम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ.प्र.-वि.स./318/74(200)]

ORDER

S.O. 4575.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Swamy Kamlashram, Village Dandi Kshetra, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 318-Tindwari, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Swamy Kamlashram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament or of the Legislative Assembly or legislative Council of a State for a period of three years from the date this order.

[No. UP-LA/318/74 (200)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का० आ० 4576 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 245-कोलसला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरजा शंकर, ग्राम व पोस्ट मरुई, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गिरजा शंकर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/245/74 (201)]

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 4576.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girja Shankar, Village & Post Marui, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 245-Kolasla assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri

Girja Shankar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/245/74(201)]

आदेश

का०आ० 4577.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 240—मुगलसराय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर नाथ, ग्राम गोधना, पोस्ट मुगलसराय, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर नाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०—वि०स०/240/74 (202)]

ORDER

S.O. 4577.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Nath, Village Godhana, P.O. Moghalsarai, District Varanasi Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 240-Moghal sarai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Nath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/240/74(202)]

आदेश

का०आ० 4578.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 240—मुगलसराय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उदय नारायन, ग्राम मुगलचक, पोस्ट मुगलसराय, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उदय नारायन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०—वि०स०/240/74 (203)]

ORDER

S.O. 4578.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Udai Narain Village Mughal Chak, P.O. Moghalsarai District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 240-Moghalsarai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Udai Narain to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/240/74(203)]

आदेश

का. आ. 4579.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 246-गंगापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नन्दा, ग्राम बरेमा पो. आ. रामेश्वर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नन्दा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ.प्र.-वि.स./246/74(204]

ORDER

S.O. 4579.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nanda, Village Barema, P.O. Rameshwar, Distt. Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the

U.P. Legislative Assembly from 246-Gangapur assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the, said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said, Shri Nanda to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/246/74 (204)]

आदेश

का. आ. 4580.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 246-गंगापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री परमानन्द ग्राम धानापुर, पोस्ट जखानी जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री परमानन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ.प्र.-वि.स./246/74(205)]

ORDER

S.O. 4580:—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Perma Nand, Village Dhanapur, P.O. Jakhani District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election of the U.P. Legislative Assembly from 246-Gangapur, assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Perma Nand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/246/74(205)]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का०आ० 4581.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से अवकाश पर गये श्री डी० बालगोपालन के स्थान पर श्री टी० वेंकटस्वामी, अतिरिक्त सचिव, विधि तथा संसदीय कार्य विभाग को 8 अक्तूबर, 1975 से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं० 154/कर्नाटक/75]

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 4581.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Karnataka, hereby nominates Shri T. Venkataswamy, Additional Secretary, Department of Law and Parliamentary Affairs, as the Chief Electoral Officer for the State of Karnataka with effect from 8 October, 1975 vice Shri D. Balagopalan, granted leave.

[No. 154/Karnataka/75]

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4582.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 286-बिन्दकी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोला राम उर्फ बिनगैता, ग्राम सराय महमूदपुर, पो० आफिस, खजुहा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोला राम उर्फ बिनगैता को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/286/74 (217)]

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1975

S.O. 4582.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhola Ram alias Bingaita, Village Sarai Mahamoodpur, P.O. Khajuha, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 286-Bindki assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhola Ram alias Bingaita to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/286/74(217)]

आदेश

का०आ० 4583.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 267-मेजा (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम लाल, ग्राम तरांव, पत्रालय कोरांव, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/267/74 (216)]

ORDER

S.O. 4583.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Lal, Village Taraon, Post Koraon Meja, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 267-Meja (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/267/74(216)]

आदेश

का०आ० 4584.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 274-नवाबगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जंगबहादुर सिंह पटेल, 19 राजापुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जंगबहादुर सिंह पटेल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/274/74 (218)]

ORDER

S.O. 4584.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jang Bahadur Singh Patel, 19-Rajapur, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 274-Nawabganj assembly constituency, has faild to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jang Bahadur Singh Patel to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/274/74(218)]

आदेश

का०आ० 4585.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 274-नवाबगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजाराम पुत्र श्री कल्लू, दहियावां, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजाराम पुत्र श्री कल्लू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/274/74 (219)]

ORDER

S.O. 4585.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raja Ram, son of Shri Kalloo, Dahiyawan, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 274-Nawabganj assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raja Ram son of Kalloo to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/274/74(219)]

आदेश

का०आ० 4586.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 274—नवाबगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सीताराम भगत, 84 फतुहपुर, उपरहार, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सीताराम भगत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/274/74 (220)]

ORDER

S.O. 4586.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sita Ram Bhagat, 84-Fatuhpur Uparhar, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 274-Nawabganj assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sita Ram Bhagat to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/274/74(220)]

आदेश

का० आ० 4587.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 248-ग्यानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम दुलार, विद्यार्थी, ग्राम भगवानपुर, पो० आ० बड़ा गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम दुलार विद्यार्थी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/248/74(209)]

ORDER

S.O. 4587.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Dular Vidyarthi, Village Bhagwanpur, P.O. Baragaon, District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 248-Gyanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Dular Vidyarthi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/248/74(209)]

आदेश

का० आ० 4588.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249-भदोही (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विजई, ग्राम अहमदपुर फुलवरिया, पो० कुरौठा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विजई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/249/74(210)]

ORDER

S.O. 4588.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vijai Village Ahmadpur, Phulwariya, P.O. Kurautha District Varanasi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 249-Bhadohi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representa-

tion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vijai to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/249/74(210)]

आदेश

का० आ० 4589.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 252-केराकत (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महन्थ राम, ग्राम पोस्ट कुसरना, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महन्थ राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/252/74(211)]

ORDER

S.O. 4589.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahanth Ram, Village, Post Kusarna, District Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 252-Kerakat (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahanth Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/252/74(211)]

आदेश

का० आ० 4590.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 252-केराकत(अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बल्लर, ग्राम सराय बीरु, पत्रालय केराकत, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बल्लर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/252/74(212)]

ORDER

S.O. 4590.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ballar, Village Saraibiru, P.O. Kerakat District Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 252-Kerakat (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And wehreas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ballar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/252/74(212)]

आदेश

का० आ० 4591.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश, विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 253-बयालसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमरनाथ सिंह, ग्राम व पोस्ट बेहड़ा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा उपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर नाथ सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/253/74(213)]

ORDER

S.O. 4591.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Nath Singh, Village, Post Behdu, District Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 253-Beyalsi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Nath Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/253/74(213)]

आदेश

का० आ० 4592.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 253-बयालसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरधारी, ग्राम नैपुरा, पत्रालय मुफतीगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गिरधारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 253/74(214)]

ORDER

S.O. 4592.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girdhari, Village Naipura, P.O. Mufaganj District Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 253-Beyalsi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girdhari to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/253/74(214)]

आदेश

का० आ० 4593—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 259-मछलीशहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम लला, ग्राम सरावां, पो० आ० पवारा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी, लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम लला, को संसद के किसी भी सदन के किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख के से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/259/74(215)]

ORDER

S.O. 4593.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Lala, Village Serawan, P.O. Powara, District Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 259-Machhlishahr assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Lala to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/259/74(215)]

आदेश

का० आ० 4594.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 280-सिराथू निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अशोक कुमार, ग्राम तथा डाकघर उदहिन बुजुर्ग तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अशोक कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/280/74(223)]

ORDER

S.O. 4594.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ashok Kumar, Village and Post Udahin Buzurg, Tehsil Serathu, Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 280-Sirathu assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ashok Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/280/74(223)]

आदेश

का० आ० 4595.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश, विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 283-हसवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सालिक राम, ग्राम हासिमपुर, भेदपुर, पत्रालय हसवा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सालिक राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/283/74/(224)]

ORDER

S.O. 4595.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Salik Ram, Village Hasimpur Bhedpur, P.O. Haswa, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 283-Haswa assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Salik Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/283/74(224)]

आदेश

का० आ० 4596.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 283-हसवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुभाष चन्द्र सिंह, ग्राम व पोस्ट गाजीपुर जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुभाष चन्द्र सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/283/74/(225)]

ORDER

S.O. 4596.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Subhash Chandra Singh, Village and P.O. Ghazipur, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 283-Haswa assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Subhash Chandra Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/283/74(225)]

आदेश

का० आ० 4597.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 284 फतेहपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री आगेश्वर, ग्राम केवई, पोस्ट ढकौली जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये पर्याप्त कोई कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जागेश्वर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/284/74/(226)]

ORDER

S.O. 4597.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Jageshwar, Village Kewai, Post Dhakauli, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 284-Fatehpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jageshwar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/284/74(226)]

आदेश

का० आ० 4598.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 284-फतेहपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम आसरे कल्पनाधीश, मोहल्ला अमरजई, पो० आ० जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम आसरे कल्पनाधीश को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 284/74/(227)]

ORDER

S.O. 4598.—Whereas the Election Commision is satisfied that Shri Ram Ashrey Kalpanadhish, Mohalla Amar Jai, Post and Distt. Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 284-Fatehpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Ashrey Kalpanadhish to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/284/74(227)]

आदेश

का० आ० 4599.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1971 में हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 304-इटावा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार, 18/1 आलमपुर, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कृष्ण कुमार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/304/74(231)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव

ORDER

S.O. 4599.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Krishna Kumar, 18/1 Alampur, Etawa Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 304-Etawa assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Krishna Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/304/74(231)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

का० आ० 4600.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग दिल्ली प्रशासन के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन के आफिसर को, ऐसे आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अपने आदेश सं० 40, तारीख 28 अप्रैल, 1975 द्वारा यथा अवधारित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1 नई दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नई दिल्ली) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
2. दक्षिण दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
3. बाह्य दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
4. पूर्व दिल्ली	अपर जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
5. चांदनी चौक	अपर जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
6. दिल्ली सदर	अपर जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
7. करोलबाग (अ०जा०)	अपर जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।

[सं० 434/दिल्ली/75]

New Delhi, the 26th September, 1975

S.O. 4600.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby designates, in consultation with the Delhi Administration, the officer of the Administration specified in column 2 of the Table below as the Returning officer of the Parliamentary constituencies in the Union Territory of Delhi, as determined by the Delimitation Commission in its order No. 40 dated the 28th April, 1975 and as specified in column 1 of the said Table against such officer of Administration :—

Table

Serial No. and name of the parliamentary constituency.	Returning officer
1	2
1. New Delhi	Additional District Magistrate (New Delhi) New Courts, Delhi.
2. South Delhi	Additional District Magistrate (South) New Courts, Delhi.
3. Outer Delhi	Additional District Magistrate (Revenue) New Courts, Delhi
4. East Delhi	Additional District Magistrate (East) New Courts, Delhi.
5. Chandni Chowk	Additional District Magistrat e (Central) New Courts, Delhi
6. Delhi Sadar	Additional District Magistrate (North) New courts, Delhi.
7. Karol Bagh (SC)	Additional District Magistrate (Central) New Courts, Delhi.

[No. 434/DL./75]

का० आ० 4601.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन के आफिसरों को, ऐसे आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट परिसीमन आयोग द्वारा अपने आदेश सं० 40, तारीख 28 अप्रैल, 1975 द्वारा यथा अवधारित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (पार्लियामेन्ट स्ट्रीट), 68 अशोक मार्ग, नई दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (चाणक्यपुरी), 68 अशोक मार्ग, नई दिल्ली ।
2. दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (केन्ट०) पार्लियामेन्ट स्ट्रीट कोर्ट्स, नई दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (लाजपत नगर) पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, कोर्ट्स, नई दिल्ली ।
3. बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) न्यू कोर्ट्स, नई दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (कमला मार्केट) न्यू कोर्ट्स, नई दिल्ली ।
4 पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (शाहदरा), शाहदरा कोर्ट्स, दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (किंग्जवे कैम्प) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
5. चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (कोतवाली) न्यू-कोर्ट्स, दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (दरियागंज) न्यू-कोर्ट्स, दिल्ली ।
6. दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रीटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (सदर बाजार) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली । 2. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (सब्जी मण्डी) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।
7. करोलबाग (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उप खण्ड मजिस्ट्रेट (पटेल नगर) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली । 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट (ओरिजिनल रोड) न्यू कोर्ट्स, दिल्ली ।

[स० 434/दिल्ली/75-(1)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 4601.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the officers of Delhi Administration, as specified in column 2 of the Table below to assist the returning officer of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, as determined by the Delimitation Commission in its order No. 40 dated the 28 April, 1975 and as specified in column 1 of the said Table against such officers of Administration in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
Returning Officer of 1-New Delhi Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate (Parliament) Street), 68-Ashoka Road, New Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Chanakya Puri). 68-Ashoka Road, New Delhi.
Returning Officer of 2-South Delhi Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate (Cantt.) Parliament Street Courts, New Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Lajpat Nagar) Parliament Street Courts, New Delhi.
Returning Officer of 3-Outer Delhi Parliamentary Constituency.	Sub-Divisional Magistrate (Panjabi Bagh), New Courts, Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Kamla Market) New Courts, Delhi.
Returning Officer of 4-East Delhi Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate Shahdara) Shahdara Courts, Delhi.
Returning Officer of 5-Chandni Chowk Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate (Kotwali) New Courts, Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Daryaganj) New Courts, Delhi.
Returning Officer of 6-Delhi Sadar Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate (Sadar Bazar) New Courts, Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Sabzimandi) New Courts, Delhi.
Returning Officer of 7-Karol Bagh (SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate (Patel Nagar) New Courts, Delhi. 2. Sub-Divisional Magistrate (Original Road) New Courts, Delhi.

[No. 434/DL/75-(1)]
By Order,
V. NAGASUBRAMANIAN. Secy.

New Delhi, the 30th September, 1975

ERRATUM

S.O. 4602.—In the Commission's notification No. 82/TN/1-2/74, dated 13th December, 1974 published as S.O. 3386 at pages 3682—3696 of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) No, 52, dated the 28th December, 1974 the words and figures "New Delhi, the 13th December, 1974" shall be inserted at the beginning and for the words "Under Secretary", appearing at the end of the said notification, read "Secretary to the Election Commission of India".

[No. 82/TN/1-2/74]
I. K. K. MENON, Under Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर 1975

का० आ० 4603—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं० आर 15/1/सी० और पी० एफ०/पर्से, तारीख 31 मार्च, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश की अनुसूची में, "भाग 2, साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3" और "भाग 3—साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3"

क्रम सं०	पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शक्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 में की मद संख्याओं के प्रतिनिर्देश से)		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल:				
1.	महानिदेशालय सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	उपनिदेशक (प्रशासन)	उपनिदेशक (प्रशासन)	सभी	महानिदेशक
2.	पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस) जो पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	(1) उपमहानिरीक्षक पुलिस (जो महानिरीक्षक पुलिस द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) (2) पुलिस महानिरीक्षक का ज्येष्ठ स्टाफ अफसर ।	(1) से (4)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)
3.	उपमहानिरीक्षक (पुलिस) का कार्यालय सभी पद (अनुसचिवीय राजपत्रित)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	सभी	सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक
4.	कमांडेंट ग्रुप सेंटर का कार्यालय सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	(1) रेंज उपमहानिरीक्षक (पुलिस) (2) कमाण्डेंट	सभी (1) से (4)	सैक्टर महानिरीक्षक (पुलिस) रेंज उपमहानिरीक्षक (पुलिस)

1	2	3	4	5	6
5. बटालियन कमाण्डेंट का कार्यालय					
सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	रेंज उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	(1) रेंज उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	सभी	सैक्टर (पुलिस) महानिरीक्षक	
		(2) कमाण्डेंट	(1) से (4)	रेंज उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	
6. सिगनल ग्रुप सैंटर कमाण्डेंट का कार्यालय					
सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	बेतार सलाहकार	(1) बेतार सलाहकार	सभी	सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक	
		(2) कमाण्डेंट	(1) से (4)	बेतार सलाहकार	
7. सिगनल बटालियन के कमाण्डेंट का कार्यालय					
सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	बेतार सलाहकार	(1) बेतार सलाहकार	सभी	सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक	
		(2) कमाण्डेंट	(1) से (4)	बेतार सलाहकार	
8. केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय/रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य का कार्यालय					
सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	उपनिदेशक (प्रशिक्षण)	(1) उपनिदेशक (प्रशिक्षण)	सभी	सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक	
				उपनिदेशक (प्रशिक्षण)	
		(2) प्रधानाचार्य	(1) से (4)		
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेस अस्पताल का कार्यालय					
सभी पद (अनुसचिवीय अराजपत्रित)	रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	(1) रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	सभी	सैक्टर पुलिस महानिरीक्षक	
		(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	(1) से (4)	रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	
10. सभी वर्ग 3 के अस्पताल कर्मचारिवृन्द	(1) बेस अस्पताल के कर्मचारिवृन्द की बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी	(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सभी	रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	
		(2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	(1) से (4)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
	(2) बटालियन/ग्रुप सैंटर के कर्मचारिवृन्द की बाबत कमाण्डेंट	(1) कमाण्डेंट	सभी	रेंज उप महानिरीक्षक (पुलिस)	
		(2) सहायक कमाण्डेंट	(1) से (4)	कमाण्डेंट	
	(3) रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की बाबत प्रधानाचार्य	(1) प्रधानाचार्य	सभी	उपनिदेशक (प्रशिक्षण)	
		(2) उपप्रधानाचार्य	(1) से (4)	प्रधानाचार्य	
	(4) सिगनल बटालियन ग्रुप सैंटर के कर्मचारिवृन्द की बाबत कमाण्डेंट	(1) कमाण्डेंट	सभी	बेतार सलाहकार	
		(2) सहायक कमाण्डेंट	(1) से (4)	कमाण्डेंट	

भाग 3—साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4

क्रम संख्या	पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 में की मद संख्याओं के प्रतिनिर्देश से)		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5	6
1.	महानिदेशालय सभी वर्ग 4 पद (जिसमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)	संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)	सभी	उपनिदेशक (प्रशासन)
2.	पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय				
	सभी वर्ग 4 पद (जिसमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	पुलिस महानिरीक्षक का स्टाफ अफसर	पुलिस महानिरीक्षक का स्टाफ अफसर	सभी	पुलिस महानिरीक्षक का ज्येष्ठ स्टाफ अफसर

1	2	3	4	5	6
3.	उप महानिरीक्षक (पुलिस) का कार्यालय				
	सभी वर्ग 4 पद (जिसमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	सभी	सैक्टर पुलिस महा निरीक्षक
4.	ग्रुप सैंटर कमाण्डेंट का कार्यालय				
	सभी वर्ग 4 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	सहायक कमाण्डेंट	सहायक कमाण्डेंट	सभी	कमाण्डेंट
5.	बटालियन कमाण्डेंट का कार्यालय				
	सभी वर्ग 1 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	सहायक कमाण्डेंट	सहायक कमाण्डेंट	सभी	कमाण्डेंट
6.	सिगनल ग्रुप सैंटर कमाण्डेंट का कार्यालय				
	सभी वर्ग 1 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	सहायक कमाण्डेंट	सहायक कमाण्डेंट	सभी	कमाण्डेंट
7.	सिगनल बटालियन कमाण्डेंट का कार्यालय				
	सभी वर्ग 1 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	सहायक कमाण्डेंट	सहायक कमाण्डेंट	सभी	कमाण्डेंट
8.	संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का कार्यालय				
	सभी वर्ग 4 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	उपप्रधानाचार्य	उपप्रधानाचार्य	सभी	प्रधानाचार्य
9.	ग्रेम अस्पताल				
	सभी वर्ग 4 पद (जिनमें अस्पताल का कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है)	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सभी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

[सं० आर 15/1/सी० आर० टी० एफ०/पर्स 1]

टी० के० रामकृष्णन, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1975

S. O. 4503.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of rule 24, read with rule 34, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the President hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. R. 15/1/CRPF/Pers. I, dated the 31st day of May, 1975, namely:—

In the Schedule to the said order, for "Part II-General Central Service Class III" and "Part III-General Central Servic Class IV" the following shall be substituted, namely :—

"PART II-GENERAL CENTRAL SERVICE CLASS III"

Sl. No.	Description of post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate authority
			Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
Central Reserve Police Force :					
1.	Directorate General				
	All posts (Ministerial non-gazetted)	Deputy Director (Administration)	Deputy Director (Administration)	All	Director General
2.	Office of the Inspector General of Police.				
	All post (Ministerial non-gazetted).	Deputy Inspector General of Police (to be nominated by Inspector General of Police).	(i) Deputy Inspector General of Police (to be nominated by Inspector General of Police)	All	Inspector General of Police.
			(ii) Senior Staff Officer to the Inspector General of Police.	(i) to (iv)	Deputy Inspector General of Police.

1	2	3	4	5	
3.	Office of the Deputy Inspector General of Police.				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Deputy Inspector General of Police.	Deputy Inspector General of Police.	All	Sector Insector General of Police.
4.	Office of the Commandant Group Centre.				
	All posts (Ministrerial non-Gazetted).	Range Deputy Inspector General of Police.	(i) Range Deputy Inspector General of Police.	All	Sector Inspector General of Police.
			(ii) Commandant	(i) to (iv)	Range Deputy Inspector General of Police.
5.	Office of the Battalion Commandant.				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Range Deputy Inspector General of Police.	(i) Range Deputy Inspector General of Police.	All	Sector Inspector General of Police.
			(ii) Commandant	(i) to (iv)	Range Deputy Inspector General of Police.
6.	Office of Commandant Signal Group Centre.				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Wireless Adviser	(i) Wireless Adviser	All	Sector Inspector General of Police.
			(ii) Commandant	(i) to (iv)	Wireless Adviser.
7.	Office of Commandant Signal Battalion.				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Wireless Adviser	(i) Wireless Adviser	All	Sector Inspector General of Police
			(ii) Commandant	(i) to (iv)	Wireless Adviser.
8.	Office of the Principal Central Training College/Recruits Training Centre.				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Deputy Director (Training)	(i) Deputy Director (Training)	All	Sector Inspector General of Police.
			(ii) Principal	(i) to (iv)	Deputy Director (Training)
9.	Office of the Chief Medical Officer Base Hospital				
	All posts (Ministerial non-gazetted).	Range Deputy Inspector General of Police.	(i) Range Deputy Inspector General of Police.	All	Sector Inspector General of Police.
			(ii) Chief Medical Officer.	(i) to (iv)	Range Deputy Inspector General of Police.
10.	All Class III Hospital Staff.	(i) Chief Medical Officer in respect of Staff of Base Hospital.	(i) Chief Medical Officer.	All	Range Deputy Inspector General of Police.
			(ii) Senior Medical Officer.	(i) to (iv)	Chief Medical Officer.
		(ii) Commandant in respect of staff of Battalion/Group Centre.	(i) Commandant	All	Range Deputy Inspector General of Police.
			(ii) Assistant Commandant.	(i) to (iv)	Commandant.
		(iii) Principal in respect of staff of Recruits Training Centre/Central Training College.	(i) Principal	All	Deputy Director (Training).
			(ii) Vice Principal.	(i) to (iv)	Principal.
		(iv) Commandant in respect of staff of Signal/Battalion Group Centre.	(i) Commandant	All	Wireless Adviser.
			(ii) Assistant Commandant.	(i) to (iv)	Commandant.

PART III—GENERAL CENTRAL SERVICE CLASS IV

Sl. No.	Description of post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11).		Appellate authority
			Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
1.	Directorate General.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Joint Assistant Director (Administration)	Joint Assistant Director (Administration)	All	Deputy Director (Administration)
2.	Office of the Inspector General of Police.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Staff Officer to the Inspector General of Police.	Staff Officer to the Inspector General of Police.	All	Senior Staff Officer to the Inspector General of Police
3.	Office of the Deputy Inspector General of Police.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Deputy Inspector General of Police.	Deputy Inspector General of Police.	All	Sector Inspector General of Police.
4.	Office of the Commandant Group Centre.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Assistant Commandant	Assistant Commandant	All	Commandant
5.	Office of the Battalion Commandant.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Assisttant Commandant	Assistant Commandant	All	Commandant
6.	Office of Commandant Signal Group Centre.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Assistant Commandant	Assistant Commandant	All	Commandant
7.	Office of the Commandant Signal Battalion.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Assistant Commandant	Assistant Commandant	All	Commandant
8.	Office of the Principal Recruit Training Centre/Central Training College.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Vice Principal.	Vice Principal.	All	Principal
9.	Base Hospital.				
	All Class IV posts (including Hospital staff).	Senior Medical Officer.	Senior Medical Officer.	All	Chief Medical Officer.

[No. R/15/1/CRPF/Pers I]

T.K. RAMAKRISHNAN, Director.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th September, 1975

S.O. 4604.—In English notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 1844 dated the 20th May, 1975, published on pages 2141-2143 of the Gazette of India, Part II-Section 3 Sub-section (ii) dated the 21st June, 1975, the following shall be inserted in sub-paragraph (2) of paragraph (1) :—

"They shall come into force on the 7th day of April, 1975".

[No. F. 1/3/73-Coin]

S. L. DUTT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1975

स्टाम्प

का. आ. 4605.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस शुल्क से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले आठ करोड़, बत्तीस लाख रुपये मूल्य के डिबेंचरों या वचन-पत्रों के रूप में बंधपत्रों और ऐसे दस्तावेजों पर, जो उसके पश्चातवर्ती हस्तांतरण के साक्ष्य स्वरूप हैं, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य हैं, छूट देती है।

[सं. 43/75/स्टाम्प—फा. सं. 471/42/सीमाशुल्क]

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1975

STAMPS

S.O. 4605.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures or promissory notes of the value of eight crores and thirty-two lakhs of rupees, to be issued by the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi and the documents evidencing subsequent transfer of the same, are chargeable under the said Act.

[No. 43/75-Stamps/F. No. 471/42/75-Cus. VII]

आदेश

का. आ. 4606.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एमलगमेटेड इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई को उसके द्वारा जारी किए गए पाँचालिस हजार, चार सौ चौंसठ रुपए अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बंधपत्रों पर और एक हजार एक रुपए के चौंसठ अप्रतिभूत बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क मद्धे प्रभार्य तैंतीस हजार, तीन सौ अड़तालीस रुपए मात्र समेकित स्टाम्प शुल्क के संदाय की अनुमति देती है।

[सं. 44/75 स्टाम्प—फा. सं. 471/75/सी. शु-2]

डी. के. आचार्य, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4606.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Amalgamated Electric Company Limited, Bombay, to pay consolidated stamp duty of thirty-three thousand, three hundred and forty-eight rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of forty-four thousand, four hundred and sixty-four Unsecured Bonds of rupees one thousand and one each issued by the said M/s. Amalgamated Electric Company Limited, Bombay.

[No. 44/75-Stamps—F. No. 471/75-Cus. VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4607.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 9 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

1. श्री दिलीप मुखर्जी	अध्यक्ष
2. श्री सी० आर० बिस्वास, अवर सचिव, बैंकिंग विभाग, नयी दिल्ली ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
3. श्री एच० एन० भौमिक, उप निदेशक (सरकार) उद्योग तथा सिविल आपूर्ति मंत्रालय, नयी दिल्ली	
4. श्री बी० के० दासगुप्त, सहायक मुख्याधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ।	
5. श्री पन्नालाल दासगुप्त, सदस्य, पश्चिम बंगाल राज्य आयोजन मण्डल	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
6. श्री एम० भट्टाचार्य, आयुक्त, जलपाईगुड़ी प्रभाग ।	
7. श्री एम० दासगुप्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, बरहमपुर	प्रायोजक बैंक द्वारा मनोनीत
8. श्री टी० आर० शाह, सहायक महाप्रबन्धक, (विकास) यूबीआई, कलकत्ता	
9. श्री मागर घोष, पातीराम, दक्षिण दीनाजपुर	

[सं० एफ० 4-11/75-ए० सी०-II]

(Department of Banking)

New Delhi, the 2nd October, 1975

S.O. 4607.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Board of directors of the Gaur Gramin Bank Malda shall consist of the following members, namely :—

1. Shri Dilip Mukherjee	Chairman
2. Shri C. R. Biswas, Under Secy., Deptt. of Banking, New Delhi. 3. Shri H. N. Bhowmik, Dy. Director (Cooperation), Min. of Industry & Civil Supplies, New Delhi. 4. Shri B. K. Das Gupta, Asstt. Chief Officer, Reserve Bank of India, Calcutta.	Nominees of the Central Government
5. Shri Pannalal Das Gupta, Member, West Bengal State lanning Board. 6. Shri M. Bhattacharya (Commissioner, Jalpaiguri Division	Nominees of the State Government.
7. Shri S. Das Gupta, Regional Manager, United Bank of India, Berhampur. 8. Shri T.R. Shah, Asstt. General Manager (Development) UBI, Calcutta. 9. Shri Sagar Ghosh, Patiram, West Dinajpur.	Nominees of the Sponsor Bank.

[No. F. 4-11/75-AC-II]

S.O. 4608.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Board of directors of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani shall consist of the following members, namely :—

1. Shri S.P. Mehra	Chairman.
2. Shri Prem Kumar, Under Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi. 3. Shri R.L. Nagpal, Dy. Director (Cooperation), Ministry of Industry & Civil Supplies, New Delhi. 4. Shri S.V. Bhave, Asstt. Chief Officer, Reserve Bank of India, New Delhi.	Nominees of Central Government.
5 Shri Daya Nand, Advocate, Charkhi Dadri, Haryana. 6. Shri A.C. Sharma, Jt. Director, Agriculture Deptt., Govt. of Haryana, Chandigarh. 7. Shri K.N. Taimani, Manager, Priority Sector & Lead Bank Divn. Punjab National Bank, Head Office, New Delhi.	Nominees of State Government.
8. Shri S.K. Khanna, Development Manager, Punjab National Bank, Rohtak. 9. Dr. Vikas Misra, Head of Economics Deptt., Kurukshetra University, Kurukshetra.	Nominees of the Sponsor Bank.

[No. F. 4—14/75-AC-II]

का० आ० 4608.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 9 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में हरयाणा ग्रामीण बैंक, भिवानी के निदेशक-मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री एस० पी० मेहरा	अध्यक्ष
2. श्री प्रेम कुमार, अवर सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली । 3. श्री आर० एल० अग्रवाल, उपनिदेशक (सहकारिता), उद्योग और सिविल सप्लाई मंत्रालय, नयी दिल्ली । 4. श्री एस० पी० भावे, सहायक मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नयी दिल्ली ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
5. श्री दयानन्द एडवोकेट, करखी दादरी, हरयाणा । 6. श्री ए० सी० शर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
7. श्री के० एन० ताहमणी, प्रबन्धक, प्राथमिक क्षेत्र तथा लीड बैंक प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली । 8. श्री एस० के० खन्ना, विकास प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, रोहतक । 9. डा० विकास मिश्र, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।	प्रायोजक बैंक द्वारा मनोनीत

[सं० एफ० 4-14/75-ए० सी०-II]

का० आ० 4609.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 9 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री एस० एल० जैन	अध्यक्ष
2. श्री एस० एस० चौहान, निदेशक (अधिक उपज किस्म), कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नयी दिल्ली । 3. श्री एच० के० गुहा, अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नयी दिल्ली । 4. श्री डी० सी० शर्मा, सहायक मुख्याधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
5. श्री एन० एस० वर्मा, उप सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । 6. श्री सहदेव शर्मा, विधान सभा सदस्य, जिला प्रमुख, जयपुर ।	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
7. डा० हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रोफेसर, पौद्दार इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, जयपुर । 8. श्री ओ० पी० कौशिक, कृषि विकास अधिकारी, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जयपुर । 9. श्री गुलाम हुसैन, नागौर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड	प्रायोजक बैंक द्वारा मनोनीत

[सं० एफ० 4/12/75-ए० सी०-II]

New Delhi, the October 3, 1975

S.O. 4609.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 of the Regional Rural Banks Ordinance 1975 (13 of 1975), the Board of directors of the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur shall consist of the following members, namely :—

1. Shri S.L. Jain	Chairman.
2. Shri S.S. Chauhan, Director (High Yielding Varieties), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, New Delhi. 3. Shri H.K. Guha, under Secretary, Govt. of India, Ministry of Finance Department of Banking, New Delhi. 4. Shri D.C. Sharma, Asstt. Chief Officer, Reserve Bank Bank of India Jaipur.	Nominees of Central Government.
5. Shri N. N. Verma, Deputy, Secy., Finance Department, Government of Rajasthan, Jaipur. 6. Shri Sehdev Sharma, MLA, Zila Pramukh, Jaipur.	Nominees of State Government.
7. Dr. Harish Chandra Sharma, Professor, Podar Institute of Management, Jaipur. 8. Shri O.P. Kaushik, Agricultural Development Officer, United Commercial Bank, Jaipur. 9. Shri Ghulam Hussain, Nagaur Cooperative Marketing Society Ltd.	Nominees of Sponsor Bank.

[No. F. 4-12/75-AC-II]

का० आ० 4610.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री के० डी० अग्रवाल	अध्यक्ष
2. श्री आर० पी० जैन, उपनिदेशक (सहकारिता ऋण), ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई विभाग, नई दिल्ली । 3. श्री बिशन दास, अनुसंधान अधिकारी, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली । 4. श्री के० सी० शर्मा, सहायक मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
5. श्री ऐनुल आबिदीन, प्रशासक, गंडक कमांड एरिया प्राजेक्ट । 6. श्री राम प्रताप बहादुर सिंह, एडवोकेट, भार्फत जिला कांग्रेस समिति, गोरखपुर ।	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
7. श्री आर० पी० श्रीवास्तव, शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, गोरखपुर । 8. श्री पी० एन० सिंह, प्रबन्धक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, देवरिया । 9. श्री अब्दुल जालिम, हथकरघा बुनकर, खुराना, गोरखपुर ।	प्रायोजक बैंक द्वारा मनोनीत

[सं० एफ० 4-13/75-ए० सी०-II]

S.O. 4610.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1974 (13 of 1975), the Board of directors of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur shall consist of the following members, namely :—

1. Shri K.D. Agrawal	Chairman.
2. Shri R.P. Jain, Dy. Director (Cooperative Credit), Deptt. of Rural Development, Min. of Agri. & Irrigation, New Delhi. 3. Shri Wishan Dass, Research Officer, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi. 4. Shri K.C. Sharma, Asstt. Chief Officer, Reserve Bank of India, Kanpur.	Nominees of the Central Government.
5. Shri Ainul Abidin, Administrator, Gandak Command Area Project. 6. Shri Ram Pratap Bahadur Singh, Advocate, Care of Distt. Congress Committee, Gorakhpur.	Nominees of the State Government.
7. Shri R.P. Srivastava, Branch Manager, State Bank of India, Gorakhpur. 8. Shri P.N. Singh, Manager, Central Bank of India, Deoria. 9. Shri Abdul Jalim, Handloom Weaver, Khurana, Gorakhpur.	Nominees of the Sponsor Bank.

[No. F. 4-13/75-AC-II]

का० आ० 4611—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 9 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री आर० के० गर्ग	अध्यक्ष
2. श्री सी० डब्ल्यू० मीरचंदानी, अवर सचिव, बैंकिंग विभाग, नयी दिल्ली ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत
3. श्री एस० पी० शर्मा, अवर सचिव, (डी०पी०ए०पी० प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नयी दिल्ली ।	
4. श्री ओ० पी० जौहरी, सहायक मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर ।	
5. श्री एस० एल० शुक्ल, निदेशक, दुग्धशाला, उत्तर प्रदेश, सचिव भवन, सचिवालय, लखनऊ ।	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
6. श्री मिही लाल, डिपुटी गंज, मुरादाबाद ।	
7. श्री पी० एस० वी० मलैया, क्षेत्रीय विकास प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली ।	प्रायोजक बैंक द्वारा मनोनीत
8. श्री डी० टी० पै, जिला विकास प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली ।	
9. श्री खुर्शीद अहमद, अंसारी, हथकरघा बुनकर, अमरोहा ।	

(सं० 4-15/75-ए० सी०-II)

अमल कुमार दत्त, संयुक्त सचिव

S.O. 4611.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975) the Board of directors of the Prathama-Bank, Moradabad shall consist of the following members, namely :—

1. Shri R.K. Garg	Chairman
2. Shri C.W. Mirchandani Under Secretary, Department of Banking, New Delhi.	Nominees of Central Government.
3. Shri J.P. Sharma, under-Secretary (DPAP Division), Department of Rural Development, Min. of Agri. & Irrigation, New Delhi.	
4. Shri O.P. Johari, Asstt. Chief Officer, RBI, Kanpur.	
5. Shri S.L. Shukla, Director, Dairies Uttar Pradesh, Sachiv Bhavan, Secretariat, Lucknow.	Nominees of State Government.
6. Shri Mihi Lal, Deputy Ganj, Moradabad.	
7. Shri P.S.V. Mallya, Regional Development Manager Syndicate Bank, New Delhi.	Nominees of Sponsor Bank.
8. Shri D.T. Pai, District Development Manager, Syndicate Bank, New Delhi.	
9. Shri Khurshid Ahmed Ansari, Handloom Weaver, Amroha.	

[No. F. 4-15/75-AC-II]

A.K. DUTT, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1975

का० आ० 4612.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में सितम्बर 1975 के दिनांक 26 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए बैंक

(इशू विभाग)

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	23,41,26,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
प्रचलन में नोट	6135,06,14,000		विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6158,47,40,000	जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		1881,03,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5835,39,84,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं		6158,47,40,000	कुल आस्तियां		6158,47,40,000

दिनांक 1 अक्तूबर 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर

26 सितम्बर 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	23,41,26,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,45,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,84,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	62,95,39,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खज़ाना बिल	1086,48,46,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	687,39,61,000
जमाराशियां :—		निवेश**	290,55,70,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	62,43,76,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	9,82,29,000	(ii) राज्य सरकारों को @	73,24,00,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	530,52,93,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	188,50,00,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	16,91,59,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	321,57,79,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,93,69,000	(iii) दूसरों को	12,36,46,000
(iv) अन्य बैंक	72,39,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,60,44,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,50,76,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वास निगम को	87,20,00,000
(ग) अन्य	1179,62,42,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	164,94,91,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	93,45,91,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	708,91,89,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	329,30,91,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	345,61,76,000
रुपये	3694,85,87,000	रुपये	3694,85,87,000

*नकदी, मांगधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है ।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

†भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भोयाधी बिलों पर अग्रिम दिये गये 47,77,00,000 रुपये शामिल हैं ।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

के० आर० पुरी, गवर्नर

[सं० फ० 10(1)/75-बी० ओ I]

दिनांक : 1 अक्तूबर, 1975

New Delhi, the 3rd October, 1975

RESERVE BANK OF INDIA

S.O. 4612.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 26th day of September, 1975

(ISSUE DEPARTMENT)

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department.	23,41,26,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6135,06,14,000		(a) Held in India	182,52,56,000	
			(b) Held outside India	..	
Total notes issued		6158,47,40,000	Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		18,81,03,000
			Government of India Rupee Securities		5835,39,84,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6158,47,40,000	Total Assets		6158,47,40,000

Dated the 1st Day of October, 1975 K.R. Puri, Governor

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 26th September, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	23,41,26,000
		Rupee Coin	2,45,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,84,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	62,95,39,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	1086,48,46,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	687,39,61,000
		Investments**	290,55,70,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	73,24,00,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	188,50,00,000
		(ii) State Co-operative Banks††	321,57,79,000
(a) Government :		(iii) Others	12,36,46,000
(i) Central Government	62,43,76,000	Loans, Advances and Investments from National	
(ii) State Governments	9,82,29,000	Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :—	
(b) Banks			
(i) Scheduled Commercial Banks	530,52,93,000	(i) Sate Governments	69,60,44,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	16,91,59,000	(ii) State Co-operative Banks	12,50,76,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,93,69,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv)Other Banks	72,39,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
	1179,62,42,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank	10,60,13,000
	164,94,91,000	Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
	708,91,89,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	93,45,91,000
	3694,85,87,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank.	329,30,91,000
(c) Others		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank.	..
Bills Payable			
Other Liabilities		Other Assets	345,61,76,000
Rupees		Rupees	3694,85,87,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund but including temporary Overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 47,77,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

K.R.Puri, Governor.

[No. F. 10 (1)/75 BOI]

Dated the 1st day of October, 1975.

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4613.—जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली के निदेशक, श्री एल० डी० कटारिया को श्री डी० एन० घोष के स्थान पर जमा बीमा निगम के निदेशक के रूप में नामांकित करती है ।

[संख्या एफ० 6/7/75-बी० ओ०1]

च० वा० मीरचन्दानी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4613.—In pursuance of the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) the Central Government hereby nominates Shri L. D. Kataria, Director, Ministry of Finance, Department of Banking, New Delhi as director of the Deposit Insurance Corporation vice Shri D. N. Ghosh.

[No. F. 6/7/75-BO. I]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4614.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा 2 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर, उन बाण्डों पर देय ब्याज की दर 6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक निश्चित करती है जो उक्त निगम द्वारा 29 अक्तूबर, 1975 को जारी किये जाने वाले हैं और 29 अक्तूबर, 1985 को परिपक्व होंगे ।

[संख्या एफ० 2(61) आई० एफ०आई०/75]

वी० के० शुंगलू, उप-सचिव

New Delhi, the 8th October, 1975

S.O. 4614.—In pursuance of sub-section (2) of section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948) the Central Government on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 6% (six per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on the 29th October, 1975 and maturing on the 29th October, 1985.

[No. F. 2(61)IFI/75]

V. K. SHUNGLU, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1975

आय कर

का०आ० 4615.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-आई०टी०), तारीख 28 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करता है ।

उक्त अनुसूची में, अन्तिम क्रम संख्या के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6
"74	कलकत्ता नगर और हावड़ा तथा 24-परगना के सिविल जिलों के अन्तर्गत क्षेत्र के भीतर, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (19) के अनुसार आवासन सोसाइटियों और परिवहन कारबार चलाने वाली सोसाइटियों से भिन्न, सभी सहकारी सोसाइटियां	आय-कर अधिकारी सहकारी सर्किल कलकत्ता	सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण), जो सहकारी सर्किल, कलकत्ता की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।	सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आय-कर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है ।	आय-कर आयुक्त, जो सहकारी सर्किल, कलकत्ता की बाबत आय-कर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।
75	कलकत्ता नगर और हावड़ा तथा 24-परगना के सिविल जिलों के अन्तर्गत क्षेत्र के भीतर, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (19) के अनुसार सभी सहकारी आवासन सोसाइटियां	आय-कर अधिकारी सहकारी आवासन सर्किल कलकत्ता	सहायक आय-कर आयुक्त, जो सहकारी आवासन सर्किल, कलकत्ता की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।	सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।	आय-कर आयुक्त जो सहकारी आवासन सर्किल कलकत्ता की बाबत आय-कर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।"

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 964 (फा० सं० 187/9/75-आई० टी० ए० आई०)]

टी० पी० झुननवाला, सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Income-tax

New Delhi, the 15th July, 1975

S. O. 4615.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the schedule annexed to its Notification No. I (F. No. 55/233/63-IT) dated the 18th May, 1964 as amended from time to time.

After the last serial number in the said schedule the following shall be added :

1	2	3	4	5	6
"74.	All Co-operative Societies within the meaning of sub-section 19 of section 2 of the Income-tax Act, 1961 within the area covered by the City of Calcutta and Civil Districts of Howrah and 24-Parganas other than Housing Societies and Societies carrying on transport business.	Income-tax Officer Co-operative Circle Calcutta.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the function of an Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax in respect of Co-operative Circle, Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the I.T.O. referred to in Colmn. 3.	Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the function of C.I.T. in respect of Cooperative Circle, Calcutta.
75.	All Co-operative Housing Societies within the meaning of sub-section 19 of the section 2 of the Income-tax Act, 1961 within the area covered by the City of Calcutta and Civil Districts of Howrah and 24 Parganas.	Income-tax Officer, Co-operative Housing Circle, Calcutta.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax who has been appointed to performed the function of an Inspecting Assistant Commissioner, of I. Tax in r/o Co-op. Housing Circle Calcutta.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax who has been invested with powers to hear appeals against the decision of I.T.O. referred to in Colmn 3."	C.I.T. who has been appointed to perform the function of C.I.T. in respect of Co-operative Housing Circle, Calcutta.

[No. 964(F. No. 187/9/75-ITAI)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Secy.

This Notification will come into effect from Ist August, 1975

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

का० आ० 4616.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे—

अनुसूची

रेंज	आय-कर सर्किल/वार्ड/जिले	
केन्द्रीय रेंज-I कलकत्ता	केन्द्रीय सर्किल :	1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, कलकत्ता
केन्द्रीय रेंज-II कलकत्ता	केन्द्रीय सर्किल :	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, कलकत्ता

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणाम स्वरूप की जाने वाली अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 1-8-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 987(फ० सं० 261/7/75-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 24th July, 1975

S.O. 4616.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or Super-tax in the Income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circle/Wards/Districts	
Central Range-I, Calcutta	Central Circle :	I, V, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, and XVII, Calcutta.

Range	Income tax circle/wards/District	
Central Range-II Calcutta	Central Circle :	II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, and XXXIII, Calcutta.

Where an income-tax Circle, Ward or district or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range appeals arising out of assessments made in that income-tax circle, ward or districts or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax circle, ward or district or part thereof is transferred shall from the date this notification take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-8-75.

EXPLANATORY NOTE:

The amendment has become necessary consequent on redistribution of work amongst the A.A.Cs under Calcutta (Central) Charge.

(This does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory)

[No. 987(F. No. 261/7/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1975

का० आ० 4617.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे —

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सर्किल/वार्ड/जिले
1	2	3
1.	विशेष रेंज-I, नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल—2, 7, 12, 13, 14, 16, 19 और 20, नई दिल्ली ।
		(ii) घ-1 जिला, नई दिल्ली ।
2.	विशेष रेंज-II, नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल-1, 4, 6, 9, 21 और 22, नई दिल्ली ।
		(ii) घ-2 जिला, नई दिल्ली ।
		(iii) वकील सर्किल, नई दिल्ली ।
3.	विशेष रेंज-III, नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल—3, 10 और 15, नई दिल्ली ।
		(ii) विशेष सर्किल—3, 4 और 4 (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
		(iii) चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सर्किल, नई दिल्ली ।
4.	विशेष रेंज-IV नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल—5, 8, नई दिल्ली ।
		(ii) विशेष सर्किल—1, 1 (अतिरिक्त) और 7, नई दिल्ली ।
5.	विशेष रेंज-V, नई दिल्ली	(i) विशेष सर्किल—5, 6, 6 (अतिरिक्त), 10, 12, 13, और 14, नई दिल्ली ।
		(ii) जिला 8 (3), (4), (5) और (6) नई दिल्ली ।
		(iii) जिला 10(3), (4) और (11), नई दिल्ली ।
		(iv) भविष्यनिधि सर्किल, नई दिल्ली ।
6.	'क' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 10(1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 10 (अतिरिक्त), (12) और (13), नई दिल्ली ।
		(ii) जिला 8(15), (16), (17), (18), (19), और (19) अतिरिक्त, नई दिल्ली ।
		(iii) सर्वेक्षण सर्किल-4, नई दिल्ली ।
		(iv) जिला 11 (1), और (2), नई दिल्ली ।
7.	'ख' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 3(19), (20), (21), (22), और (23), नई दिल्ली ।
		(ii) जिला—7 (1), (2), (3) और (4), नई दिल्ली ।
		(iii) विशेष सर्किल 8 और 8 (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
		(iv) विदेश अनुभाग, नई दिल्ली ।
		(v) प्रतिश्राय सर्किल, नई दिल्ली ।
		(vi) चिकित्सक सर्किल, नई दिल्ली ।
		(vii) जिला 7 वार्ड क, क (1) और ख, नई दिल्ली ।
		(viii) जिला 3 वार्ड क, क (अतिरिक्त), क(अतिरिक्त-1) ओ एण्ड ओ (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
		(ix) जिला ख-1, ख-1(1), ग 1 ग-1(1), ग-2 और ग-3, नई दिल्ली ।
8.	'ग' रेंज, नई दिल्ली नथ-सजित	(i) जिला 3 (10), (11), (12), 12 (अतिरिक्त), (13) (13)(अतिरिक्त), (14), (14)(अतिरिक्त) 14-प्रथम अतिरिक्त और (26), नई दिल्ली ।

(1)	(2)	(3)
9.	'ख' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 3(6) (अतिरिक्त), (7), (7) (अतिरिक्त), (8), और (9), नई दिल्ली ।
10.	'ङ' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 5(1), (2), (3), (4), (5), और (6), नई दिल्ली ।
		(ii) जिला 8(1), (2), (2), (अतिरिक्त), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), और (14) नई दिल्ली,
		(iii) जिला 8, वार्ड-क, क (अतिरिक्त), ख, ख (अतिरिक्त-1) ख (अतिरिक्त 2) ग, घ, च(1), छ, ज, ज (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
		(iv) क-1, क-2, क-3, क-4, क-4(1), और 1(1) जिला, नई दिल्ली ।
		(v) आय-कर एवं धन-कर सर्किल-8
11.	'च' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला-3 (15), (16), 16(अतिरिक्त), (17) (17) (अतिरिक्त), (18), (18) (अतिरिक्त), 18(प्रथम अतिरिक्त), 18(द्वितीय अतिरिक्त), और 24, नई दिल्ली ।
12.	'छ' रेंज नई दिल्ली	(i) कम्पनी सर्किल-11, 17, 18, नई दिल्ली ।
		(ii) विशेष सर्किल-2, 2(अतिरिक्त) और 9, नई दिल्ली ।
		(iii) न्यास सर्किल, नई दिल्ली ।
13.	'ज' रेंज	(i) जिला 6(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10) (अतिरिक्त), (11), (12), (13), (14), और (15) नई दिल्ली ।
		(ii) आय-कर एवं-सम्पदा शुल्क सर्किल, नई दिल्ली ।
		(iii) जिला 6, वार्ड क, क(अतिरिक्त), क(1), क(2), ख (अतिरिक्त), ग, ग(अतिरिक्त) ग(1), ग-1 (अतिरिक्त), घ और ङ, नई दिल्ली ।
		(iv) अतिरिक्त सम्पदा शुल्क-एवं-आय-कर सर्किल, नई दिल्ली ।
14.	'झ' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 2(1), (2), (2), (अतिरिक्त), (3), (4), (5), (6), और (7), नई दिल्ली ।
		(ii) जिला 2—वार्ड क, ख, ग, घ, ङ, च, क-(1), ग(1), ग(1) (अतिरिक्त), और ग(2), नई दिल्ली
15.	'ट' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला-5(7), (8), (9), (10), (11), 11(अतिरिक्त) (12), (12) (अतिरिक्त), (13), (13)(अतिरिक्त), (14), (15), (15) (अतिरिक्त) (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त) (18) (19), और (20), नई दिल्ली ।
		(ii) ठेकेदार सर्किल, नई दिल्ली ।
		(iii) ख-12 और ख-15 जिला, नई दिल्ली ।
		(iv) जिला 5, वार्ड क, क (अतिरिक्त), क(1) ख, ख (अतिरिक्त) ख(1), ग, ग-1, घ, ङ, च, च(1), च(1)(अतिरिक्त), च-3 और छ, नई दिल्ली ।
		(v) आय-कर-एवं-धन-कर सर्किल 9 और 10, नई दिल्ली ।
16.	'ठ' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला-3(25) (अतिरिक्त) (27), (28), (29), (30), (31), (32), (32) (अतिरिक्त) (33), (34), और (35), नई दिल्ली ।
		(ii) सर्वेक्षण सर्किल 3, नई दिल्ली ।
		(iii) परिवहन सर्किल, नई दिल्ली ।
		(iv) जिला—3, वार्ड ज, झ, ञ, ट, ठ, क(1), ग(1), ङ(1), छ(1), झ(1), और ट(1), नई दिल्ली ।
		(v) विशेष निर्धारण सर्किल, 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 10 नई दिल्ली ।
		(vi) विशेष सर्वेक्षण सर्किल-2, 3, 4 और 9, नई दिल्ली ।
		(vii) आय-कर-एवं-धन-कर सर्किल-2, नई दिल्ली ।
		(viii) ख-6, ख-7, ख-7 (अतिरिक्त) ख-9 और ख-9 (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।

(1)	(2)	(3)
17.	'ड' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला 3 (1), (1) (अतिरिक्त) 1 (प्रथम अतिरिक्त) (संग्रहण), (1) द्वितीय अतिरिक्त (संग्रहण) (1) तृतीय अतिरिक्त (संग्रहण), (2) (2) (अतिरिक्त), (3), (4), दक (5), नई दिल्ली ।
		(ii) निष्क्रान्त सर्किल, नई दिल्ली ।
		(iii) जिला-3, वार्ड ख, ग, घ, ड०, च, च (अतिरिक्त) छ, ड, ड (1) और क, नई दिल्ली
18.	'ढ' रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला—4 (1), (2), (3), (4), (5), (5) (अतिरिक्त), (6) (6) (अतिरिक्त), (7), (8), (9), (10), और (11) नई दिल्ली ।
		(ii) जिला-1 (1), (1) (अतिरिक्त) नई दिल्ली ।
		(iii) जिला-1, वार्ड क-1 और क (1), नई दिल्ली ।
		(iv) जिला-4, वार्ड क, ख, ग, घ और ग (1), नई दिल्ली ।
		(v) जिला-9, वार्ड क, नई दिल्ली
19.	'ण' रेंज, नई दिल्ली	(i) सभी सरकारी वेतन सर्किल, नई दिल्ली ।
		(ii) सभी प्राइवेट वेतन सर्किल, नई दिल्ली ।
		(iii) आय-कर अधिकारी, (विशेष कार्य अधिकारी, कृषि) धन-कर शाखा, नई दिल्ली ।
		(iv) जिला-2 (12), (12), (अतिरिक्त), (13), (14), और (15), नई दिल्ली ।
		(v) आय-कर एवं धनकर सर्किल 7, नई दिल्ली ।
20.	'त' रेंज, नई दिल्ली (नव सर्जित)	(i) जिला-1 (2), (2) (अतिरिक्त), और (3), नई दिल्ली ।
		(ii) जिला-2 (8), (8) (अतिरिक्त), (9), (9) (अतिरिक्त), (10), (11) और (11) (अतिरिक्त) नई दिल्ली ।
		(iii) जिला-9 (1), नई दिल्ली ।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणाम स्वरूप की जाने वाली अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 1-8-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1007/फा० सं० 261/4/75-आई०टी०जे०]

एम० रामस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st July, 1975

S.O. 4617.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, wards and Districts specified in the corresponding entry in Column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles/Wards and Districts
(1)	(2)	(3)
1.	Special Range-I, New Delhi.	(i) Companies Circle-II, VII, XII, XIII, XIV, XVI, XIX, & XX, New Delhi.
		(ii) D-I, District , New Delhi.
2.	Special Range-II, New Delhi.	(i) Companies Circle-I, IV, VI, IX, XXI & XXII, New Delhi.
		(ii) D-II, District, New Delhi.
		(iii) Lawyers' Circle, New Delhi.
3.	Special Range-III, New Delhi.	(i) Companies Circle-III, X & XV New Delhi.
		(ii) Special Circles III, IV & IV (Addl.) New Delhi.
		(iii) Chartered Accountants' Circle, New Delhi.
4.	Special Range-IV, New Delhi.	(i) Companies Circle V & VIII, New Delhi.
		(ii) Special Circles-I, I (Addl.) & VII, New Delhi.
5.	Special Range-V, New Delhi.	(i) Special Circles, V, VI, VI (Addl.), X, XI, XII, XIII & XIV, New Delhi.
		(ii) Distt. VIII (3), (4), (5), & (6), New Delhi.
		(iii) District X (3), (4) & (11), New Delhi.
		(iv) Provident Fund Circle, New Delhi.
6.	'A' Range, New Delhi.	(i) District X (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 10 (Addl.), (12) & (13), New Delhi.

(1)	(2)	(3)
		(ii) District VIII (15), (16), (17), (18), (19), & 19 (Addl.), New Delhi.
		(iii) Survey Circle-IV, New Delhi.
		(iv) District XI (1), & (2), New Delhi.
7.	'B' Range, New Delhi.	(i) District III (19), (2), (21), (22) & (23), New Delhi.
		(ii) Districts-VII (1), (2), (3), & (4) New Delhi.
		(iii) Special Circles VIII & VIII (Addl.), New Delhi.
		(iv) Foreign Section, New Delhi.
		(v) Refund Circle, New Delhi.
		(vi) Doctors' Circle, New Delhi.
		(vii) Distt. VII Ward A, A(1) & B, New Delhi.
		(viii) Distt. III Wards A, A (Addl.), A (Addl.-I) O & O (Addl.), New Delhi.
		(ix) Distt. B-I, B-I (1), CI, C-I (1), CII & C-III, New Delhi.
8.	'C' Range, New Delhi (Newly created).	(i) Distt. III (10), (11), (12), 12 (Addl.) (13), (13) (Addl.), (14), (14) (Addl.), 14-Ist Addl. & (26), New Delhi.
9.	D, Range, New Delhi	(i) Distt. III(6), 6 (Addl.), 6(7) (7) (Addl.), (8), & 9 New Delhi.
10.	'E' Range, New Delhi.	(i) Distt. V (1), (2), (3), (4), (5) & (6), New Delhi.
		(ii) Distt. VIII (1), (2), (2) (Addl.), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), & (14), New Delhi.
		(iii) Distt. VIII, Wards-A, A (Addl.), B, B (Addl.), B (Addl.-I), B (Addl. II), C, D, D(1), E, F, F(Addl.), New Delhi.
		(iv) A-I, A-II, A-III, A-IV, A-IV(1), & I(1) Districts, New Delhi.
		(v) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle-VIII, New Delhi.
11.	'F' Range, New Delhi.	(i) District-III (15), (16), 16 (Addl.), (17), 17 (Addl.), (18), (18) (Addl.), 18 (Ist Addl.), 18 (2nd Addl.), & 24, New Delhi.
12.	'G' Range, New Delhi.	(i) Companies Circles-XI, XVII, XVIII, New Delhi.
		(ii) Special Circle-II, II (Addl.), & IX, New Delhi.
		(iii) Trust Circle, New Delhi.
13.	'H' Range	(i) District VI (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10) (Addl.), (11), (12), (13), (14), & (15), New Delhi.
		(ii) Income-tax-cum-Estate Duty Circle, New Delhi.
		(iii) District VI, Wards A, A (Addl.), A (I), A (II), B (Addl.), C, C (Addl.), C (I), C-I (Addl.), D & E, New Delhi.
		(iv) Addl. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New Delhi.
14.	'J' Range, New Delhi.	(i) District II (1), (2), (2) (Addl.), (3), (4), (5), (6), & (7), New Delhi.
		(ii) District II-Wards A, B, C, D, E, F, A (I), C (I), C (I) (Addl.), & C (II), New Delhi.
15.	'K' Range , New Delhi.	(i) District-V (7), (8), (9), (10), (11), (11) (Addl.), (12), (12), (Addl.), (13), (13) (Addl.), (14), (15), (15) (Addl.), (16), (16) (Addl.), (17), (17) (Addl.), (18), (19), & (20), New Delhi.
		(ii) Contractors' Circle, New Delhi.
		(iii) B-XII & B-XV Districts, New Delhi.
		(iv) District V, Wards A, A (Addl.), A (I), B, B (Addl.), B (I), C, C-I, D, E, F, F (I), F (I) (Addl.), F-III, & G, New Delhi.
		(v) Income-tax-cum-Wealth-tax Circles IX & X, New Delhi.
16.	'L' Range, New Delhi.	(i) District-III (25), (25) (Addl.), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (32) (Addl.), (33), (34), & (35), New Delhi.
		(ii) Survey Circle III, New Delhi.
		(iii) Transport Circle, New Delhi.
		(iv) District-III, Wards H, I, J, K, L, A (I), C(I), E(I), C(I), I(I), & K(I), New Delhi.
		(v) Special Assessment Circles, I, II, III, VI, VII, VIII & X, New Delhi.
		(vi) Special Survey Circles-II, III, IV, & IX, New Delhi.
		(vii) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle-II, New Delhi.
		(viii) B-VI, B-VII, B-VII (Addl.), B-IX & B-IX (Addl.), New Delhi.
17.	'M' Range, New Delhi.	(i) District III (1), (1) (Addl.), I (1st Addl.) (Collection), (1) 2nd Addl. (Collection), (1) 3rd Andl. (Collection). (2), (2) (Addl.), (3), (4), and (5), New Delhi.
		(ii) Evacuee Circles, New Delhi.
		(iii) District-III, Wards B, C, D, E, F, F (Addl.), G, M, M (I) and N, New Delhi.
18.	'N' Range, New Delhi.	(i) District-IV (1), (2), (3), (4), (5), (5) (Addl.), (6), (6) (Addl.), (7), (8), (9), (10), & (11), New Delhi.
		(ii) District-I (1), (1) (Addl.), New Delhi.
		(iii) District-I, Wards A & A (1), New Delhi.
		(iv) District-IV, Wards A, B, C, & C(1), New Delhi.
		(v) District-IX, Ward A, New Delhi.

1	2	3
19.	'O' Range, New Delhi.	(i) All Government Salary Circles, New Delhi. (ii) All Private Salary Circles, New Delhi. (iii) Income-tax Officer (Officer on Special Duty, Agricultural, Wealth-tax Branch, New Delhi. (iv) District-II (12), (12) (Addl.), (13), (14), & (15), New Delhi. (v) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle VII, New Delhi.
20.	'P' Range, New Delhi, (Newly created).	(i) District-I (2), (2) (Addl.), & (3), New Delhi. (ii) District-II (8), (8) (Addl.), (9), (9) (Addl.), (10), (11), and (11) (Addl.), New Delhi. (iii) District-IX (1), New Delhi.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Income-tax of the ranges from whom that income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st August, 1975.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on re-organisation of jurisdiction of the Commissioners of Income-tax with effect from 1-8-1975.

(This note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1007 (F.No. 261/4/75-ITJ)]

S. RAMASWAMI, Under Secretary.

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

का० आ० 4618.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 754 (फा० सं० 261/12/74-आई टी जे) तारीख 31-10-1974 को आंशिक रूप से उपान्तरित करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 7 और 8 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
7.	रेंज-I, मेरठ	(i) सर्किल—I, मेरठ (ii) मुजफ्फरनगर सर्किल (iii) क-वार्ड, मेरठ (iv) ख-वार्ड, सर्किल-I, मेरठ (v) ग-वार्ड, सर्किल-I, मेरठ (vi) घ-वार्ड, सर्किल-I, मेरठ (vii) ङ०-वार्ड, मेरठ (viii) ङ०-वार्ड, सर्किल-I, मेरठ (ix) ज-वार्ड, मेरठ (x) झ-वार्ड, सर्किल-I, मेरठ (xi) ञ-वार्ड, मेरठ (xii) ट-वार्ड, सर्किल-II, मेरठ (xiii) विशेष वार्ड सर्किल-I, मेरठ (xiv) अतिरिक्त 'क' वार्ड, मेरठ (xv) अतिरिक्त 'क' वार्ड, सर्किल-I, मेरठ
8.	रेंज-II मेरठ	(i) सर्किल-II, मेरठ (ii) गाजियाबाद सर्किल (iii) हापुड़ सर्किल (iv) बेलन सर्किल, मेरठ (v) ड-वार्ड मेरठ (vi) ढ-वार्ड, सर्किल-II, मेरठ (vii) ण-वार्ड, मेरठ (viii) ण-वार्ड, सर्किल-II, मेरठ (ix) थ-वार्ड, मेरठ (x) थ-वार्ड, सर्किल-II, मेरठ (xi) अतिरिक्त छ-वार्ड, मेरठ (xii) अतिरिक्त छ, वार्ड सर्किल-II मेरठ (xiii) छ-वार्ड, मेरठ (xiv) छ-वार्ड, सर्किल-II, मेरठ (xv) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, मेरठ (xvi) परियोजना सर्किल, मेरठ (xvii) 'ट' वार्ड सर्किल-II, मेरठ

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की जाने वाली अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 1-8-1975 से प्रभावी होगी ।

2. बोर्ड की अधिसूचना सं० 980 तारीख 23.7.75., रद्द समझी जाएगी ।

[सं० 1008/फा० सं० 261/1/75-आई.टी.जे]

New Delhi, the 1st August, 1975

S. O. 4618.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of notification No. 754 (F. No. 261(12/74-ITJ) dated 31-10-1974, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the entries at Sl. Nos. 7 & 8 in the Schedule to the said Notification shall be substituted by the following entries :—

SCHEDULE

S. No.	Range	Income-tax Circles, Wards & Districts
1	2	3
7.	Range-1, Meerut.	(i) Circle-1, Meerut. (ii) Muzaffarnagar Circle. (iii) A-Ward, Meerut. (iv) A-Ward, Circle-1, Meerut. (v) D-Ward, Meerut. (vi) D-Ward, Circle-1, Meerut. (vii) E-Ward, Meerut. (viii) E-Ward, Circle-1, Meerut. (ix) H-Ward, Meerut. (x) H-Ward, Circle-1, Meerut. (xi) J-Ward, Meerut. (xii) J-Ward, Circle-II, Meerut. (xiii) Special Ward, Circle-1, Meerut. (xiv) Additional 'A' Ward Meerut. (xv) Additional 'A' Ward Circle-1, Meerut.
8.	Range-II, Meerut.	(i) Circle-II, Meerut. (ii) Ghaziabad Circle. (iii) Hapur Circle. (iv) Salary Circle, Meerut. (v) B-Ward Meerut. (vi) B-Ward, Circle-II, Meerut. (vii) C-Ward, Meerut. (viii) C-Ward, Circle-II, Meerut. (ix) F-Ward, Meerut. (x) F-Ward, Circle-II, Meerut. (xi) Addl. G-Ward, Meerut. (xii) Addl. G-Ward, Circle-II, Meerut (xiii) G-Ward, Meerut. (xiv) G-Ward, Circle-II, Meerut. (xv) Special Survey Circle, Meerut. (xvi) Project Circle, Meerut. (xvii) 'K' Ward Circle-II, Meerut.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or Distt. or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom that said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-8-75.

2. The Board's Notification No. 980 dated 23-7-75 be treated as cancelled.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on abolition of A.A.C., Range-III Meerut under Meerut Charge.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1038 (F.No. 261/1/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

का० आ० 4616—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की साधारण अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे —

अनुसूची

रेंज	आय-कर सर्किल/वार्ड/जिले
1	2
सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) पुणे रेंज 1, पुणे।	1. क-वार्ड, पुणे 2. ग-वार्ड, पुणे 3. ङ-वार्ड, पुणे 4. च-वार्ड, पुणे 5. छ-वार्ड, पुणे 6. अतिरिक्त छ-वार्ड, पुणे 7. ट-वार्ड, पुणे 8. ड-वार्ड, पुणे 9. ढ-वार्ड, पुणे 10. त-वार्ड, पुणे 11. द-वार्ड, पुणे 12. ब-वार्ड, पुणे 13. म-वार्ड, पुणे 14. एस० एस० सी० 1, पुणे 15. संग्रहण सर्किल-1, पुणे 16. संग्रहण सर्किल-2, पुणे 17. संग्रहण सर्किल-3, पुणे 18. संग्रहण सर्किल-4, पुणे 19. संग्रहण सर्किल-5, पुणे 20. डब्ल्यू० टी० एवं जी० टी० सर्किल, पुणे 21. आई० टी० ओ०, प्रशासन, पुणे 22. क-वार्ड, अहमद नगर 23. ख-वार्ड, अहमद नगर 24. ग-वार्ड, अहमद नगर 25. घ-वार्ड, अहमद नगर

1	2
सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) ठाणा रेंज, ठाणा	1. क-वार्ड, ठाणा 2. अतिरिक्त क-वार्ड, ठाणा 3. ख-वार्ड, ठाणा 4 अतिरिक्त ख-वार्ड, ठाणा 5. ग-वार्ड, ठाणा 6. घ-वार्ड, ठाणा 7. ङ-वार्ड, ठाणा 8. च-वार्ड, ठाणा 9 छ-वार्ड, ठाणा 10. ज-वार्ड, ठाणा 11. झ-वार्ड, ठाणा 12. ट-वार्ड, ठाणा 13. ठ-वार्ड, ठाणा 14. ड-वार्ड, ठाणा 15. ढ-वार्ड, ठाणा 16. त-वार्ड, ठाणा 17. संग्रहण सर्किल-1, ठाणा 18. संग्रहण सर्किल-2, ठाणा 19. एस० एस० सी०, ठाणा 20. अतिरिक्त एस० एस० सी०, ठाणा 21. वसूली सर्किल-3, ठाणा 22. पालघर सर्किल, पालघर 23. ख-वार्ड, पुणे 24. छ-वार्ड, पुणे 25. अतिरिक्त छ-वार्ड, पुणे 26. घ-वार्ड, पुणे
आय-कर आयुक्त (अपील) नासिक रेंज, नासिक	1. क-वार्ड, नासिक 2. ख-वार्ड, नासिक 3. ग-वार्ड, नासिक 4. घ-वार्ड, नासिक 5. ङ-वार्ड, नासिक 6. च-वार्ड, नासिक 7. संग्रहण सर्किल, नासिक 8. संग्रहण सर्किल-1, नासिक 9. संग्रहण सर्किल-2, नासिक 10. एस० एस० सी०, नासिक 11. क-वार्ड, मालेगांव 12. ख-वार्ड, मालेगांव 13. क-वार्ड, धूलिया 14. ख-वार्ड, धूलिया 15. ग-वार्ड, धूलिया 16. घ-वार्ड, धूलिया 17. संग्रहण सर्किल, धूलिया 18. क-वार्ड, जलगांव 19. ख-वार्ड, जलगांव 20. ग-वार्ड, जलगांव 21. घ-वार्ड, जलगांव 22. ङ-वार्ड, जलगांव 23. च-वार्ड, जलगांव 24. संग्रहण सर्किल, जलगांव

1	2
सहायक आय-कर आयुक्त, पुणे रेंज II, पुणे	1 कम्पनी सर्किल, पुणे 2. अतिरिक्त कम्पनी सर्किल-पुणे 3. कम्पनी सर्किल, 1, पुणे 4. कम्पनी सर्किल, 2, पुणे 5. केन्द्रीय सर्किल, पुणे 6. क-वार्ड, पानवेल 7. ख-वार्ड, पानवेल 8. ग-वार्ड, पानवेल 9. क-वार्ड, सतारा 10. ख-वार्ड, सतारा 11. ग-वार्ड, सतारा 12. घ-वार्ड, सतारा 13. अतिरिक्त ग-वार्ड, पुणे 14. घ-वार्ड, पुणे 15. ज-वार्ड, पुणे 16. ठ-वार्ड, पुणे
सहायक आयकर आयुक्त (अपील), पुणे रेंज III, पुणे	1. एस०एस०सी०, पुणे 2. अतिरिक्त एस०एस०सी०, पुणे 3. वेतन और प्रतिदाय, पुणे 4. जी०एच०क्यू०, पुणे 5. क-वार्ड, शोलापुर 6. ख-वार्ड, शोलापुर 7. ग-वार्ड, शोलापुर 8. घ-वार्ड, शोलापुर 9. ङ०-वार्ड, शोलापुर 10. च-वार्ड, शोलापुर 11. संग्रहण सर्किल, शोलापुर 12. आई०टी०ओ० बारसी 13. एस०एस०सी०, शोलापुर 14. एस०एस०सी०, 2 पुणे 15. ध-वार्ड, पुणे 16. न-वार्ड, पुणे 17. प-वार्ड, पुणे 18. वेतन और प्रतिदाय सर्किल 1, पुणे 19. वेतन और प्रतिदाय सर्किल 2, पुणे 20. वेतन और प्रतिदाय सर्किल 3, पुणे 21. वेतन और प्रतिदाय सर्किल 4, पुणे 22. जी०एच०क्यू०, सर्किल 1, पुणे 23. जी०एच०क्यू०, सर्किल 2, पुणे 24. जी०एच०क्यू०, सर्किल 3, पुणे
सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), कोल्हापुर रेंज, कोल्हापुर	1. क-वार्ड, कोल्हापुर 2. ख-वार्ड, कोल्हापुर 3. ग-वार्ड, कोल्हापुर 4. घ-वार्ड, कोल्हापुर 5. ङ-वार्ड, कोल्हापुर 6. च-वार्ड, कोल्हापुर 7. छ-वार्ड, कोल्हापुर 8. ज-वार्ड, कोल्हापुर 9. संग्रहण सर्किल, कोल्हापुर 10. संग्रहण सर्किल 1, कोल्हापुर

1	2
	11. आई०टी०ओ० इचालकरनजी
	12. क-वार्ड, इचालकरनजी
	13. ख-वार्ड, इचालकरनजी
	14. संग्रहण सर्किल 2, कोल्हापुर
	15. एस०एस०सी०, कोल्हापुर
	16. आई०टी०ओ० रत्नगिरि
	17. क-वार्ड, सांगली
	18. ख-वार्ड, सांगली
	19. ग-वार्ड, सांगली
	20. घ-वार्ड, सांगली
	21. ङ०-वार्ड, सांगली
	22. संग्रहण सर्किल, सांगली

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो गया वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की जाने वाली अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया है, सहायक आय-कर (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 11-8-1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1022/फ० सं० 261/5/75-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 8th August, 1975

S. O. 4619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, and in supersession of all the previous orders, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Range specified in Col. 1 General Schedule, below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circle, Wards and Districts specified in the corresponding entry in Col. 2 thereof :

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
(1)	(2)
A.A.C., Poona Range I, Poona.	1. A-Ward, Poona.
	2. C-Ward, Poona.
	3. E-Ward, Poona.
	4. F-Ward, Poona.
	5. J-Ward, Poona.
	6. Addl. J-Ward, Poona.
	7. K-Ward, Poona.
	8. M-Ward, Poona.
	9. N-Ward, Poona.
	10. P-Ward, Poona.
	11. R-Ward, Poona.
	12. W-Ward, Poona.
	13. X-Ward, Poona.
	14. S.S.C.I., Poona.
	15. Collection Circle-I, Poona.
	16. Collection Circle-II, Poona.
	17. Collection Circle-III, Poona.
	18. Collection Circle-IV, Poona.
	19. Collection Circle-V, Poona.
	20. W.T.-Cum-G.T. Circles, Poona.
	21. I.T.O. Admn., Poona.
	22. A-Ward, Ahmednagar.
	23. B-Ward, Ahmednagar.
	24. C-Ward, Ahmednagar.
	25. D-Ward, Ahmednagar.
A.A.C., Thana Range, Thana.	1. A-Ward, Thana.
	2. Addl. A-Ward, Thana.
	3. B-Ward, Thana.
	4. Addl. B-Ward, Thana.
	5. C-Ward, Thana.
	6. D-Ward, Thana.
	7. E-Ward, Thana.
	8. F-Ward, Thana.
	9. G-Ward, Thana.
	10. H-Ward, Thana.
	11. J-Ward, Thana.
	12. K-Ward, Thana.
	13. L-Ward, Thana.
	14. M-Ward, Thana.
	15. N-Ward, Thana.
	16. P-Ward, Thana.
	17. Collection Circle-I, Thana.
	18. Collection Circle-II, Thana.
	19. S.S.C., Thana.
	20. Addl. S.S.C. Thana.
	21. Recovery Circle-III, Thana.
	22. Palghar Circle, Palghar.
	23. B-Ward, Poona.
	24. G-Ward, Poona.
	25. Addl. G-Ward, Poona.
	26. S-Ward, Poona.
A.A.C., Nasik Range, Nasik.	1. A-Ward, Nasik.
	2. B-Ward, Nasik.
	3. C-Ward, Nasik.
	4. D-Ward, Nasik.
	5. E-Ward, Nasik.
	6. F-Ward, Nasik.
	7. Collection Circle, Nasik.
	8. Collection Circle-I, Nasik.
	9. Collection Circle-II, Nasik.
	10. S.S.C., Nasik.
	11. A-Ward, Malegaon.
	12. B-Ward, Malegaon.
	13. A-Ward, Dhulia.
	14. B-Ward, Dhulia.
	15. C-Ward, Dhulia.
	16. D-Ward, Dhulia.
	17. Collection Circle, Dhulia.

(1)	(2)
	18. A-Ward, Jalgaon.
	19. B-Ward, Jalgaon.
	20. C-Ward, Jalgaon.
	21. D-Ward, Jalgaon.
	22. E-Ward, Jalgaon.
	23. F-Ward, Jalgaon.
	24. Collection Circle, Jalgaon.
A.A.C., Poona Range, II Poona.	1. Companies Circle, Poona.
	2. Addl. Companies Circle, Poona.
	3. Companies Circle I, Poona.
	4. Companies Circle II, Poona.
	5. Central Circle, Poona.
	6. A-Ward, Panvel.
	7. B-Ward, Panvel.
	8. C-Ward, Panvel.
	9. A-Ward, Satara.
	10. B-Ward, Satara.
	11. C-Ward, Satara.
	12. D-Ward, Satara.
	13. Addl. C-Ward, Poona.
	14. D-Ward, Poona.
	15. H-Ward, Poona.
	16. I.-Ward, Poona.
A.A.C., Poona Range III, Poona.	1. S.S.C., Poona.
	2. Addl. S.S.C., Poona.
	3. Salaries & Refunds, Poona.
	4. G.H.Q., Poona.
	5. A-Ward, Sholapur.
	6. B-Ward, Sholapur.
	7. C-Ward, Sholapur.
	8. D-Ward, Sholapur.
	9. E-Ward, Sholapur.
	10. F-Ward, Sholapur.
	11. Collection Circle, Sholapur.
	12. I.T.O. Barsi.
	13. S.S.C., Sholapur.
	14. S.S.C. II, Poona.
	15. Q-Ward, Poona.
	16. T-Ward, Poona.
	17. U.Ward, Poona.
	18. Salaries & Refunds CircleI Poona.
	19. Salaries & Refunds Circle II, Poona.
	20. Salaries & Refunds Circle III, Poona.
	21. Salaries & Refunds Circle IV, Poona.
	22. G.H.Q., Circle I, Poona.
	23. G.H.Q. Circle II, Poona.
	24. G.H.Q. Circle III, Poona.
A.A.C., Kolhapur Range, Kolhapur.	1. A-Ward, Kolhapur.
	2. B-Ward, Kolhapur.
	3. C-Ward, Kolhapur.
	4. D-Ward, Kolhapur.
	5. E-Ward, Kolhapur.
	6. F-Ward, Kolhapur.
	7. G-Ward, Kolhapur
	8. H. Ward, Kolhapur.
	9. Collection Circle, Kolhapur.
	10. Collection Circle I, Kolhapur.
	11. I.T.O. Ichalkaranji.
	12. A-Ward, Ichalkaranji.
	13. B-Ward, Ichalkaranji.
	14. Collection Circle II, Kolhapur.
	15. S.S.C., Kolhapur.
	16. I.T.O. Ratnagiri.
	17. A-Ward, Sangli.
	18. B-Ward, Sangli.
	19. C-Ward, Sangli.
	20. D-Ward, Sangli.
	21. E-Ward, Sangli.
	22. Collection Circle, Sangli.

Where an Income-tax Circle/Wards or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeal arising out of assessments made in that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle/Ward of Districts or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 11th August, 1975.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary on account of creation of some new Wards/Circles and readjustment of jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners.

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1022 (F.No. 261/5/75-ITJ)].

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

का० आ० 4620.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, अधिसूचना सं० 924 (फा० सं० 261/13/75-आई टी जे) तारीख 30 मई, 1975 द्वारा यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 752 (फा० सं० 261/ 74-आई टी जे) तारीख 10 अक्तूबर, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

क्रम सं० 5 के सामने, स्तम्भ (1) और (2) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

रेंज तथा मुख्यालय	आय-कर सर्किल, वार्ड और जिले
(1)	(2)
5. विशेष रेंज, गोहाटी	(i) विशेष सर्किल, गोहाटी (ii) गोहाटी सर्किलों के क-वार्ड, अतिरिक्त क-वार्ड, ग-वार्ड, घ-वार्ड, विशेष वार्ड और सर्वेक्षण वार्ड

(1)	(2)
	(iii) विशेष सर्किल, शिलांग
	(iv) शिलांग सर्किल, शिलांग
	(v) वेसन सर्किल, शिलांग

यह अधिसूचना 16-8-1975 से प्रभावी होगी ।

(सं० 1044(फा० सं० 261/13/75-आई टी जे)

पी० मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August , 1975.

S.O. 4620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the Schedule appended to its Notification No. 752 (F. No. 261/10/74-ITJ) dated 10th October, 1974 as amended by Notification No. 924 (F. No. 261/13/75-ITJ) dated 30th May, 1975 namely ;

Existing entries under columns (1) and (2) against serial number 5 shall be substituted by the following entries namely:—

SCHEDULE

Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards & Districts.
(1)	(2)
5. Special Range, Gauhati	(i) Special Circle, Gauhati.
	(ii) A-Ward, Addl. A-Ward, C-Ward, D-Ward, Special Ward and Survey Ward of Gauhati Circles.
	(iii) Special Circle, Shillong.
	(iv) Shillong Circle, Shillong.
	(v) Salary Circle, Shillong.

This notification shall take effect from 16-8-1975.

EXPLANATORY NOTE

This amendment has become necessary consequent on creation of a new Income-tax Circle at Gauhati viz. Special Circle, Gauhati.

[No. 1044(F. No. 261/13/75-ITJ]

P. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

का० आ० 4621.—आय-कर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड निदेश करता है कि आय-कर आयुक्त दिल्ली-i, दिल्ली ii, iii, iv और v, नई दिल्ली की अधिकारिता में आने वाले सभी पूर्त धार्मिक न्यासों/संस्थाओं के मामलों (किसी अन्य आय-कर अधिकारी को धारा 127 के अधीन समनुदिष्ट मामलों को छोड़कर) की अधिकारिता आयकर अधिकारियों, न्यास सर्किल, में, निम्न प्रकार, निहित होगी :—

90GI/75—7

अनुसूची

1	2	3
1.	आयकर अधिकारी, न्यास सर्किल-i, नई दिल्ली	आय-कर आयुक्त, दिल्ली i, ii, iii, iv, और v, नई दिल्ली की अधिकारिता में आने वाले उन सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों/संस्थाओं के मामले, जिनका नाम अंग्रेजी के "ए" से "एम" तक के किसी अक्षर से आरम्भ होता है (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) ।
2.	आय-कर अधिकारी, न्यास सर्किल-ii, नई दिल्ली ।	आय-कर आयुक्त, दिल्ली i, ii, iii, iv और v, नई दिल्ली की अधिकारिता में आने वाले उन सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों/संस्थाओं के मामले, जिनका नाम अंग्रेजी के "एन" से 'जड' तक के किसी अक्षर से आरम्भ होता है (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) ।

यह अधिसूचना 8-8-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1021 (फा० सं० 187/10/75-ii (ए आई)]

के० आर० राघवन,
सचिव

New Delhi, the 7th August, 1975.

S.O. 4621.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of all previous notifications in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the jurisdiction over all charitable and religious trusts/institutions cases falling in the jurisdictions of the Commissionrs of Income-tax, Delhi-I, Delhi-II, III, IV & V, New Delhi (except the cases assigned under section 127 to any other Income-tax Officer) shall vest in the Income-tax Officer, trust Circle as under:—

SCHEDULE

1	2	3
1.	Income Tax Officer Trust Circle-I, New Delhi.	All Charitable and religious trusts institutions cases falling in the jurisdiction of the C.I.T. Delhi I, II, III, IV & V New Delhi, whose name commences with any one of the alphabets from A to M (both inclusive).
2.	Income Tax Officer Trust Circle-II, New Delhi.	All charitable and religious trusts /institutions cases falling in the jurisdiction of the C.I.T. Delhi-I, II, III, IV & V New Delhi, whose name commences with any one of the alphabets from N to Z (both inclusive).

This notification shall take effect from 8-8-1975.

[No. 1021 (F. No. 187/10/75-IT(AI)]

K. R. RAGHAVAN,
Secy.

बड़ौदा, 6 सितम्बर, 1975

का० आ० 4622.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं गुजरात राज्य, सूरत जिला

'भेस्तान' को भांडागार स्थान (बॅन्ड हाउसिंग स्टेशन) होने की घोषणा करता हूं।

[अधिसूचना 1-75 सं० VIII/48-8/सी०शु०/75-I]

एच०आर० सिएम, समाहर्ता

Baroda, the 6th September, 1975

S.O. 4622.—In exercise of the powers conferred on me by Section 9 of the Customs Act, 1962, I declare 'Bhestan', District Surat, in the State of Gujarat, to be a warehousing station.

[Notification No. 1—75 No. VIII/48-8/Cus/75-I]

H. R. SYIEM, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय : पूना

पूना, 16 अगस्त, 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 4623—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश कर हूं कि फाइल संख्या बी जी एन (30)-58/68/डी०ए०, दिनांक 27-12-1968 के अधीन जारी की गई, इस समाहर्तालय की अधिसूचना संख्या सी०ई०आर० 10/1968 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए।

सारणी (टेबल) के स्तम्भ 2 में से शब्द और अंक "173जी(4)" निकाल दिये जाएं।

[के०उ०शु० नियम सं० 3/1975 फा० सं० बी०जी०एन० (30)-31/डी०ए०/75]

POONA CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Poona, the 16th August, 1975

CENTRAL EXCISES

S.O. 4623.—In exercise of the powers vested in me under Rue 5 of Central Excise Rules, 1944, I order that the following amendment shall be made in this Collectorate Notification No. CER. 10/1968 issued under F. No. VGN(30)-53/68/TA dated 27-12-1968.

In the column 2 of the Table, the word and figure "173G(4)" shall be deleted.

[CER. No. 3/1975 F. No. VGN(30)-31/TA/75]

का० आ० 4624—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उपसमाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पूना को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-जी (4) के अधीन समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता हूं।

[के०उ०शु० नियम सं० 4/1975 फा० सं० बी जी एन(30)-31/डी० ए०/75]

जे०एम० वर्मा, समाहर्ता

S.O. 4624.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I empower the Deputy Collector, Central Excise, Poona to exercise the powers of Collector under Rule 173-G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[CER. No. 4/1975 F. No. VGN(30)-31/TA/75]

J. M. VERMA, Collector

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, एवं सीमा शुल्क समाहर्ता

कलकत्ता, 26 जुलाई, 1975

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

का० आ० 4625—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए मैं इस समाहर्तालय के उपसमाहर्ता को समाहर्ता के कार्यक्षमता को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 1944, नियम, 173-जी (4) के द्वारा प्राप्त, उचित सीमा तक उपयोग करने की अनुमति देता हूं।

[अधिसूचना सं० 1/75 सी० सं० IV(16)9-के०शु०/ई०बी/72]

एन०एस० राय चौधरी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS,

Calcutta, the 26th July, 1975

CENTRAL EXCISE

S.O. 4625.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputty Collectors of Central Excise of this Collectorate, to exercise, within their respectlve jurisdictions, the powers of the Collector under Rule 173-G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[Notification No. 1/75 C. No. IV(16)9-CE/WB/72]

N. N. ROYCHOUDHURY, Collector

कलकत्ता, 19 अगस्त, 1975

का० आ० 4626.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 5, सन् 1944 के अधीन प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए नीचे की तालिका के कालम 4 के अधिकारियों को समाहर्ता के कार्य-क्षमता, जो द्वितीय कालम में व्यक्त हैं और उनसे सम्बन्धी नियम तृतीय कालम में व्यक्त है, के उचित उपयोग की अनुमति देता हूं।

तालिका

क्रम सं०	कार्य क्षमता का स्वरूप	नियम सं०	जिसको सौंपा गया है
1.	प्रथम आवेदन पत्र को विशेष क्रिया विधि के लिए पूर्ण अथवा संक्षिप्त अवधि के लिए स्वीकार करना।	96 जेड ओ(1) और 96 जेड ओ(2)	अधीक्षक
2.	ऐसे उत्पादक को स्वीकृत क्रिया विधि का उपयोग समयानुसार न करने के और बिना किसी उचित सूचना के ऐसे कार्य में रत हों, उन्हें ऐसी क्रिया विधि के अधीन कार्य करने से रोकना।	96 जेड ओ (3)	सहायक समाहर्ता
3.	(ए) फार्म ए० एस० पी० में नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करना	96 जेड ओ (4)	अधीक्षक
	(बी) नवीनीकरण के लिए देर से दिए गए ए०एस०पी० को क्षमा करना	समान	(i) अधीक्षक 15 दिन तक (ii) सहायक समाहर्ता 15 दिन से अधिक
4.	फार्म ए० आर० 11 के हटाने के लिए देर से दिए गए आवेदन पत्र को क्षमा करना और माहवारी जमा देने में हुई देर को क्षमा करना	96 जेड क्यू (2)	(i) अधीक्षक प्रत्येक केस में 5 दिन तक (ii) सहायक समाहर्ता उपरोक्त (i) से अधिक देरी को।

2. समाहर्तालय की अधिसूचना सं० 3/1974 दिनांक 27 अगस्त 1974 को रद्द किया जाता है।

[अधिसूचना सं० 2/1975 सं० सी० iv(16)9/सी०ई०/72]

एच० एल० बनर्जी, समाहर्ता

Calcutta, the 19th August, 1975

S.O. 4626.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I empowr the officers of the rank mentioned in Column 4 of the Table below to excise within their respective jurisdiction the powers of the Collector mentioned in Column 2 under rules mentioned against each in column 3 of the said table.

TABLE

Sl. No.	Nature of power	Rule No.	To whom delegated
1	2		3
1.	To accept first application for the special procedure for a full period or for a shorter period.	96 zo (1) and 96 zo (2)	Superintendent.
2.	To preclude a manufacturer from working under the special procedure for failure to give proper notice for not availing of such procedure during the period for which permission has been granted to him.	96 zo (3)	Assistant Collector.
3.	(a) To acept renewal application in form ASP.	96 zo (4)	Superintendent.
	(b) To condone delay in submission of ASP for renewal.	-Do.-	(i) Superintendent for condoning delays not exceeding 15 days. (ii) Assistant Collector for condoning delays exceeding 15 days.
4.	To condone delay in submission of application for removal in form A.R. 11 and to condone delays in making monthly deposits.	96 zq(2)	(i) Superintendent for condoning delays not exceeding 5 days in each case. (ii) Assistant Collector of the delay exceeds the limits under (i) above.

2. Collectorate Notification No. 3 /1974 dated the 27th August, 1974 is hereby rescinded.

[Notification No. 2/1975-C No. IV(16)9-CE/72]

H. L. BANERJEE, Collector

कार्यालय आयकर आयुक्त

भोपाल, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4627.—उन समस्त धन कर निर्धारितियों के नाम जिनका कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान रुपये 10 लाख से अधिक कुल धन पर निर्धारण किया गया है - परिस्थिति के लिये कालम (i); व्यष्टि के लिये "आई" ; निर्धारण वर्ष के लिए कालम (ii); विवरणी में दर्शाये गये कुल धन के लिये कालम (iii); कुल धन जिन पर निर्धारण किया गया के लिये कालम (iv) ; देय कर के लिये कालम (v) ; भुगतान किये गये कर के लिये कालम (vi) ।

अनुसूची

अनुक्रमांक (i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1. श्री रामगोपाल मुचल, एम० टी० सी० एम०, इंदौर					
1. हि०अ०कु०	1969–70	9,49,186	12,65,581	13,140	8,100
2. "	1968–69	11,22,733	12,22,676	10,953	10,953
2. श्रीमती गायत्री देवी बिरला, बिरला नगर, ग्वालियर					
3. व्यष्टि	1973–74	12,23,100	12,26,643	21,140	20,360
4. "	1974–75	15,67,840	15,67,840	32,594	32,594

[एफ० नं० सी० एम० (धा०क० 9/74–75]

Bhopal, 15th September, 1975

S.O. 4627.—Names of all Wealth Tax Assessees Assessed on net Wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the financial year 1974-75. (i) stands for Status—'I' for Individual; (ii) for Assessment year; (iii) Net wealth returned; (iv) Net wealth assessed; (v) Tax payable and (vi) for Tax paid.

SCHEDULE

Sl. No. (i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
(1) Shri Ramgopal Muchal, M.T.C.M., Indore.					
1. H.U.F.	1969-70	9,49,186	12,65,581	13,140	8,100
2. Do.	1968-69	11,22,733	12,22,676	10,953	10,953
(2) Smt. Gayatridevi Birla, Birla Nagar, Gwalior.					
3. Ind.	1973-74	12,23,100	12,26,643	21,140	20,360
4. Do.	1974-75	15,67,840	15,67,840	32,594	32,594

[F. No. C.S. (WT)9/74-75].

का० आ० 4628.—उन समस्त व्यक्तियों और हिन्दू संयुक्त परिवारों के नाम जिनका कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये रुपये एक लाख से अधिक आय पर कर निर्धारण किया गया है। प्रास्थिति के लिए कालम (i), व्यष्टि के लिए – 'आई' हिन्दू संयुक्त परिवार के लिये 'एच', निर्धारण वर्ष के लिये कालम (ii) विवरणी में बताई आय के लिये कालम (iii) आय जिस पर निर्धारण किया गया, के लिये कालम (iv) देय कर के लिये कालम (v) प्रदत्त कर हेतु कालम (vi)।

अनुसूची

अ० क्र० (i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
(1) श्री मोह० अजीज पार्टनर मे० कालेखां मो० हनीफ, इब्राहीमपुरा, भोपाल					
1. व्यष्टि	1969–70	3,85,165	3,86,690	12,626	—
2. तदैव	1970–71	5,02,840	5,00,160	—	—
(2) श्री एन० ए० बुहारीवाला, 142 सिमरोल रोड़, मऊ					
3. व्यष्टि	1972–73	18,240	1,03,360	62,891	48,470
(3) श्री जितेन्द्र मगनलाल द्वारा मै० फार्माकाल, 287 जवाहर मार्ग, इंदौर					
4. व्यष्टि	1972–73	95,985	1,01,000	61,805	57,213
5. तदैव	1973–74	1,04,937	1,09,840	69,791	64,222
6. तदैव	1974–75	1,15,894	1,14,110	72,646	72,641
(4) स्वर्गीय श्री० जी० ठाकुर द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्रीनिवास ठाकुर द्वारा मै० ठाकुर सौदेकर एंड कं०, खातेगांव					
7. व्यष्टि	1972–73	90,341	1,17,940	81,880	52,210
(5) श्री सुबोध कुमार गुप्ता पार्टनर, मैसर्स मंदसौर सीमेंट पाइप फैक्टरी, मन्दसौर					
8. व्यष्टि	1972–73	1,01,481	1,04,600	64,952	64,952

अनुसूची – II

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन उन समस्त फर्मों व्यष्टियों के संगम और कंपनियों के नामों का प्रकाशन जिनका वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये दस लाख रुपये से अधिक आय पर कर निर्धारण किया गया है।

शून्य

[एफ० नं० एस० 9/74–75/वि० अ० शा०]

S.O. 4628:—Names of all individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income of more than Rs. one lakh during the financial year 1974-75: (i) is for status-'I' for Individual, 'H' for H. U.F.; (ii) for Assessment year; (iii) for Income returned (iv) for Income assessed; (v) Tax payable and (vi) for Tax paid.

SCHEDULE

(1) Shri Mohd. Aziz P/o M/s. Kalekhan Mohd. Hanif, Ibraheimpura, Bhopal .

Sl. No. (i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1. Ind.	1969-70	3,85,165	3,86,690	12,626	—
2. Do.	1970-71	5,02,840	5,00,160	—	—
(2) Shri N.A. Buhariwala, 142, Simrol Road, Mhow.					
3. Ind.	1972-73	18,240	1,03,360	62,891	48,470
(3) Shri Jitendra Maganlal C/o M/s. Farmakal, 287, Jawahar Marg, Indore.					
4. Ind.	1972-73	93,985	1,01,000	61,805	57,213
5. Do.	1973-74	1,04,937	1,09,840	69,791	64,222
6. Do.	1974-75	1,15,884	1,14,110	72,646	72,641
(4) The Late V.G. Thakur through L/H Shriniwas Thakur C/o. M/s. Thakur Saudekar & Co., Khategaon.					
7. Ind.	1972-73	90,341	1,17,940	81,880	52,210
(5) Shri Subodhkumar Gupta P/o. Mandsaur Cement Pipe Factory, Mandsuar.					
8. Ind.	1972-73	1,01,481	1,05,600	64,952	64,952

SCHEDULE-II.

Publication of names u/s 287 of the Income-tax Act, 1961, of All firms, A.O.P.s & Commpanies. assessed on income of over Rs. ten lakh during the financial year 1974-75.

NIL

[F.No. S-9/74-75/SIB]

का० आ० 4629.—उन सभी धन कर निर्धारितियों के नाम जिनका कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान रुपये 10 लाख से अधिक कुल धन पर निर्धारण किया गया है – व्यक्तियों के लिये कालम (i) ; व्यष्टि के लिये "आई"–; निर्धारण वर्ष के लिये कालम (ii) ; विवरणी में दर्शाये गये कुल धन के लिये कालम (iii) ; कुल धन जिस पर निर्धारण किया गया के लिये कालम (iv) ; देय कर के लिये कालम (v) ; भुगतान किये गये कर के लिये कालम (vi) ;

अनुसूची

(1) भूतपूर्व महारानी मेनकाराजे पवार, देवास,

अनुक्रमांक (i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1. व्यष्टि	1969–70	16,62,322	19,55,435	30,883	30,883
2. "	1970–71	18,96,225	21,88,733	37,652	37,652
3. "	1971–72	21,84,113	23,61,078	67,055	67,055
4. "	1972–73	5,24,200	21,89,430	85,174	76,360
(2) भूतपूर्व महाराजा तुकोजीराव होल्कर, इंदौर					
5. व्यष्टि	1971–72	20,86,966	21,95,088	45,626	45,626
6. "	1972–73	21,50,125	22,35,000	66,684	66,684
7. "	1973–74	22,24,087	22,91,100	70,264	70,264
(3) श्री भरतकुमार कान्तीलाल, नेहरूपारा, रायपुर					
8. व्यष्टि	1973–74	13,98,410	12,33,930	22,020	22,020

[एफ० नं० सी० एम० (घ० क०) 9/74-75]

के० जगन्नाथन, आयकर आयुक्त

S.O. 4629.—Names of all Wealth Tax Assessees Assessed on net Wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the financial year 1973-74. (i) stands for Status 'I' for Individual; (ii) for Assessment year ; (iii) Net Wealth returned; (iv) Not wealth assessed (v) Tax payable and (vi) for Tax paid.

SCHEDULE

(1) H.H. Menakaraje Pawar, Dawas.

Sl. No.	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	Indl	1969-70	16,62,322	19,55,435	30,883	30,883
2.	Do.	1970-71	18,96,225	21,88,733	37,652	37,652
3.	Do.	1971-72	21,84,112	23,61,078	67,055	67,055
4.	Do.	1972-73	5,24,200	21,89,430	85,174	76,360
	(2) H.H. Tukojirao Holkar, Indore.					
5.	Ind.	1971-72	20,86,966	21,95,088	45,626	45,626
6.	Do.	1972-73	21,50,125	22,35,000	66,684	66,684
7.	Do.	1973-74	22,24,087	22,91,100	70,264	70,264
	(3) Shri Bharat Kumar Kantilal, Maharpara, Raipur.					
8.	Ind.	1973-74	13,98,410	12,33,930	22,020	22,02

[F. No. C.S. (WT)/9/74-75]

K. JAGANNATHAN, Commissioner

धनकर आयुक्त कार्यालय,

पटियाला, 29 सितम्बर, 1975

(धनकर)

का०आ० 4630.—धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 42-क के अधीन ऐसे सभी करदाताओं के नाम तथा विशिष्टियां, जिनका शुद्ध धन वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया गया है (i) हैसियत के लिये 'आई' व्यष्टि के लिये 'एच' हि० अवि०कु० के लिये (ii) निर्धारण वर्ष के लिये (iii) दी गई धन विवरणी के लिये/निर्धारित धन के लिये तथा (iv) करदाता द्वारा संदेय कर/करदाता द्वारा संदत्त कर के लिये है।

1. श्री देविन्दर सिंह गरचा, एम०ए०एल०एल०बी०, संसद सदस्य, सराभा नगर, लुधियाना (i) व्यष्टि (ii) 73-74 (iii) 1247890/1303032 (iv) 27350/273501.

2. श्री जे०के० सेठी, मालिक सन्त राम एण्ड सन्ज (जगदेश्वर), 808, इण्डल० एरिया-बी, लुधियाना (i) व्यष्टि (ii) 73-74 (iii) 977956/1001909 (iv) 15057/1291।

3. सरदारनी भगवन्त कौर, मार्फत दीवान जगदीश चन्दर, एडवोकेट, सिविल लाइन्ज, लुधियाना (i) व्यष्टि (ii) 73-74 (iii) 1000000/1160000 (iv) 19800/10,000

4. श्री इन्दर मोहन सिंह ग्रेवाल, मार्फत मैसर्ज अपर इण्डिया स्टील (प्रा०) लि०, लुधियाना (i) व्यष्टि (ii) 72-73 (iii) 999490/1036706 (iv) 15632/15632

[फा० सं० रैक/प्रकाशन/धनकर]

वी०पी० गुप्ता, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX

Patiala, the 29th September, 1975

(WEALTH-TAX)

S.O.4630.—Names and particulars of all the assessees who have been assessed to net wealth over Rs. 10 lakhs during the financial year 1974-75 u/s 42 -A of the W. Tax Act, 1957 (i) stands for status 'I' for individual, 'H' for HUF, (ii) for assessment year (iii) for wealth returnd/wealth assessed and (vi) for tax payable by assessee/tax paid by the assessee.

1. Sh. Devinder Singh Carcha, M.A.LL.B., M.P. Sarabha Nagar, Ludhiana, (i) I, (ii) 73-74, (iii) 1247890/1303032, (iv) 27350/27350.

2. Sh. J. K. Sethi, Prop. Sant Ram & Sons (Jogdeshwar) 808, Indl. Area-B, Ludhiana (i) I, (ii) 73-74, (iii) 977956/1001909, (iv) 15057/1291.

3. Sardarni Bhagwant Kaur, C/o Dewan Jagdish Chander, Advocate, Civil Lines, Ludhiana, (i) I, (ii) 73-74, (iii) 1000000 1160000, (iv) 19800/10000.

4. Shri Inder Mohan Singh Grewal, C/o M/s. Upper India, Steel (P) Ltd., Ludhiana (i) I, (ii) 72-73, (iii) 999490/1036706 (iv) 15632/15632.

[F. No. Rec/Publication/W.T.]

V. P. GUPTA, Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

का०आ० 4631.—सर्वश्री महेन्द्र ओवन लि०, 118, बम्बई पूना रोड, पिंपरी, पूना-18 को यू०के० भारत अनुरक्षण ऋण 1972 के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये संलग्न सूची के अनुसार संघटकों के आयात के लिये 2,99,100 रुपए का एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2197209/आर/एम एल/50/एच/35-36, दिनांक 26-3-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार

पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति उनके द्वारा अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि सीमाशुल्क प्रति बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाने के बाद और 57,898 रुपए शेष छोड़ कर 2,41,202 रुपए के लिये उपयोग करने बाद अस्थानास्थ हो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/डी/2197209, दिनांक 26-3-74 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है और निदेश देता हूं कि उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये। मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है। आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या ट्रैक्टरस 10 (3—5)/72-73/आर०एम० 6]

ए०एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1975

S.O. 4631.—M/s. Mahindra Owen Ltd., 148 Bombay Poona Road, Pimpri, Poona-18 were granted licence No. P/D/2197209/R/ML/50/H/35-36, dated 26-3-74 for Rs. 2,99,100 under U.K.-India Maintenance Loan 1972 for import of Components as per list attached to it. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the ground that original Customs Copy has been misplaced by them. It has further been reported by the licensee that the Customs Copy has been misplaced after having been registered with Bombay Customs Authority and that the same has been utilised for an amount of Rs. 2,41,202 leaving a balance of Rs. 57,898.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Customs Purposes Copy of the licence No. P/D/2197209, dated 26-3-74 has been misplaced/lost and directs that duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to them. The Original Customs Purposes Copy is cancelled. Duplicate Customs Purposes Copy of the Import licence is being issued separately.

[No. *Tractor. 10(3—5)/72-73/RM6*]

A. N. CHATTERJI, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का०आ० 4632.—सर्वश्री एसोसिएटिड जर्नल लिमिटिड लखनऊ, को 48190/- रुपये (अड़तालीस हजार एक सौ नब्बे रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1359678/सी/एक्स एक्स/43/एच/33-34 दिनांक, 21-6-72 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि, मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति यूनाइटिड कमर्शियल बैंक कलकत्ता के पास पंजीकृत करवाई गई थी और उसका अंशतः उपयोग किया गया था। इसका 25464/- रुपये के लिये उपयोग कर लिया गया था और इसमें 22726/- रुपये शेष उपलब्ध था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ आयुक्त न्यायालय लखनऊ द्वारा प्रमाण पत्र सहित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तदनुसार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिये यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री एसोसिएटिड जर्नल्स लि०, लखनऊ को जारी किये गए लाइसेंस सं० पी/ए/1359678/सी/एक्स एक्स/43/एच/33-34 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को इस के द्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: 67-वी/ए-12/71-72/एन पी एस]

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1975

S.O. 4632.—M/s. Associated Journals Ltd., Lucknow were granted an import licence No. P/A/1359678/C/XX/43/H/33-34, dated 21-6-72 for Rs. 48190 (Rupees Forty eight Thousand and One Hundred and ninety only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control Copy was registered with the United Commercial Bank, Calcutta and utilised partly. It was utilised for Rs. 25464 and the balance available on it was Rs. 22726.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Commissioner of Affidavit Civil Court, Lucknow. I am accordingly satisfied that the Original Exchange Control Purposes Copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Exchange Control Purposes Copy of licence No. P/A/1359678/C/XX/43/H/33-34, dated 21-6-1972 issued to M/s Associated Journals Ltd. Lucknow, is hereby cancelled.

A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. 67-V/A-12/71-72/NPS]

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1975

का०आ० 4633.—श्री ललित ओबराय, राज निकेतन, 5, कल्याणी पथ, रुद्रपुर (नैनीताल) को गैर-निषेध बोर के एक रिवाल्वर के आयात के लिये 1000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) मूल्य का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या: पी/जे/3048493, दिनांक 29-3-75 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था। इस तर्क के समर्थन में उसने एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि

मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या: पी/जे/3048493, दिनांक 29-3-75 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिये। मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द किया जाता है।

[संख्या: 315-4/एल-3/एम-75/एडहाक/1213]

एन०सी० कांजीलाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 27th September, 1975

S.O. 4633.—Shri Lalit Oberai, Raj Niketan, 5 Kalyani View Rudrapur (Nainital) was granted CCP No. P/J/3048493 dated 29-3-75 for Rs. 1000 (Rupees one thousand) for the import of one N.P. Bore Revolver. He has applied for a duplicate copy of the C.C.P. on the ground that the original C.C.P. has been lost/misplaced. It is further stated that the original C.C.P. was not registered with any Customs House and not utilised. In support of this contention, he has filed an affidavit I am satisfied that the original CCP No. P/J/3048493 dated 29-3-75 has been lost/misplaced and direct that a duplicate C.C.P. should be issued to the applicant. The original CCP is cancelled.

[File No. 315-IV/L-3/AM-75/Adhoc/1213]

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4634.—सर्वश्री हेग्डे एंड गोले लि०, श्रीशाइला, कणकपुरा रोड, बंगलौर-11 को विदेशी आर्थिक सहयोग अंशदान के मद्दे 16,59,050 रुपए (सोलह लाख, उनसठ हजार पचास रुपए मात्र) के लागत बीमा भाड़े मूल्य के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2068292/ए/एस एच/48/एच/37-38/सी जी-4, दिनांक 12-9-73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति बैंकर्स के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई है। यद्यपि शेष अप्रयुक्त 6,97,543 रुपए (छः लाख सत्तानवें हजार पांच सौ तेतालीस रुपए मात्र) को छोड़ कर विदेशी सहयोग साम्य भाग के मद्दे 9,61,507 रुपये (नौ लाख इकसठ हजार पांच सौ सात रुपए मात्र) मूल्य का आयात प्रभावी कर दिया गया है। विदेशी आर्थिक सहयोग अर्थात् सर्वश्री बर्ना गोले एस० ए० स्विटजरलैण्ड को अब ऋणस्थगन के अन्तर्गत बताया गया है।

2. उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने नोटरी बंगलोर नगर के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है/खो गई है। इसलिये यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री हेग्डे एंड गोले लि० को जारी किये गए आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2068292 दिनांक 12-9-73 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति इस के द्वारा रद्द की जाती है।

3. आवेदक को उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: —सी जी-4/13(13)/73-74]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1975

S.O. 4634.—M/s. Hegde and Golay Ltd., Shreeshyla, Kanakpura Road, Bangalore-11 were granted import licence No. P/C/2068292/A/SH/48/H/37-38/CG. IV dated 12-9-73 for a c.i.f. value of Rs. 16,59,050 (Rupees sixteen lakhs, fiftynine thousand and fifty only) against foreign financial collaborators share subscription. They have applied for issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that original Exchange Control Purposes copy has been misplaced/lost. It has further been stated that the original Exchange Control purposes copy has not been registered with the Bankers though import of the value of Rs. 9,61,507 (Rupees Nine lakhs sixtyone thousand five hundred and seven only) are stated to have been effected against the foreign collaborators share of equity leaving an un-utilised balance of Rs. 6,97,543 (Rupees six lakhs, ninetyseven thousand, five hundred and fortythree only). The foreign financial collaborators viz. M/s. Bernad Golay SA, Switzerland are stated to be under Moratorium now.

2. In support of the above, the applicant has filed an affidavit duly sworn before Notary, Bangalore city. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy of the said import licence has been misplaced/lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Purposes Copy of the Import licence No. P/C/2068292, dated 12-9-1973 issued to M/s. Hegde and Golay Ltd., is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said Import licence is being issued to the appilcants separately.

[No. CG. IV/13(13)/73-74]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4635.—परियोजना अधिकारी, भारत-जर्मन नीलगिरि विकास परियोजना, उटकमंड (तमिलनाडु) को पहले ही जर्मनी संघीय गणराज्य से आयात की गई जीपों के फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये 1000 रुपये मूल्य के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिये सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या: जी/जे/3041903/एन, दिनांक 27-12-1974 प्रदान किया गया था। कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या: एफ-6 (12)/74-प्रोजेक्ट्स, दिनांक 27-6-1975 द्वारा इस कार्यालय को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रति के लिये इस आधार पर सम्पर्क स्थापित किया है कि उनसे उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है।

कृषि निदेशक, तमिलनाडु राज्य, मद्रास ने परियोजना अधिकारी/उटकमण्ड के निमित्त आवश्यक शपथपत्र/घोषणा-पत्र, दाखिल किया है जिसके अनुसार उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया है और उसका बिलकुल उपयोग नहीं किया गया है।

घोषणा पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट मिलने पर या उपलब्ध होने पर रिकार्ड के लिये जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा। मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट माल सूची के साथ खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिये। मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या: 7/ए जी-141/74-75/एम एल-1/881]

नवरेखा शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 9th October, 1975

CANCELLATION ORDER

S.O. 4635.—The Project Officer, Indo-German Nilgiris Development Project Ootacamund (Tamil Nadu) were granted CCP No. G/J/3041903/N dated 27-12-1974 for c.i.f. value of Rs. 1,000 for the importation of spaces for the Jeeps already imported from Federal Republic of Germany. The Ministry of Agriculture & Irrigation, New Delhi vide their letter No. F. 6(12)/74-Projects dated 27th June, 1975 have approached this office for grant of a duplicate CCP for the aforesaid CCP on the ground that the original one has been lost by them.

The necessary affidavit/declaration has been furnished by the Director of Agriculture, Government of Tamil Nadu Madras on behalf of the Project Officer, Ootacamund, according to which the aforesaid CCP has not been registered with any Customs House and not utilised at all. It has also been incorporated in the declaration that if the said CCP traced or found later on it will be returned to the issuing authority for record. I am satisfied that the original CCP alongwith the list of goods has been lost/misplaced and direct that duplicate should be issued to the applicant. The original CCP is hereby cancelled.

[File No. 7/AG-141/74-75/ML. I/881]

NAV REKHA SHARMA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4636.—सर्वश्री सेशासाई पेपर एंड बोर्ड लि०, पल्लीपालयम, कावेरी, आर० एस० पी० ओ, एरोड-7 (तमिलनाडु) को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत कागज एवं कागज बोर्ड के विनिर्माण के लिये स्थापित मशीनरी के लिये स्वीकृत फालतू पुर्जों के आयात के लिये 8,08,000 रुपए मात्र का एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2194264/सी/एक्स एक्स/47/एच/35-36/पेपर दिनांक 7-8-1973 स्वीकृत किया गया था।

फर्म ने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि उन के द्वारा मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह प्रतिवेदित किया गया है कि लाइसेंस में शेष अप्रयुक्त 5,29,881 रुपए मात्र थे। लाइसेंस मद्रास सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2194264 दिनांक 7-8-1973 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये। मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या पेपर/4(1)/73-74/आर एम 2]

आ० वी० चुनकत, उप-मुख्य नियंत्रक]

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4636.—M/s. Seshasayee Paper and Boards Limited, Pallipalayam, Cauvery R.S.P.O., Erode-7 (Tamil Nadu) were granted Import Licence No. P/D/2194264/C/XX47/H/35-36/Paper dated 7-8-1973 under G.C.A. for Rs. 8,08,000 only for import of permissible spare parts of Machinery installed for the manufacture of Paper and Paper Boards.

2. The firm have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an un-utilized balance of Rs. 5,29,881/- only. The licence was registered with Madras Customs.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/D/2194264 dated 7-8-1973 has been lost and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued sepaartely.

[No. Paper/4(1)/73-74/RM II]

I. V. CHUNKATH, Dy. Chief Controller of Import and Export

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

बम्बई, 9 जनवरी, 1975

का०आ० 4637.—सर्वश्री एम०एम० केमिकल्स, 22-सी राजेन्द्र नगर, इन्दौर को निम्नलिखित लाइसेंस जारी किये गए थे :—

क्रम सं०	लाइसेंस सं० एवं दिनांक	मूल्य	माल का विवरण
1.	पी/एस/1362851/15-11-72	32500 रुपये	एन्टीमोनी आक्साइड पाराएमिनो फिनोल
2.	पी/एस/1362852/15-11-72	16250 रुपये	एसिटिक एनिहाइड्रोमाइड
3.	पी/एस/1362853/15-11-72	16250 रुपये	ग्लिसरीन

ये लाइसेंस निम्नलिखित शर्त पर जारी किये गए थे :—

"यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इसके अन्तर्गत आयातित माल की सभी मदों का उपयोग उस आवेदन पत्र में दिखाए गए पते पर लाइसेंसधारक के कारखाने में किया जाएगा जिसके मद्दे लाइसेंस जारी किया गया है और केवल उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाएगा जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया है या किसी अन्य के विनिर्माण कर्ता एकक के कारखाने में संसाधित किया जाए, किन्तु इसके किसी भी भाग को किसी अन्य पार्टी को बेचा अथवा उपयोग अथवा अन्य किसी विधि से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन किसी अन्य के कारखाने में संसाधित किये गए ऐसे माल का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा लिये गए विनिर्माण कार्यों में किया जाएगा। लाइसेंसधारी इस लाइसेंस के मद्दे आयातित माल के उपभोग और उपयोग का निर्धारित विधि से सही लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी, प्रयोजनक प्राधिकारी या अन्य किसी भी सम्बद्ध प्राधिकारी को उनके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।"

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या 1/153/73/ए यू/इन्फ/3191 दिनांक 10-12-1973 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 15 दिन के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किये गए उक्त

लाइसेंसों को धारा 9 उपधारा (ए) एवं (सी सी) के अनुसार क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हें इस आधार पर कि सर्वश्री कीर्ति मशीनरी वर्क्स, बम्बई का जिसे सर्वश्री एम० एम० कैमिकल्स द्वारा पक्का आदेश जारी किया गया था कुछ पता नहीं है।

3. सर्वश्री एम० एम० कैमिकल्स, इन्दौर के कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया है।

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि उन्होंने लाइसेंस धोखे से प्राप्त किये हैं और वे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे कि जिस के लिये जारी किये गए हैं।

5. ऊपर की कंडिका में जो कुछ बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अन्यथा रूप से अप्रभावित किये जाने चाहिये। इसलिये अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण आदेश 1955 की धारा 9 उपधारा (ए) एवं (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री एम० एम० केमिकल्स इन्दौर के नाम में जारी किये गए लाइसेंस सं० पी/एस/1362851 मूल्य 32,500 रुपये पी/एस/1362852 मूल्य 16,250 रुपये एवं पी/एस/1362853 मूल्य 16,250 रुपये को एतद्द्वारा रद्द करता है।

[सं० 1/153/73/ए०यू०/इन्फ/208]

एस० डी० मराठे, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

Bombay, the 9th January, 1975

S.O. 4637.—The following licences were issued to M/s. M. M. Chemicals, 22-C Rajendra Nagar, Indore :

Sl. No.	Licence No. & Date	Value in Rs.	Description of goods
1.	P/S/1362851/15-11-72.	32,500	Antomony Oxide, Para Amino Phenol.
2.	P/S/1362852/15-11-72.	16,250	Acetic Anhyrine Bromine
3.	P/S/1362853/15-11-72.	16,250	Glycerine.

These licences were issued subject to the following condition :

"This licence is issued subject to the condition that all items of goods imported under it shall be used only in the licence holder's factory at the address shown in the application against which the licence is issued and for the purpose for which the licence is issued or may be processed in the factory of another manufacturing unit, but no portion thereof shall be sold to any other party or utilised or permitted to be used in any other manner. The goods so processed in another factory shall, however, be utilised in the manufacturing processes undertaken by the licensee. The licensee shall maintain a proper account of consumption and utilisation of the goods imported against the licence in the prescribed manner and produce such account to the licensing authority, sponsoring authority, or any other authority concerned, within such time as may be specified by such authority".

2. Thereafter a show cause notice No. 1/153/73/AU/Enf/3191 dated 10-12-1973 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that according to a report received from the Director of Industries, Bhopal the firm M/s. Kirti Machinery Works, Bombay on whom firm order for machinery was stated to have been placed by M/s. M. M. *Chemicals is not traceable at the given address,* in terms of Clause 9, sub-clauses (a) and (cc).

3. M/s. M. M. Chemicals, Indore have not replied to the Show Cause Notice.

4. The undersigned has carefully examined the case and has come to the conclusion that they have obtained the licences by frandulant means and the licences will not serve the purpose for which they have been granted.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in her under clause 9-sub-clauses (a) and (cc) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the licence Nos. P/S/1362853 for Rs. 32,500 P/S/1362852 for Rs. 16,250 and P/S/1362853 for Rs. 16,250 all dated 15-11-1972 issued in favour of M/s. M. M. Chemicals, Indore.

[No. 1/153/73/AU/Enf/208]

S. D. MARATHE, Dy. Chief Controller.

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का०आ० 4638.—सर्वश्री एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं० 2281, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली को अप्रैल-मार्च, 74 अवधि के लिये सामान्य क्षेत्र से घड़ियों के पुर्जों के आयात के लिये संस्थापित आयातक के रूप में 1250 रुपये के लिये एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/ई/0223492, दिनांक 24-8-73 स्वीकृत किया गया था।

2. पार्टी ने यह बताया है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अप्रैल-मार्च, 1975 अवधि के लिये आवृत्ति प्रचालन के लिये बिलकुल उपयोग किये बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उसी को रद्द करने के लिये अनुरोध किया है। पार्टी ने उपर्युक्त ब्यान के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण, नियम एवं क्रियाविधि हैंड बुक, 1975-76 की कंडिका 320 में यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 के धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस की उक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि हैंड बुक, 1975-76 की कंडिका 320(4) की व्यवस्था के अनुसार अप्रैल-मार्च, 75 अवधि के लिये सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आवृत्ति प्रचालन के आधार पर प्रयोग के लिये उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये।

[संख्या: 308/4/101/एएम-74/म्यूएल/सीएलए/381]

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 29th Sept. 1975

S.O. 4638.—M/s. Export Trading Co. 2281, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-5 were granted licence No. P/E/0223492 dated 24-8-73 for Rs. 1250/- on G.A. for import of parts of Watches for AM-74 period as an Established Importer.

2. The party have intimated that the Exchange Control purpose copy of the above licence has been lost/misplaced without having been utilised at all or repeat operation for AM-75 period and have requested for cancellation thereof. Party have also requested to issue duplicate Exchange Control purpose

Copy of the same. The party have filed an affidavit in support of above statement as required vide para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76.

3. In exercise of the power conferred on me under section 9 (CC) of Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955, I Order the cancellation of the aforesaid Exchange Control Purpose copy of the licence.

4. The applicant is now being issued duplicate Exchange Control Purpose aforesaid licence for Rs. 1250 on G. A. for utilisation on Account of Repeat operation for AM-75 period in accordance with the provision of para 320(4) of the ITC Hand Book of Rules and Procedure 1975-76.

[F. No. 308-IV/101/AM-74/QL/CLA]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller.

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय, अहमदाबाद

आदेश

अहमदाबाद, 1 अगस्त, 1975

का०आ० 4639.--सर्वश्री सली केमिकल्स, पटेल इन्डस्ट्रियल इस्टेट ब्लाक नं० एच/2, दाभू रोड, प्रताप नगर, बड़ौदा-4 को पारा नाईट्रो फिनोल आदि के आयात के लिये 84490 (चौरासी हजार चार सौ नब्बे रुपये मात्र) का लासेंस सं० पी/एस/1380730 दिनांक 31-3-74 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति) के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/1380730 दिनांक 31-3-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 909/ई यू/25586/पी 31/ए एम 74/327]

डी० डि०' सूजा, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

Ahmedabad, the 1st August, 1975

S.O. 4639.—M/s. Suly Chemicals, Patel Industrial Estate, Block No. H/2, Dabho Road, Pratapnagar, Baroda-4 has been granted licence No. P/S/1380730 dated 31-3-74 for Rs. 84490 (Rupees Eighty four thousand four hundred and ninety only) for the import of Para Nitro Phenol etc.

They have applied for duplicate copy of the said licence (exchange purpose copy only) on the ground that the original Exchange Control purpose copy has been lost without having been registered with any Custom Authority.

In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the Exchange Purpose copy of the licence No. P/S/1380730 dated 31-3-74 has been lost and direct that the duplicate of the said Exchange purpose copy of the licence should be issued to the applicant firm.

The original Exchange Control purpose copy of the licence is cancelled.

[F. No. 909/EU/25586/P. 31/AM 74/SSI]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

(लोहा तथा इस्पात)

आदेश

फरीदाबाद, 15 जुलाई, 1975

का०आ० 4640.—सर्वश्री गेस्ट, कीन, विलियम लि० (संकी प्रिसीजन प्रेसिंग डिवीजन) लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भंडूप, बम्बई-78 को अप्रैल/मार्च, 71 अवधि के लिये यू०एस० सहायता के अन्तर्गत प्राइम माइल्ड इस्पात शीट्स एवं औजार तथा मिश्रित धातु इस्पात मदों के आयात के लिये 65,45,000 रुपये का बम्बई पंजीयन पत्तन के लिये एक आयात लाइसेंस संख्या: पी/डी/8541303/एस/ /37/डी-31-32, दिनांक 10-11-70 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने के बाद और उसका 53,40,396 रुपये के लिये आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या: 8541303, दिनांक 10-11-70 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को विषयाधीन आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति को रद्द कर अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये।

[संख्या: पी/जी० 2/एएम-71/इलैक्ट/2225]

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

(Iron & Steel)

ORDER

New Delhi, the 15th July, 1975

S.O. 4640.—M/s. Guest, Keen, Williams Ltd., (Sankey Precision Pressings Division) Lal Bahadur Shastri Marg, Bhandup, Bombay-78 were granted an import licence No. P/D/8541303/S/S/37/D/31-32 dated 10-11-70 for the items 'Prime Mild Steel Sheet' & 'Tool & Alloy Steel' for Rs. 65,45,000 under U.S. Aid for April/March 71 period with Port of Registration 'Bombay'. They have applied for issue of duplicate Customs Clearance Purpose Copy of this licence on the ground that the original C.C.P. Copy of the licence has been lost/misplaced after having been registered with Bombay Custom House and utilised partly by Rs. 53,40,396.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original C.C.P. Copy of licence No. 8541303 dated 10-11-70 has been lost/misplaced, and direct that the duplicate C.C.P. Copy should be issued to the applicant in cancellation of the original C.C.P. Copy of the import licence in question.

[No. P/G. 2/AM-71/Elect/2225]

आदेश

फरीदाबाद, 4 अगस्त, 1975

का०आ० 4641.—सर्वश्री ओमेगा ब्राइट स्टील कम्पनी लि०, प्लाट सं 109, सेक्टर 24, फरीदाबाद को "प्राइम हाई सल्फर फ्री कटिंग ब्लैक बार्स और प्राइम लेडिड फ्री कटिंग ब्लैक बार्स" मद के लिये कुल

40,000/- रुपये मूल्य के लिये निर्बाध उच्चतम सीमा के अधीन बम्बई पत्तन पर पंजीकरण की शर्त के साथ अप्रैल 72/मार्च 73 अवधि के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/8567368/सी/एक्स एक्स जे०/50/35-36 दिनांक 22-3-74 प्रदान किया गया था। पार्टी ने यह लाइसेंस पुनर्वैधीकरण के लिये प्रस्तुत किया था, परन्तु वह इस कार्यालय द्वारा भूल से रद्द कर दिया गया था।

उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूल आयात लाइसेंसों को रद्द करने इनकी अनुलिपि (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क निकासी प्रति) उपर्युक्त फर्म को जारी की जाए।

[संख्या: एन पी/ओ-5/ए एम/73/एच एम ई/3129]

के०एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

CANCELLATION ORDER

Faridabad, the 4th August, 1974

S.O. 4641.—M/s. Omega Bright Steel Co. Ltd. Plot No. 109, Sector 24, Faridabad were granted an import licence No. P/D/8567368/C/XX/J/50/35-36 dated 22-3-74 for the item "Prime High Sulphur Free Cutting Black Bars and Prime Leaded Free Cutting Black Bars" for a total value of Rs. 40,000/- under Free ceiling for April 72/March, 73 period with the Part of Registration as Bombay. This licence was submitted by the party for revalidation but inadvertantly, it was cancelled by this office.

In view of above a duplicate import licence (ECP & CCP Copies) may be issued to the above firm, in cancellation of the original licences.

[No. NP/O.5/AM/73/HME/3129]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर 1975

का० आ० 4642.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी ई एक्स से बी डी जैड तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

बी ई एक्स से बी डी जेड तक आर ओ यू का अर्जन

राज्य : गुजरात जिला : कायरा तालुका : मातार

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टर	ऐ आर ई	सेण्टियर
गोबलीज	394	0	01	75
	398/1	0	06	00
	398/2	0	04	25
	391	0	04	25
	401	0	00	50
	402	0	07	75
	405	0	04	25
	419/2	0	04	75

[सं० 12016/13/75-एल० एण्ड एल०]

टी० पी० सुब्रह्मनियम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Patroleum)

New Delhi, the 3rd October, 1975

S.O. 4642.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from BEX TO BDZ in Sibsagar Distt., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipelines under the land to the Competent Authority, *viz.* the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. From BEX to BDZ

State : GUJARAT District : KAIRA Taluka : MATAR

Village	Survey No.	Hactare	Arc	Centiare
Goblegs	394	0	01	75
	398/1	0	06	00
	398/2	0	04	25
	391	0	04	25
	401	0	00	50
	402	0	07	75
	405	0	04	25
	419/2	0	04	75

[No. 12016/13/75-L.& L.]

T. P. SUBRAHMANYAM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4643.—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट (उत्पादन पूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 19) की धारा

1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियत करती है कि उक्त अधिनियम 1976 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

[सं० पी० 16012/1/75-पी०एच० (वाल्यूम II)]
ए०पी० अत्रि, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 4643.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1976, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. P. 16012/1/75-P.H.(Vol. II)]
A. P. ATRI, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4644.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उप-नियम (2) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 949, दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में "एक वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष की अवधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा० सं० ए० वी० 11016/1/74 ए/ए० आर०/ 1937 (5)/1975]

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

ORDER

New Delhi, the 6th October, 1975

S.O. 4644.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 949, dated the 6th April, 1974, namely :—

In the said Order, in paragraph 2, for the words "a period of one year", the words "a period of two years" shall be substituted.

[F. No. Av. 11016/1/74-A/AR/1937(5)/1975]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1975

का० आ० 4645.—केन्द्रीय सरकार, विमानवहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के भूतपूर्व संचार विभाग की अधिसूचना सं० एम० 95, तारीख 13 सितम्बर, 1939 को अधिक्रान्त करते हुए, प्रमाणित करती है कि नीचे की सारणी के भाग 1, स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट उच्च संविदाकारी पक्षकार, उसके स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों की बाबत, वारसा में 12 अक्तूबर, 1929 को हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन से संबंधित कतिपय नियमों के एकीकरण अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार होंगे और यह भी प्रमाणित करती है कि उक्त सारणी के भाग 2 में उल्लिखित उच्च संविदाकारी पक्षकारों ने उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिए गए नियम 36 के उपबन्धों का स्वयं उपयोग कर लिया है।

सारणी

भाग 1

अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार	वे राज्यक्षेत्र जिनकी बाबत वे पक्षकार हैं
1	2
अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
अल्जीरिया	अल्जीरिया
अर्जेन्टाईना	अर्जेन्टाईना
आस्ट्रेलिया	पपुआ, नारफाक द्वीप, न्यूगिनी
आस्ट्रिया	आस्ट्रिया
बारबादोस	बारबादोस
बैल्जियम	बैल्जियम
ब्राजील	ब्राजील
बुलगारिया	बुलगारिया
बर्मा	बर्मा
बायलोरुसो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक	बायलोरुसो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
केमरुन	केमरुन
कनाडा	कनाडा
चीन लोक गणराज्य	चीन
कोलम्बिया	कोलम्बिया
कांगो लोक गणराज्य	कांगो लोक गणराज्य
क्यूबा	क्यूबा
साईप्रस	साईप्रस
जैकोस्लोवाकिया	जैकोस्लोवाकिया
दहोमी	दहोमी
डेनमार्क	डेनमार्क
डोमिनिकन प्रजातन्त्र	डोमिनिकन प्रजातन्त्र
इक्वेडर	इक्वेडर
मिस्र, अरब गणराज्य	मिस्र, अरब गणराज्य
इथोपिया	इथोपिया
फीजी	फीजी
फिनलैण्ड	फिनलैण्ड
फ्रांस	फ्रांस
गैबन	गैबन
जर्मनी प्रजातन्त्र गणराज्य	जर्मनी प्रजातन्त्र गणराज्य
जर्मनी संघ गणराज्य	जर्मनी संघ गणराज्य
यूनान	यूनान
ग्वाटेमाला	ग्वाटेमाला
गिनी	गिनी
हंगरी	हंगरी
आईसलैण्ड	आईसलैण्ड
भारत	भारत
इंडोनेशिया	इंडोनेशिया
ईराक	ईराक
आयरलैण्ड	आयरलैण्ड

1	2
इजराईल	इजराईल
इटली	इटली
आईवरी कोस्ट	आईवरी कोस्ट
जापान	जापान
जार्डन	जार्डन
कीनिया	कीनिया
कोरिया प्रजातन्त्र लोक गणराज्य	कोरिया प्रजातन्त्र लोक गणराज्य
लाओस	लाओस
लेबनान	लेबनान
लिबेरिया	लिबेरिया
लीबियन अरब गणराज्य	लीबियन अरब गणराज्य
लीकटेन्सताइन	लीकटेन्सताइन
लक्समबर्ग	लक्समबर्ग
मैडागास्कर	मैडागास्कर
माली	माली
मरिटानिया	मरिटानिया
मैक्सिको	मैक्सिको
मंगोलिया	मंगोलिया
मोरक्को	मोरक्को
नेपाल	नेपाल
नीदरलैण्ड्स अधिराज्य	नीदरलैण्ड्स अधिराज्य
न्यूजीलैण्ड	न्यूजीलैण्ड
नाईजर	नाईजर
नाईजीरिया	नाईजीरिया
नार्वे	नार्वे
पाकिस्तान	पाकिस्तान
पैरागुवे	पैरागुवे
फिलिपाइन्स	फिलिपाइन्स
पोलैण्ड	पोलैण्ड
पुर्तगाल	पुर्तगाल
रूमानिया	रूमानिया
रुवाण्डा	रुवाण्डा
सऊदी अरब	सऊदी अरब
सैनेगल	सैनेगल
सियरा ल्योने	सियारा ल्योने
सिंगापुर	सिंगापुर
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य
स्पेन	स्पेन
श्रीलंका	श्रीलंका
स्वीडन	स्वीडन
स्विटजरलैण्ड	स्विटजरलैण्ड
सीरिया	सीरिया
तंजानिया सयुक्त गणराज्य	तंजानिया संयुक्त गणराज्य
ट्युनीशिया	ट्युनीशिया
युगाण्डा	युगाण्डा
यूकेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट संघ गणराज्य	यूकेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट संघ गणराज्य
युनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड	युनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड।
युनाईटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड	(क) ऐण्टीगुवा
	बहमास
	बरमुदा
	ब्रिटिश एण्टार्कटिक राज्यक्षेत्र
	ब्रिटिश होण्डुरस
	ब्रिटिश वर्जिन द्वीपि समूह
	केमेन, तुर्की और केकस द्वीपसमूह
	ऐक्रोटिरी और धेकेलिया (साईप्रस के राज्यक्षेत्र)
	डोमिनिका
	फाकलैण्ड द्वीप समूह और अधीन क्षेत्र
	जिब्राल्टर
	गिलबर्ट और एलिस द्वीपसमूह
	ग्रेनाडा
	हांगकांग
	माण्टसेरट
	सेण्ट क्रिस्टोफर और नेविस
	सेण्ट हेलेना और असेन्शन
	सेण्ट लूसिया
	सेण्ट विन्सेण्ट
	सेक्लीज
	ब्रिटिश सोलोमन द्वीपसमूह सरक्षित देश
	(ख) दक्षिणी रोडेशिया।
	(ग) ब्रुनेई
	टोंगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका
अपर वोल्टा	अपर वोल्टा
वेनेजुएला	वेनेजुएला
विएतनाम, गणराज्य	विएतनाम, गणराज्य
पश्चिमी सोमोआ	पश्चिमी सोमोआ
युगोस्लाविया	युगोस्लाविया
ज्येरे गणराज्य	जुयेरे, गणराज्य
जाम्बिया	जाम्बिया
	भाग 2
कनाडा	
कांगो, लोक गणराज्य	
क्यूबा	
इथोपिया	
संयुक्त राज्य अमेरिका	

[फा० सं० 5-ए०-73/69]

एस० एकामबरम, उप-सचिव

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4645.—In pursuance of sub-section (2) of section 3 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) and in supersession of the Notification of the Government of India in the late Department of Communications, No. M. 95, dated the 13th September, 1939, the Central Government hereby certifies that the High Contracting Parties specified in column 1 of Part I of the Table below shall be the High Contracting Parties to the Convention for the unification of certain rules relating to the International Carriage by Air signed at Warsaw on the 12th day of October, 1929 in respect of the territories specified in the corresponding entry in column 2 thereof, and further certifies that the High Contracting Parties mentioned in Part II of the

said Table have availed themselves of the provisions of rule 36 set out in the First Schedule to the said Act.

TABLE
PART I

High Contracting Parties to the Convention	Territories in respect of which they are parties
1	2
Afghanistan	Afghanistan
Algeria	Algeria
Argentina	Argentina
Australia	Papua, Norfolk Island, New Guinea
Austria	Austria
Barbados	Barbados
Belgium	Belgium
Brazil	Brazil
Bulgaria	Bulgaria
Burma	Burma
Byelorussian Soviet Socialist Republic	Bylorussian Soviet Socialist Republic
Cameroon	Cameroon
Canada	Canada
China, People's Republic of	China
Colombia	Colombia
Congo, People's Republic of the	Congo, People's Republic of the
Cuba	Cuba
Cyprus	Cyprus
Czechoslovakia	Czechoslovakia
Dahomey	Dahomey
Denmark	Denmark
Dominican Republic	Dominican Republic
Ecuador	Ecuador
Egypt, Arab Republic of	Egypt, Arab Republic of
Ethiopia	Ethiopia
Fiji	Fiji
Finland	Finland
France	France
Gabon	Gabon
Germany, Democratic Republic of	Germany, Democratic Republic of
Germany, Federal Republic of	Germany, Federal Republic of
Greece	Greece
Guatemala	Guatemala
Guinea	Guinea
Hungary	Hungary
Iceland	Iceland
India	India
Indonesia	Indonesia
Iraq	Iraq
Ireland	Ireland
Israel	Israel
Italy	Italy
Ivory Coast	Ivory Coast
Japan	Japan
Jordan	Jordan
Kenya	Kenya
Korea, Democratic People's Republic of	Korea, Democratic People's Republic of
Laos	Laos
Lebanon	Lebanon
Liberia	Liberia
Libyan Arab Republic	Libyan Arab Republic
Liechtenstein	Liechtenstein
Luxembourg	Luxembourg
Madagascar	Madagascar
Mali	Mali
Mauritania	Mauritania
Mexico	Mexico
Mongolia	Mongolia
Morocco	Morocco
Nepal	Nepal
Netherlands, Kingdom of the	Netherlands, Kingdom of the
New Zealand	New Zealand
Niger	Niger
Nigeria	Nigeria
Norway	Norway
Pakistan	Pakistan
Paraguay	Paraguay
Philippines	Philippines
Poland	Poland
Portugal	Portugal
Romania	Romania
Rwanda	Rwanda
Saudi Arabia	Saudi Arabia
Senegal	Senegal
Sierra Leone	Sierra Leone
Singapore	Singapore
South Africa, Republic of	South Africa, Republic of
Spain	Spain
Sri Lanka	Sri Lanka
Sweden	Sweden
Switzerland	Switzerland
Syria	Syria
Tanzania, United Republic of	Tanzania, United Republic of
Tunisia	Tunisia
Uganda	Uganda
Ukrainian Soviet Socialist Republic	Ukrainian Soviet Socialist Republic
Union of Soviet Socialist Republics	Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	(a) Antigua Bahamas Bermuda British Antarctic Territory Brtish Honduras British Virgin Islands Caymen, Turka and Cqicos Islands Akrotiri and Dhakelia (Territories of Cyprus) Dominica Falkland Islands and Dependencies Gibraltar Gilbert and Ellice Islands Grenada Hongkong Montserrat St. Chirstopher and Nevis St. Helena and Ascension St. Lucia St. Vincent Seychelles British Solomon Islands Protectorate (b) Southern Rhodesia (c) Brunei

1	2
	Tonga
United States of America	United States of America
Upper Volta	Upper Volta
Venezuela	Venezuela
Viet-Nam, Republic of	Viet-Nam, Republic of
Western Somoa	Western Somoa
Yugoslavia	Yugoslavia
Zaire, Republic of	Zaire, Republic of
Zambia	Zambia

PART II

Canada
Congo, People's Republic of the
Cuba
Ethiopia
The Philippines
The United States of America

[File No. 5-A/73-69]
S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4646.—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, 1960 के नियम 3 और 7 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० बी० दातार, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को श्री पी०एन० जैन के स्थान पर 5-12-1974 से नौवहन विकास निधि समिति के सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन एवं संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग—परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 628 दिनांक 17 मार्च, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"2. श्री ए० बी० दातार संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग"	5-12-1974

[सं० एम० एस० डी०-10/75 (एम०टी०)]

म०कृ० रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 14th September, 1975

S.O. 4646.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rules 3 and 7 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri A. B. Datar, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure as a member of the SDFC with effect from 5-12-1974 vice Shri P. N. Jain and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport—Transport Wing) No. S.O. 628, dated the 17th March, 1959, namely :—

In the said Notification, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"2. Shri A. B. Datar, Joint Secretary or Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure.	5-12-1974

[No. MSD-10/75(MD)]

M. K. RAMASWAMY, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4647.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है? उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उनके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
1 सहायक नगर प्रशासक, खेतड़ी, कापर काम्पलैक्स, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	स्वयं उनके या पट्टे पर लिए गए सरकारी स्थान, जो निम्नलिखित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। (1) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्पलैक्स की खेतड़ी और कोलिहान खानों के लिए खनन पट्टे के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र, और (2) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्पलैक्स नगरी और कालोनी के लिए पट्टाधृत या अर्जित ऐसे क्षेत्र जो हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आते हैं।

[सं० 11025/3/74-धातु 3]

सी०पी०एस० नायर, उप-सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 10th October, 1975

S.O. 4647.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government to be estate officer for the purposes of the said Act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by, or under, the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. Assistant Town Administrator, Khetri Copper Complex, Hindustan Copper Limited.	Public premises belonging to or taken on lease and falling within the area:- (1) covered by the mining lease for Khetri and Kolihan Mines of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited; and (2) the lease hold or acquired area, for the township and colony of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, which are under the administrative control of Hindustan Copper Limited and falling within the local limits of his jurisdiction.

[No.11025/3/73 Met.III].

C. P. S. NAIR, Dy. secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

का. आ. 4648.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने निडाडवोल टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-75 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-6/75-पी. एच. बी.]

पी. सी. गुप्ता, सहायक महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 4648.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-11-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nidadavole Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-6/75-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director

रेल मंत्रालय

रेल बोर्ड

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4649.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना सं० 75/एम० (एन०)/951/69, तारीख 12 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में मद 'अनुज्ञात अधिक लदान की सीमा' के अधीन उप मद

(2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद और टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) बी०ओ०एक्स० बी०ओ०आई०, बी०आर०एस०, बी०आर० एच०, बी० सी० एक्स०, बी० ओ० बी० एस०, बी० ओ० बी० एक्स० वैगनों की उनकी वहन क्षमता से 2 मीटर टन तक अधिक लदान करने दिया जा सकेगा।

टिप्पण :—टैंक—वैगनों की दशा में, किसी भी प्रकार का अधिक लदान नहीं करने दिया जाएगा।"

[सं 75/एम (एन०)/951/69]

ए०एल० गुप्ता,

सचिव, रेलवे बोर्ड और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the, 16th October, 1975

S.O. 4649.—In exercise of the following conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 53 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. 75/M(N)/951/69, dated the 12th September, 1975, namely :—

In the said notification, under item '1. Extent of overloading permitted', after sub-item (2), the following sub-item and note shall be inserted, namely :—

"(3) BOX, BOI, BRS, BRH, BCX, BOBS, wagons may be permitted the loading tolerance to the extent of 2 tones over the carrying capacity.

Note : No overloading is permitted in the case of tank wagons."

[No. 75/M(N)/951/69]

A. L. GUPTA, Secy., Railway Board and ex-officio Joint Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4650.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Satgram Colliery, Satgram Sub-area of the Coal Mines Authority Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th September, 1975.

BEFORE SHRI J. N. DAS, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) ASANSOL AND ARBITRATOR

Parties :

The Sub-Area Manager, Satgram Sub-Area, Coal Mines Authority Limited, Area No. III, P. O. Raniganj, (Burdwan)

Versus

Colliery Mazdoor Congress, Goral Mansion, G. T. Road, Asansol, P.O. Asansol. (Burdwan).

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri N. Das, Advocate.

For the Workmen.—Shri D. D. Mishra, Vice-President, Colliery Mazdoor Congress.

State.—West Bengal Industry.—Coal.

Dated the 23rd September, 1975

AWARD

The management of the Coal Mines Authority Limited, Eastern Division as represented by Shri B. N. Singh, Senior Personnel Officer (P), Satgram Sub-Area and the workmen of New Satgram Colliery as represented by Prof. Vinoy Kumar. General Secretary, Colliery Mazdoor Congress (HMP) by their agreement dated 10th March, 1975 referred the following matter under dispute under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 for my arbitration :—

"Whether the action of the management of New Satgram Colliery under Area No. III of Coal Mines Authority Limited was justified in covering the piece-rated trammers as time-rated trammers without giving increments for each year of services rendered by them on piece-rate. If not, how many increment should have been granted to them at the time of conversion from piece-rated to time-rated and what relief, if any, should they get now ?"

2. The parties submitted statements of their case as late as on 2-8-75 and thereafter parties were given hearing on different dates. The last and the final hearing was held on 10-9-75 when the management was represented by Shri N. Das Advocate and the union through its Vice-President, Shri D. D. Mishra,. Parties argued on the lines of their respective written statements.

3. The case of the union is that the 308 trammers employed below the ground in New Satgram Colliery were working for a long time on piece-rate basis and the management unilaterally changed their system of working from piece-rate to time-rate with effect from 24-9-73 and no notice as required under Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947 was given.

3.1. That, the workmen have been agitating over this issue from the very beginning and Shri Raj Narain, M. P. and the President of the union had written a letter in this respect to the Managing Director, Coal Mines Authority Limited in Eastern Division on 2-9-74.

3.2. That, the Wage Board Recommendations on Coal Mining Industry was accepted by the previous management of the New Satgram Colliery as well as the present owner, i.e., the Coal Mines Authority Limited.

3.3. That, while converting these trammers from piece-rate to time-rate the management should have given them appropriate increments as per the Recommendations of the Wage Board treating these trammers to be on piece-rate with effect from 15-8-66, i.e., the date from which the Wage Board's Recommendations were made applicable.

3.4. That, inspite of fixing these workmen as mentioned in the preceding paragraph the management gave several increments as they liked with the result that the workmen were put to a loss.

3.5. That, in several other areas of the Coal Mines Authority Limited. Eastern Division, namely, in Area No. II, IV and V many such conversion have taken place with regard to the trammers and loaders who had been working for a long time on piece-rate basis. Everywhere except in New Satgram Colliery the concerned workmen have been allowed special increments to compensate their loss.

3.6. Shri Mishra, therefore, demanded that the concerned workmen should be re-fixed as if they, were working on time-rate as on 15-8-66 and after allowing them the increments as per the Coal Wage Board's Recommendations for their past services they should be given annual increments for each of the subsequent year beginning from 15-8-67 and onwards till the day on which they were coverted into time-rate.

4. The management's view is that before converting the trammers concerned in this dispute into time-rate the management had consulted the majority union which was operating in the New Satgram Colliery, namely, the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC). A bilateral agreement was signed on 17-9-73 with the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) in which the concerned workmen were given appropriate increments depending on the length of their past services.

4.1. That, the management of the New Satgram Colliery was not bound to follow the procedure of fixation as might have been adopted in other Areas of the C.M.A. Ltd., because the conditions of working differ from place to place and from mine to mine.

4.2. That, the Wage Board on Coal Mining Industry does not visualise the manner of fixation as advocated by the union's representative.

4.3. That, there is no legal liability created upon the management of New Satgram Colliery under any statute, rule or by settlement or agreements to allow extra increments to the concerned workmen.

4.4. That, these workmen have already been allowed and paid their due increments flowing from the bilateral agreement dated 17-9-73.

4.5. That, the Wage Board have recommended that maximum number of increments for the past services of the workmen should not exceed three. The management have strictly adhered to this principle.

4.6. That, the present demand of the union for giving extra increment to the workmen concerned should be viewed with reference to the capacity of the colliery to pay.

4.7. That. the New Statgram Colliery has been running into loss and, as such, the present demand of the union cannot be acceded to.

4.8. That, if there is an objection of the union that the concerned workman should be reverted to their old system of working of piece-rate basis the management would willingly agree to it.

4.9. That, the demand of the union. therefore. should be rejected and it should be held that the management had rightly fixed the concerned trammers after allowing them appropriate increments on their conversion to time-rate.

5. After discussions and on examination of the various documents which have been marked as exhibits it was observed that some of the concerned trammers were employed in the year 1971. They on their conversion to time-rate have been allowed one increment. Again, those trammers appointed in the year 1970 have been given two increments and the trammers having been appointed between 1968-69 have been allowed three increments. The rest of the trammers who were appointed in 1968 or before were allowed four increments. The Recommendations of the Wage Board on Coal Mining Industry have provided that while adjusting into new scale of pay the increments that should be added for the past services rendered by the workmen should be as under :—

(a) For 3 years and over and below six years one increment.

(b) For six years and below nine years two increments, and

(c) For 9 years and more three increments.

5.1. Thus the Wage Board has allowed maximum increments of only three for the past services of the workmen. There is no dispute that the concerned trammers in New Satgram Colliery have been converted into time-rate from 24-9-73. Also there is no dispute that prior to this date these workmen were working on piece-rate system. The Union's representative did not contest the submission of the management that as visualised under the bilateral agreement dated 17-9-73 between them and the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) the workmen have been given increments as per the terms of the said agreement and the said increments have already been paid to them including the arrears.

5.2. Now the question arises as to how these workmen should have been fitted into the time rate scale with effect from 24-9-73. As had been detailed above the trammers who were appointed after 1971 were given one increment, those appointed in 1970 have been given two increments, those appointed between 1968-69 were given three increments and the trammers who were appointed in 1968 or before were given four increments. The fact that these trammers have been converted into time-rate on and from 24-9-73 is also not disputed. According to the union's view those trammers who were appointed in 1969 or before should have been given at least two more increments to cover up the loss in their earnings. The management, on the other hand, held the view that no loss has been sustained, by any of these trammers after their conversion into time-rate.

5.3. On discussion of the pros & cons of the submission of the parties management and the union became agreeable to allow at least one increment to all the trammers irrespective of the day of their appointment over and above what have been paid to them as a result of bi-lateral agreement dated 17-9-73. The only demand which was further stressed by the union is the date from which this increment should be availed of. As could be seen the Wage Board Recommendations on Coal Mining Industry is applicable with effect from 15-8-67 and the first increment to be allowed to the workmen was with effect from 15-8-68. It is, therefore, an accepted principle that the increments were allowed on 15th August every year in respect of those who were employed from before the commencement of the Wage Boards Recommendations. It, therefore, stand to reason that one increment which is to be given now to all the trammers concerned in this dispute should also be from 15-8-73 and that their future increment should also be given on 15th August, every year.

6. Since the union and the management have both agreed that one increment should be allowed to all the trammers concerned in this dispute over and above what have been allowed and paid to them as a result of the bi-lateral agreement dated 17-9-73, this increment should also be made available to them from 15-8-73 and that their annual increment would fall on 15-8-74 and so on.

7. In the result I decide that one more increment should be allowed to all the trammers concerned in this dispute with effect from 15-8-73 and they should be further allowed their annual increments on 15-8-74 and 15-8-75. I, therefore, order that the arrears of this additional increment is well as the annual increment which fell due on 15-8-74 and 15-8-75, if not allowed and paid already should be paid to the concerned workmen within a month of the date of publication of my award.

This is the award I give.

J. N. DAS, Regional Labour Commissioner (C),

Asansol & Arbitrator

[No. L 19012/5/75/DIII/B]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 4651.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th October, 1975.

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, (CENTRAL) CHANDIGARH

Reference No. 40/C of 1975

BETWEEN

The workmen and the management of the Union Bank of India, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Gurdarshan Singh.—for management.

None.—for the workmen.

AWARD

The services of Shri Sukhdev Kumar, peon, employed by the Union Bank of India, New Delhi, were alleged to have been terminated with effect from 3rd September, 1974. He was dis-satisfied with the orders of the bank authorities and raised an industrial dispute in this regard through Union Bank of India Employees' Union (Punjab) Regd., Jullundur City. The Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 referred as per Notification No. L. 12012/67/75/DII/A, dated 24th July, 1975, published in the Gazette of India, the following matter to this Tribunal for adjudication:—

> Whether the action of the management of the Union Bank of India, New Delhi, terminating the services of Shri Sukhdev Kumar, Peon, with effect from the 3rd September, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

2. Notices were issued to the parties requiring them to file their pleadings but none appeared on behalf of the workmen despite the service of notice per registered post acknowledgement due. Shri Gursharan Singh, Personnel Officer of the respondent bank, however, did appear and made a statement to the effect that the bank authorities had decided to take back Shri Sukhdev Kumar, Peon in service and that consequently the dispute has been amicably settled. From the non-appearances of the concerned workman or any on his behalf and the statement of Shri Gursharan Singh I am satisfied that the workman is not interested in pressing his claim, which seems to have been compromised. The claim is consequently dismissed as not pressed with no order as to costs.

7-9-1975.

H. R. SODHI, Presiding Officer.

[No. L. 12012/67/75/DII/A]

S.O. 4652.—In pursuance of section 17 of the Industrial DisputesAct,1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1975.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT 5/75

Ref:—Government of India, Ministry of Labour order No. L. 12012/80/74 LR III dated 30-5-1975.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Rajasthan Bank Employees Union, Rampura, Kota.

AND

United Commercial Bank, Bani Park, Jaipur.

APPEARANCES:

For the Union—None.

For the Bank.—Shri B. D. Bhatt.

Date of Award: 22-9-1975.

AWARD

The Central Government has made the following reference for adjudication to this Tribunal :—

> Whether the action of the management of the United Commercial Bank, Rampura Branch, Kota, in

denying joining period on transfer to Shri Nahar Singh, Watchman-cum-Peon, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

Notice were issued to the parties to appear before this Tribunal to file their claim and counter claim. Inspite of service of notice, no body on behalf of the Rajasthan Bank Employees Union appeared on two subsequent dates to file the statement of claim. It apears that the Union was not interested in pursuing the reference. A no dispute award is, therefore, passed.

[No. L. 12012/86/74/LRIII]

U. N. MATHUR, Judge

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 4653.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th October, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 46 of 1975

PRESENT

Shri E. K. Moidu, Presiding Officer

PARTIES:

Empolyers in relation to the management of the Food Corporation of India.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of Employers.—Shri S. K. Mitra, Deputy Manager (Personnel).

On behalf of Workmen.—Shri S. Basu Majumdar, Regional Secretary, Food Corporation of India Employees' Union.

State : West Bengal.

AWARD

This refernece was sent by the Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-42012/1/75/D. IIB dated 19th July, 1975, for adjudication to this Tribunal and it reads as follows :—

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India, Calcutta, in retrenching the under-mentioned 17 casual workmen with effect from the dates shown against their names, was justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

Name	Date of retrenchment
1. Shri Debidas Banerjee	1-7-1974
2. Shri Dipak Kumar Deb	1-7-1974
3. Shri Pradip Kumar Sil	1-7-1974
4. Shri Tapan Kumar Nag	1-7-1974
5. Shri Jyotirmay Chatterjee	1-7-1974
6. Shri Shyam Sunder Nandy	1-7-1974
7. Shri Johar Lal Ray	1-7-1974
8. Shri Mukumda Ray	1-7-1974
9. Shri Paritosh Dey	1.7.1974
10. Shri Debabrata Sengupta	1-7-1974
11. Shri Khokan Dasgupta	1-7-1974
12. Shri Ashim Kumar Sengupta	1-7-1974
13. Shri Sushil Kumar Nag	1-4-1974
14. Shri Birendra Nath Singh	1-4-1974
15. Shri Panchu Kawal	1-4-1974
16. Shri Radha Pada Ghosh	1-4-1974
17. Shri Gautam Mukherjee	1-4-1974

2. When the reference came up for hearing both the union and the employer filed a memorandum of settlement setting forth the terms of settlement. Both parties agree that an award may be passed in terms of the settlement. On consideration of the terms of settlement, I am satisfied that the settlement is for the best interest of the employer and employee to maintain peace and harmony amongst the labourers and the employer.

3. In the result an award is passed in terms of the settlement. A copy of the settlement will form part of the award.

Dated, Calcutta, the 3rd October, 1975.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

FORM-H

FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of Parties : Food Corporation of India & their workmen

Representing Employers : S;ri S. K. Mitra, Dy. Manager (Personnel) on behalf of Food Corporation of India

Representing Workmen : Food Corporation of India Employees' Union represented by Sri S. Basu Majumdar, Regional Secretary, Calcutta.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Retrenchment by the management of the Food Corporation of India, Calcutta, of 17 casual workmen with effect from 1-7-1974 for 12 such workmen and from 1-4-1974 for remaining 5 workmen.

TERMS OF SETTLEMENT

The employers have agreed that :—

(1) 17 casual labourers retrenched will be appointed as temporary casual workmen at the Depots/Rice Mills at Durgapur, Suri, Buniadpur and Bankura or anywhere in West Bengal.

(2) These casual workmen will be brought back to Calcutta or suburbs as and when suitable vacancies arise.

(3) The cases for appointment of these casual workmen on regular basis will be considered in normal course alongwith other casual workmen as and when management decide for such appointments at establishments where they will be working.

The Food Corporation of India Employees' Union agreed on behalf on the 17 casual workmen that:—

(1) The reference of the dispute to the Industrial Tribunal will be considered withdrawn.

(2) They will forego all claims arrears including retrenchment benefits from the date of retrenchment till the date of appointment.

Sd/- S. K. MITRA, Dy. Manager,

for Zonal Manager (Personnel).

Food Corporation of India, Calcutta.

Sd/- S. BASU MAJUMDAR, Regional Secy.

Food Corporation of India Employees' Union.

Witness:—

(1) Sd/- M. K. DUTTA,
Asstt. Manager,
Food Corporation of India.

(2) Sd/- Illegible
Regional Treasurer,
F.C.I.E.U.

[No. L. 42012(1)/75-DII(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 16th October, 1975

S.O. 4654.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Selected Fatka Colliery, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-9-75.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri K. K. Sarkar

Presiding Officer.

Reference No. 3 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's order No. F.No. L-2012/169/72-LRII, dt. 2-1-74)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Selected Fatka Colliery, P. O. Nirsachatti, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the Employers :—Shri S. S. Mukherjjee, Advocate.

On behalf of the Workmen :—Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 24th September, 1975

AWARD

In this reference which has been sent by the Government of India, Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication of the industrial disputes involved, the following issues were framed :—

"(1) Whether the action of the management of Selected Fatka Colliery, Post Office Nirsnachatti, District Dhanbad, in terminating the services of Sarvashri Jagdish Mistry and Dilwar Mian with effect from the 25 September, 1972 is justified?

(2) If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. The case of workmen in short is that identical chargesheets were issued against the concerned workmen Shri Jagdish Mistry and Dilwar Mian alleging some misconduct on their part.

The workmen concerned replied to the chargesheets denying the misconduct. It is alleged that the concerned workmen were not given opportunity to properly defend their case in the enquiry which was an empty formality. The management is alleged to have violated the principle of natural justice in conducting domestic enquiry and dismissing the concerned workmen from service. The management by their written statements deny above allegations and according to them a proper enquiry was held in which the misconduct was satisfactorily established against the concerned workmen and accordingly they were dismissed from the service. They deny that principles of natural justice were violated in conducting the enquiry or dismissing the concerned workmen. Another point taken by the management is that a Receiver was appointed by the Calcutta High Court in respect of the colliery in question who still continues as such and the Receiver cannot be made a party in this reference without obtaining to necessary permission of the Court which appointed him as Receiver nor any award can be passed against him. A written statement was submitted on behalf or Shri Sisir Kumar Roy Receiver of the colliery and it is his contention that present proceeding against Receiver is not maintainable without obtaining permission from the Hon'ble High Court at Calcutta.

Now, it is a case of dismissal of two workmen and the reference before us is dated 2-1-1974. Parties before me adduced evidence on the validity of the domestic enquiry only. This is permissible in view of decision of the Supreme Court in the case of workmen of Fire Stone Tyre and Rubber Co. vs management appearing in 1973(I) L.L.J. 278 Supreme Court. It is therefore open to this Tribunal to deal with the validity of the domestic enquiry when one is alleged to have been held as a preliminary issue. In support of their case the management examined two witnesses viz. Kalidas Mukherjee, MW.1 and Telu Ram Agarwalla, MW.2. According to MW.1, Shri T. R. Agarwalla who was Director of Srikrishna Colliery Co. (P) Ltd. owner of the Selected Fatka Colliery, held the domestic enquiry and he cannot throw further light on the above domestic enquiry. MW.2 the Director however says in his evidence that Shri Gopal Prasad, Personnel Officer held the domestic enquiry and he is not in service now. He seeks to prove the statements recorded by Shri Gopal Prasad in the domestic enquiry. He however admits that the statements of the witnesses were not recorded in his presence nor the enquiry was held in his presense. M.W.2 is not competent to prove the proceedings of the enquiry as he was neither present in the enquiry nor statement of witnesses were recorded in his presence. MW.2 however admits that the enquiry officer recorded no findings and he verbally recommended the dismissal of the concerned workmen as the charges were substantiated against them. Apart from the incompetency of MW.2 to prove the enquiry proceedings, no written report of findings by the enquiry officer was even filed as there was none. Apart from any other thing the question remains if the Tribunal can accept the proceedings of a domestic enquiry where no written report of findings was either made or submitted to the authorities. The Supreme Court in a case between Sannuggur Jute Factory Co. Ltd. and their workmen as reported in S.C.L.J. Vol. V page 2990 held that if at the end of the domestic enquiry the enquiry officer does not make report that itself introduces a serious infirmity in the enquiry and the Industrial Tribunal can in that case ignore the domestic enquiry .In that view of the matter the absence of the report of enquiry officer in the present case introduces a serious infirmity in the enquiry itself and on the order of dismissal based on the proceeding of the domstic enquiry without the report of the Enquiry Officer. This gross infirmity in the domestic enquiry vitiates the enquiry itself. It is now a settled law that where a domestic enquiry is vitiated for some infirmities in it, it will be deemed that there was no enquiry at all. The non-validity of the domestic enquiry is therefore established. The question remains whether in the circumstances of the case the employers should be given a chance to justify their action of dismissal of the concerned workmen. The law in this respect as it existed at one time was that when no domestic enquiry was held or the domestic enquiry is held to be vitiated by the Tribunal for some reason or other, the employers should be given a chance to justify their action on merit. If the above law continued there would have been no difficulty for me to afford apportunities to the employers to justify their action on merit. The law appears to have been altered to some extent in the decision of the Supreme Court in Delhi Cloth and General Mills Co. Limited-Vs-Ludh Budh Singh appearing in 1972 L. L. J. Vol.I page 180. Now in a case where the domestic enquiry is held to be vitiated the employers are required to make an application in writing for an opportunity to adduce evidence to justify their action on merit. In the above decision a stage has also been fixed by the Supreme Court by which time the employers are required to ask for an opportunity to adduce the evidence on merit to justify their action. According to the above decision the employers are to make a request to adduce evidence on merit to justify their action of dismissal during the pendency of the preliminary issue as to the validity of the domestic enquiry. It would

appear from the above ruling in D.C.M. case that the management has got a right to sustain its order by adducing independent evidence before the Tribunal. But the management should avail itself of the said opportunity by making a suitable request to the Tribunal before the proceedings are closed. In the present reference at no stage of the pendency of the hearing of the preliminary issue on the validity of the domestic enquiry has the management made a request for giving them an opportunity to adduce evidence on merit to justify their action. The management it appears has also not made any request even after the close of the hearing of the preliminary issue on the validity of the domestic enquiry for an opportunity afforded to them to adduce any evidence on merit to justify their action. In short, upto this date the management never made any request in the above respect. Working on the basis of law as enunciated by the Supreme Court above the employers cannot be afforded any opportunity to justify their action on merit after the preliminary issue on the validity of the domestic enquiry which has been held to be vitiated. The net position therefore comes to this that the domestic enquiry has been held to be vitiated by this Tribunal in its hearing on the preliminary issue and the management is not entitled under the law to be given any opportunity to adduce evidence to justify their action. The thing which comes to stay ultimately is that no domestic enquiry is deemed to have been held as it was found to be vitiated. The employers cannot therefore plead any justification in support of their action in dismissing the concerned workmen.

4. It was contended before me by the learned Advocate of the management that it is pleaded in the written statement of the Receiver that the concerned workmen are already working in Khas Shampur Colliery. Whether the concerned workmen are working elsewhere is relevant for the purpose of back wages and other benefits. It appears that in para 7 of the written statement of the Receiver it is pleaded that the Receiver has been informed that the concerned workmen are already working in Khas Shampur Colliery. How far this information can be relied upon is a question which must be supported by other facts and not on the information alone. In his evidence MW. 2 says that he knows that the concerned workmen are now working in Khas Shampur Colliery under the Coal Mines Authority. No satisfactory evidence is forthcoming in support of the fact that the concerned workmen are working in Khas Shampur Colliery or elsewhere. If however they have been actually working in that colliery back wages if granted to the concerned workmen will be subject to adjustment of the emoluments that they might have got elsewhere.

5. In the original reference the Receiver was not a party but after it was disclosed by the employers that the Receiver has been appointed in respect of the colliery the Receiver was impleaded as a party in this reference with notice. After the Receiver was appointed, the possession management and control of the colliery vested in the Receiver. The Receiver therefore becomes a necessary party in this reference as no effective award can be passed without making the Receiver a party in this reference and in view of the authority coming down from Section 18(3) of the Industrial Disputes Act the Receiver was rightly made a party in this reference. The question raised is that as the Receiver was appointed by the Calcutta High Court he cannot be impleaded as a party without permission of the Calcutta High Court which appointed him as a Receiver. Now the appointment of Receiver is governed by Civil Procedure Code, 1908. The appointment and other allied matters in respect of a Receiver is governed by order 40 rule 1 of Civil Procedure Code. Under the above provision of the Civil Procedure Code a Receiver cannot sue or be sued except with the leave of the Court by which he was appointed as a Receiver. In other words the institution of a suit against a Receiver must follow the leave of the Court by which he was appointed a Receiver. Now the Industrial Disputes Act is a special legislation governed by the procedure as prescribed by the Industrial Disputes Act, 1947 itself and rules made thereunder. The Civil Procedure Code has no application in a proceeding before the Industrial Tribunal except to a limited extent. According to Section 11 Subsection (3) of Industrial Disputes Act Labour Courts and Industrial Tribunals have the same powers as are vested in the Civil Court under the Code of Civil Procedure in respect of the following matters, viz.

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) compelling the production of documents and material objects;

(c) issuing commission for the examination of witnesses;

(d) in respect of such other matters as may be prescribed;

Rule 24 of the Industrial Disputes Act (Central) Rules, 1957 provides the following further matters in which the provisions of the Civil Procedure Code shall apply, viz. (i) discovery and inspection (ii) granting adjournment (iii) reception of evidence taken on affidavit. In respect of other matters, the powers have to be prescribed by the rules framed under the Industrial Disputes Act. In the absence of rules, other provisions of the Code of Civil Procedure are not applicable to proceedings before the Industrial Tribunals. It appears that the proceedings before Industrial Tribunals are to be deemed as judicial proceedings only within the meaning of Section 193 and 228 of the Indian Penal Code and such Tribunal are to be deemed as Civil Court only for the purpose of Section 480 and 482 of the Criminal Procedure Code. For all other purposes the Tribunal shall not be deemed to be Civil Court and the proceedings before them shall not be treated as judicial proceedings. In view of my analysis of the above law I am of the view that order 40 rule 1 of the Civil Procedure Code does not come within the limited application of the Civil Procedure Code, finding place in Section 11 of the Industrial Disputes Act and rule 24 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. Without prejudice to any existing law I consider that the Receiver has been rightly impleaded as a party in this Reference and the present proceedings are maintainable.

6. In the result, the action of the management of Selected Fatka Colliery, Post Office Nirshachatty, District Dhanbad in terminating the services of Sarvashri Jagdish Mistry and Dilwar Mian with effect from the 25th September, 1972 is not justified. The above two workmen are therefore entitled to be reinstated in their jobs with continuity of services and back wages after adjustment of the emoluments, if any received by them for the period of non-employment.

This is my award.

K. K. SARKAR, Judge,
Presiding Officer,

[No. L 2012/169/72/LR II]

G. C. SAXENA, Under Secy.

New Delhi, the 16th October, 1975

S.O. 4655.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the Indian Overseas Bank, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th October, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Madras

(Constituted by the Central Government)

Wednesday the 24th day of September, 1975

Industrial Dispute No. 23 of 1975.

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Indian Overseas Bank, Madras.)

BETWEEN

The workmen represented by :

The President, All India Overseas Bank Employees Union, 151, Mount Road, Madras-2.

AND

The Chairman, Indian Overseas Bank, Central Office, 151-Mount Road, Madras-2.

REFERENCE :

Order No. L. 12012/112/74/LR. III, dated 21st March, 1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 15th day of September, 1975 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal A. L. Somayaji and R. Jamal Nazeem, Advocates for the workmen and of Thiru N. G. R. Prasad, Advocate appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

The Government of India by its order No. L. 12012/112/74/LR. III dated 21st March, 1975, Ministry of Labour have referred the following dispute between the employers and the employees of the Indian Overseas Bank, Madras for adjudication by this Tribunal.

"Whether the management of Indian Overseas Bank, Madras were justified in terminating the service of Miss Bijaya Chakravarthi who was appointed as Telephone Operator in their Defence Colony Branch at New Delhi ? If not, to what benefit she is entitled and from what date ?"

2. The All India Overseas Bank Employees' Union has filed a claim statement alleging that one Miss Bijaya Chakravarthy was appointed on 20th July, 1973 by the Regional Manager of the Defence Colony Branch of the respondent Bank at New Delhi on a temporary basis and thereafter terminated the services of the employee concerned on 17-8-1973. The reason alleged for the termination is that the Regional Manager made this appointment without obtaining prior permission from the Head Office. The claimant Miss Bijaya Chakravarthy alleges that the termination is arbitrary and illegal and unjustified; that the Regional Manager acted for and on behalf of the Head Office as its agent and any act done by him as the Agent of the Head Office is binding on the principal; that this principle would apply even in the case where the agent has acted without authority. The other grounds alleged are that the termination is not bona fide, because the rival Trade Union brought pressure on the respondent to terminate the services of Miss Bijaya Chakravarthy. Lastly, it is alleged that the termination is an act of victimisation, because of her refusal to join the claimant union.

3. The respondent Bank has filed a counter statement contending that after the termination of the services of Miss Bijaya Chakravarthy, neither the employee concerned nor the claimant union made a demand on the Management of the Respondent Bank stating that the termination was not in order and that she should be taken back into service. Under these circumstances, there is no industrial dispute and hence the present reference is incompetent. On merits, the respondent Bank contends that the termination of the services of Miss Bijaya Chakravarthy is bona fide and valid; that the respondent Bank have been following a centralised system of recruitment; that no appointment including temporary appointments can be made by the branches without the specific sanction of the Central Office of the respondent Bank; that in this case, the Branch Manager of the Defence Colony Branch made the temporary appointment without the specific sanction of the Central Office and the Central Office refused to ratify this appointment made without authority and hence the Branch Manager terminated her services. The next contention is that Miss Bijaya Chakravarthy was only a temporary employee and her services could be terminated at any time. The respondent Bank also contends that the principle of agency cannot be applied to the instant case. The Management denies the allegations of victimisation.

4. ISSUE :

This dispute relates to the termination of the services of one Miss Bijaya Chakravarthy. The Defence Colony Branch in New Delhi, appointed temporarily Miss Bijaya Chakravarthy as a Telephone Operator on 20th July, 1973. Ex. M-2 is the letter written by the Agent of the Defence Colony Branch of the respondent Bank to the Staff Department asking for ratification of the appointment of Miss Bijaya Chakravarthy because the prior permission of the Central Office was not obtained before appointment. This letter is dated 24-7-1973. Ex. M-13 is the Manual for guidance of Regional Managers. Thiru A. J. Sellakumer, M.W. 1 is the Assistant General Manager (Personal), Central Office, Madras, Indian Overseas Bank (Recruits). His evidence discloses that the post of a Telephone Operator belongs to the clerical category; that the power of appointment vests with the Managing Director and that either the Regional Manager or Branch Manager cannot make appointment to the clerical post and that the procedure mentioned in Ex. M-13 was not followed in the matter of appointment of the Telephone Operator Miss Bijaya Chakravarthy in the Defence Colony Branch at New Delhi. Clause 29 of Ex. M-13 reads as follows :—

"29. Recruitment, postings and promotions to officer, clerical and cash department cadres will be handled at Central Office. Recruitment to the subordinate cadre will be done by the Regional Manager, but before doing so he must obtain Central Office sanction for increase in the strength or filling up a vacancy as the case may be, in the subordinate ranks."

Because this instruction seen in Clause 29 of the Manual for guidance of Regional Managers (i.e.) Ex. M-13 was not followed, the Agent wrote Ex. M-2 for ratification of the appointment. Ex. M-3 contains the notes made by the Chairman relating to the ratification asked for in Ex. M-2. M.W. 1 Thiru A. J. Sellakumar deposed that the Chairman did not confirm the appointment of Miss Bijaya Chakravarthy. This fact could be seen in Ex. M-3. Thereafter the Central Office of the Indian Overseas Bank sent a telex message and Ex. M-4 is the copy of the telex message. The Central Office did not ratify the appointment of Miss Bijaya Chakravarthy. Because it was against the instructions relating to the appointment of the clerical staff the services of Miss Bijaya Chakravarthy was terminated on 17-8-1973.

5. The learned counsel for the management raised a preliminary objection before me, namely, that no demand was made directly on the management before the reference. In other words, the argument was that, after the services of Miss Bijaya Chakravarthy was terminated, neither the employee nor the claimant union made any demand directly on the management stating that the termination is unjustified and that she should be taken in service. Unfortunately, the claimant Miss Bijaya Chakravarthy was not examined to contravert the allegation, namely, that there was no direct demand of the employee before raising the dispute to the effect that the termination of her services was unjustified, though the counsel for the Union took time to examine some office bearers of the Union, nobody was examined to show that at least the Union was authorised to raise this dispute and as a matter of fact, the Union made any demand directly on the management before the conciliation or the reference was made to this Tribunal. Ex. M-7, is the letter from the Union to the Labour Commissioner soliciting his intervention in the matter. In this letter, it is alleged that in contravention of Para 18.12 of the settlement between the management of Indian Overseas Bank and the Union, the Management is contemplating appointment of a new recruit to fill up a permanent vacancy without giving preference to the employee who had already worked temporarily and this instance has arisen at the Defence Colony Branch where a vacancy of a permanent telephone operator exists and where one Miss Bijaya Chakravarthi had been working temporarily. All that the Union wanted was that the Regional Labour Commissioner should interfere in the matter and ensure that this temporary employee should be given appointment in the vacancy. Ex. M-9 is the conciliation failure report. It also shows that the Union only demanded that Miss Bijaya Chakravarthy should be reinstated in service and appointed on a regular basis. It was not the case of the Union that the termination was not proper for the reasons now mentioned in the claim statement. In view of the fact that there was no demand directly on the management either before the conciliation or at the time of the conciliation mentioning that the termination was not valid or unjustified, the reference is incompetent.

6. Now coming to the case on merits. I will discuss the evidence to find out whether the termination is justified. Admittedly, the appointment was temporary in nature. Ex. M-13 shows that the Regional Manager should have obtained the prior permission from the Head Office before appointment to the clerical cadre. Admittedly, she worked only for 27 days. The management is entitled to ratify the defects in the matter of appointment. The Agent of the Defence Colony Branch had no authority to make this appointment. The claimant cannot ask this Tribunal to uphold an invalid appointment on the ground that it was not her fault.

7. The learned counsel for the union relied on a ruling reported in Indian Factories and Labour Reports—Volume 30—1975 at page 48. The facts of that case show that the Delhi Branch of the Indian Bank appointed a peon and the services of the peon were terminated after six months and that he challanged the order of termination on the ground that he was on probation and was confirmed on the expiry of six months. It is also seen that the management has alleged that the agent had no authority to appoint the peon. It was held in that case that even if the appointment made by the agent was to be approved by the head office that approval must be deemed to have been given by the conduct of the head office; that Section 197 of the Contract Act provides that ratification may be expressed or implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done. The principles laid down in that ruling is not applicable to the facts of our case. In the case concerned in this case within 27 days after the appointment, the Agent of the Delhi Branch of the Defence Colony found out that he had no authority to appoint and wrote to the Central Office for ratification. It is also significant to note that in the decisions cited, no objection was raised by the Head Office for a period of one year. In our case, the services were terminated within 27 days after the appointment. Under those circumstances, it cannot be said that there was any implied ratification. In the decision relied on by the counsel for the management, there was an implied ratification. On a consideration of the facts of our case, and the principles laid down in the decision. I come to the conclusion that the principles laid down in that decision cannot be applied to the facts of our case.

8. The fact that Miss Bijaya Chakravarthy was only a temporary employee cannot be disputed. The Bank has got every right to terminate the services of a temporary employee when it found that the Branch Manager had appointed without the sanction of the Central Office. There is no marit in the objection that the termination is capricious because within 27 days after the appointment of a temporary clerk, her services were terminated and no question of estoppel arises. If Miss Bijaya Chakravarthy had continued for 6 months or more or for a period of one year and drawn increments and other benefits then there can be some force in the contention that there was an implied ratification. So the terminaion cannot be said to be capricious or illegal or arbitrary. The management has terminated her services bona fide and there are absolutely no grounds for suspecting bona fieds of the management. In view of the fact that the order of termination was bona fide, no interference is called for. This issue is found against the claimant.

In the result, there will be an award holding that the termination of the services of Miss Bijaya Chakravarthy is justified and she is not entitled to any relief. There will be no order as to costs.

Dated, the 24th day of September, 1975.

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer

Industrial Tribunal

WITNESS EXAMINED

For workmen—Nil.
For management

M.W.1—Thiru A. J. Sellakumar, Assistant General Manager.

DOCUMENTS MARKED

For workmen—Nil.
For management

Ex.M-1/5-4-73.—Application of Bijaya Chakravarthy for the post of Telephone Operator.

Ex.M-2/24-7-73.—Letter from Defence Colony (New Delhi) Bank to the Head Office regarding recruitment of Telephone Operator.

Ex.M-3/7-8-73.—Office note to the General Manager regarding the recruitment of Telephone Operator.

Ex.M-4/16-8-73.—Cable massage to the New Delhi Branch Bank asking to terminate the services of Bijaya Chakravarthy.

Ex.M-5/16-8-73.—Letter from Defence Colony (New Delhi) Bank to the Head Office regarding the appointment of Telephone Operator.

Ex.M-6/21-8-73.—Letter from the Head Office to the Regional Manager, Indian Overseas Bank. New Delhi giving instructions for appointing telephone operator (copy).

Ex.M-7/14-2-74.—Letter from the Union to the Regional Labour Commissioner (C) Madras-6 soliciting his intervention in the matter.

Ex.M-8/9-7-74.—Letter from the Regional Manager, New Delhi Bank to the Head Office regarding appointment of Telephone Operator.

Ex.M-9/26-9-74.—Conciliation failure report.

Ex.M-10/16-11-74.—Application of Miss Ahuja Ramesh for the post of Telephone Operator.

Ex.M-11/12-11-74.—Appointment order issued to Miss Ramesh Ahuja.

Ex.M-12/19-1-71.—Certificates of Miss Ramesh Rani Ahuja issued by the Indian Posts and Telegraphs Department (Photostat copy).

Ex. M-13.—Manual for guidance of Regional Manager, Reorganization of the Banks Administrative and Operational structure.

Ex.M-14/21-8-73.—Original of Ex.M-6.

[No. L-12012/112/74-LR III]

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer,

Industrial Tribunal

Note: Particulars directed to take return of their documents within six months from the date of the award.

S. O. 4656.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th October, 1975.

BEFORE SHRI THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TIRBUNAL

(Constituted by the Central Government)

Thursday the 25th September, 1975

Industrial Dispute No. 10 of 1975.

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Bank of Madural Ltd., Madural).

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary,

Bank of Madurai Employees Union,

378, North Masi Street, Madurai (Tamil Nadu).

AND

The General Manager,

The Bank of Madural Limited,

33-North Chithrai Street, Madural (Tamil Nadu).

Reference :

Order No. L. 12012/120/74/LR. III, dated 10-2-1975 of the Ministry of Labour, Government of Tamil Nadu.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 16th day of September, 1975 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal A.L. somayaji and R. Jamal Nazeem, Advocates appearing for the workman and of Thiruvalargal M.R. Narayanaswami and S. Jayaraman, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India by its order No. L. 12012/120/74/LR. III, dated 10th February, 1975, Ministry of Labour have referred the following dispute between the employers and the employees of the Bank of Madurai Limited for adjudication by this Tribunal.

"Whether the action of the management of the Bank of Madurai Limited, Madurai in terminating the services of Sarvashri C.T. Chelliah, R. Mahalingam, S. Rangarajan, P.T. Abraham, Shrimathi M.R. Narmatha and A.V. Java and Kumari S. Aruna Devi, T. Kalyani and S. Visalakshi apprentice clerks, is justified ? If not, to what relief are they entitled ?"

2. The General Secretary of the Bank of Madurai Employees' Union has filed a claim statement alleging that the 9 workmen concerned in this dispute were appointed by the respondent as apprentice clerks; that the terms of appointment provided that the progress in work of these workmen would be reviewed every three months on the basis of the progress report and they would be informed of deficiencies, if any; that the workmen concerned in this dispute were performing their duties satisfactorily, and they were not informed of any deficiencies, but the management terminated the services of these 9 workmen concerned in the references for the reasons mentioned in the Annexure to the Claim Statement (i.e.) some for unsatisfactory work and some on the ground that their services were no longer required. It is alleged in the claim statement that the management had victimised the workmen because they were supporting the union and were effectively taking part in the conduct of the case I.D. No. 1 of 1973. Moreover, the workmen concerned in this reference, namely, S. Visalakshi, C.T. Chelliah, A.V. Rana and M.R. Narmatha are closely related to some of the office-bearers and active members of the union and therefore the management victimised them by terminating their services. The other allegation is that no opportunity was given to these employees to estabilsh that they were innocent before terminating their services. The Union contends that the termination is punitive in character.

3. The respondent Bank has filed a counter statement contending that there is no warrant for stating that there is any industrial dispute between the workmen and the management of the Bank of Madurai Ltd., that none of its other employees have sponsored the cause of the persons mentioned in the schedule to the order of reference and hence the reference is incompetent. The next contention is that in respect of seven out of nine persons, their claims are clearly barred in view of the Awards passed by this Tribunal in Complaints Nos. 2 to 8 of 1973. On merits, the respondent contends that the termination is justified because it has been done as per the terms of the order of appointment and that the management has got every right to terminate the services of temporary apprentices for reasons best known to them. The Management denies the alleged charge of victimisation.

4. Issue : The Bank of Madurai Limited, Madurai recruited apprentice clerks for imparting training and then absorbing them in the various branches. Hence Shri C.T. Chelliah, Thirumathi A.V. Rama, Kumari S. Aruna devi, Kumari S. Visalakshi, Thirumathi M.R. Narmatha, Shri R. Mahalingam, Shri S. Rangarajan, Shri P. J. Abraham and Kumari T. Kalyani were appointed on 22-7-1972, 21-6-1972, 21-6-1972, 21-6-1972, 21-6-1972, 8-11-1972, 22-7-1972, 22-7-1972 and 21-6-1972 respectively the services of Thiru C.T. Chelliah, W.W. 1 was terminated on 26-7-1973. The reason stated by the management was that his performance was not satisfactory and hence the services were no longer required. The services of Thirumathi A.V. Rama, W.W. 3 were terminated on 2-4-1973. The reason stated was that her services were no longer required. The services of Kumari S. Aruna Devi, W.W. 8 were terminated on 2-4-1973 or the reason that her services were no longer required. The services of Kumari S. Visalakshi, W.W. 2 were terminated on 2-4-1973 for the reason that her services were no longer required. So also the services of Thirumathi M.R. Narmatha were terminated on 23-6-1973 on the ground that her performance during the apprenticeship period was unsatisfactory The services of Shri R. Mahalingam, W.W. 7 were terminated on 15-6-1973 on the ground that his services were no longer required. The Bank terminated the services of Shri S. Rangarajan, W.W. 4 on 27-6-1973 on the ground that his services were not required and relieved from the bank. The services of Shri P.I. Abraham, W.W. 5 were terminated on 26-7-1973 on the ground that his performance during the apprenticeship period was unsatisfactory. So also the services of Kumari T. Kalyani, W.W. 6 were terminated on 23-6-1973 on the ground that her performance during the apprenticeship period was not satisfactory.

5. The grievance of these nine apprentice clerks as set out in paragraph 6 of the claim statement is that they were victimised because they were supporting the union in pursuing the matters effectively, when I.D. No. 1 of 1973 was pending in this Tribunal. The other reason set out for termination of services is that their relations are office-bearers in the Union and also active members and hence the management victimised them by terminating the services of Kumari S. Visalakshi, Shri C.T. Chelliah, Thirumathi A.V. Rama and Thirumathi M.R. Narmatha.

6. Now I will discuss the evidence in this case to find out how far the Union was able to prove the grounds set out in the claim statement for contending that the order of termination of the 9 apprentice clerks are not justifiable. To support the plea that these workmen were supporting the Union activities and their relations are active supporters of the Union, the Union examined 8 witnesses as W.W. 1 to W.W. 8 Sri C.T. Chelliah, W.W. 1 deposed before me that he gave evidence in I.D. No. 1 of 1973 and supported the stand of the Union. His grievance also is that his father was placed under suspension by the Bank. In the course of the cross-examination, he admitted that in May, 1972, his father was suspended. When pursuad further, he stated that he did not know the reason for his suspension. To the question put up by the counsel for the management stating that his father was suspended for assaulting a superior officer he gave an evasive answer by stating that he does not know. He also stated that his father was an active member of the Employees' Union. It is seen from his evidence that his father was suspended for assaulting a superior officer and that the Bank never intended to victimise him. Thirumathi S. Visalakshi, W.W. 2 deposed that Mr. S. Sundaram, her brother is the Joint Secretary of the Union and so the Management thought to victimise her by terminating her services. In the course of the cross-examination, she gave an evasive answer to the question whether Thiru Sundaram was dismissed for some misconduct or whether approval was obtained from the Tribunal for terminating his services. Thus it is clearly seen that the services of Thirumathi S. Visalakshi, W.W. 2 was not terminated for alleged victimisation. Thirumathi A.V. Rama, W.W. 3 deposed that her husband was the Secretary of the Union branch and he was suspended from service. In the course of the cross-examination, she admitted that on 2-4-1973, when her services were terminated, her husband was in service and he continues to be in service till today. Thus it is seen that the ground set out cannot be true. Shri S. Rangarajan, W.W. 4 has not stated any reason for alleged victimisation. Sri P.I. Abraham, W.W. 5 has deposed that his father was working as a clerk in the Quilon Branch and he is an active member of the union and now he is looking after the affairs of the Trivandrum Branch of the Bank This was stated to be the reason for terminating his services. In the course of the cross-examination, he admitted that his father is still in service. That being so it is highly unlikely that instead of terminating the services of an active member of the union on some flimsy grounds the Bank thought fit of terminating the services of an apprentice clerk. Thirumathi T. Kalyani, W.W. 6 has not spoken any reason for the alleged victimisation. Sri R. Mahalingam, W.W. 7 has not stated any grounds for the alleged victimisation. Thirumathi S. Aruna Devi, W.W. 8 has not stated any grounds for the alleged victimisation. The ground of victimisation put forward in para 6 of the claim statement can only be imaginary for the following reasons : It is the common case of both the parties that the Union took about 380 persons as apprentice clerks and confirmed about 303. The evidence of

W.W. 8 do not establish the alleged ground of victimisation set out in para (6) of the claim statement. It is seen that inspite of the trade union activities of some of the relations of the witnesses they are still in service and they are not punished. The Union has failed to establish the ground of victimisation set out in para (6) of the claim statement. Further it is strange to contend that the Bank thought fit of vitimising only these 9 apprentice clerks when the Bank confirmed about 303 apprentice clerks out of a total of 380. As already held, the materials furnished before me for alleged ground of victimisation are totally inadequate.

6. The learned counsel for the Union, Mr. Somayaji argued that these 9 apprentice clerks were appointed for imparting training and no enquiry was held before terminating their services. The second argument was that some of the apprentice clerks were dissmissed for unsatisfactory work and unsatisfactroy work would amount to misconduct and so in the absence of any domestic enquiry, the order of termination cannot be justified. He also argued that an apprentice is also a probationer and *the principles applied to a probationer should also be extended* to apprentices. In support of his argument, he referred to the decision reported in 1966—I—L.L.J.—page 398 (Utkal Machinery Ltd., Vs. Santi Patnaik (Miss). The above decision related to the discharge of a probationer during the period of probation. It is seen from the facts of the decisio n that no evidence was adduced by the employer before the Labour Court dealing with the dispute as to the unsatisfactory work of the concerned employee and no held tha t the termination of the services of the probationer was punitive and mala fide and the Labour Court awarded one year's salary as compensation to the concerned employee. Now we have to find out whether the principles laid down in that ruling can be applied to the facts of our case.

Their Lordships have observed the general principles at page 400. It is as follows :—

> "We shall, however, assume in favour of the appellant that the respondent was appointed on 9th December, 1961, on probation for a period of six months and it was stipulated in the contract that during the probationery period the services of the respondent could be terminated without notice and without assigning any reason. In other words, the management had the contractual right to terminate the services of the respondent without assigning any reason therefore. But if the validity of the termination in challenged in an industrial adjudication, it would be competent to the industrial tribunal to enquire whether the order of termination has been effected in the bona fide exercise of its power conferred by the contract. If the discharge of the employee has been ordered by the management in bona fide exercise of its power, the industrial tribunal will not interfere with it, but it is open to the industrial tribunal to consider whether the order of termination is mala fide or whether it amounts to victimisation of the employee or an unfair labour practices or is so capricious or unreasonable would lead to the inference that it has been passed for ulterior motives and not in bona fide exercise of the power arising out of the contract. In such a case it is open to the industrial tribunal to interfere with the order of the management and to afford proper relief to the employee".

So we have to find out whether the order of termination is bona fide. As already stated the services of some of the apprentice clerks were terminated for unsatisfactory work and some on the grounds that their services were no longer required. The Bank took about 380 apprentices clerks and confirmed about 303. No satisfactory materials were placed before this Tribunal for coming to the conclusion that the Bank with mala fides thought fit of terminating the services of a 9 apprentice clerks. Sri K. Thiagaraja, M. W. 1 is the Deputy Cheif Officer, Staff Department in the Central Office, Madukarai was examined to prove the bona fide of the Bank in terminating the services of these apprentice clerks. His evidence discloses that the Agent will review the work of apprentice clerks once in 3 months ; that if his work is not found satisfactory he would be given another section ; that the Bank do not make out a record of their performance ; that at the end of the year, the Head Office will call for the report of the concerned apprentice clerk and Ex. M-8 is the sample of such report and that after the yearly report relating to an apprentice clerks the Central Office would confirm or terminate the services. He furhter stated that once in 3 months the Agent would inform orally the apprentice clerks about his or her satisfactory nature or otherwise of the work. It is seen that on the basis of the reports from the agent, the management terminated the services of some for unsatisfactory work and some on the ground that their services were no longer required. Further this witness stated that in case, the Agent sends an unsatisfactory report, the Management would immediatley terminate the service and no the Agent did not put in writing and send to the Head Office or give to the concerned clerk. One thing is clear, namely, that the Agent was reviewing the work of apprentice clerks. Hence there is no merit in this objection that some of the clauses in the appointment orders were not strictly observed. The several orders of termination issued to these 9 clerks do not suggest any misconduct on the part of these clerks. On a consideration of the evidence of M.W. 1 and the surrounding circumstances, I have no hesitation in coming to the conclusion that the orders of termination issued by the Bank are bona fide. In view of my discussion above I am of the view that the Union in this case cannot contend that because a probationer was awared compensation, the apprentices clerks also are entitled to compensation or other reliefs. On the facts of that case, it was decided that the discharge of the probationer was mala fide and compensation was awarded. Further, our case relates apprentice clerks. There is lot of difference between apprentice clerks and the probationers. The apprentice clerks are taken for the purpose of imparting training, so that they may be found sutiable after the period of apprenticeship to do the work of a permanent clerks. The probationer is appointed to a permanent post and he will be entitled to come of the benefits of a permanent clerk after the period of probation. But here, in the case of apprentice clerks, they are paid only stipends and not a regular pay like that of a permanent employee. A probationer found suitable after the period of probation would be absorbed to the permanent post. But whereas the apprentice clerks is not entitled to get posting as a matter of right to the permanent post of clerk after the expiry of the period of apprenticeship. As the decision related only to the probationer, the decision in that ruling cannot be applied to the case of apprentice clerks.

7. The learned counsel for the Union argued that unsatisfactory work would amount to misconduct and that there is an observation to that effect in the decision reported in 1966—I—L.L.J—page 399. It is true that their Lordships have observed at page 400 as follows :—

> "In the absence of any standing order the unsatisfactory work of an employee may be treated as misconduct and when the respondent was discharged according to the management for unsatisfatory work it would be taken that her discharge was tentamount to punishment for an alleged misconduct."

The quesion is whether those observations can be applied to the facts of our case. It is seen from that ruling that the management witnesses did not speak a word about unsatisfactory nature of work of its employees and there was no evidence to support the allegation and no documents were produced on behalf of the management to illustrate the unsatisfactory nature of work. On facts of that case, their lordships held that the unstatisfactory work would amount to misconduct. But here the management has placed evidence to prove the unsatisfactory nature of work. In the Supreme Court decision reported in 1972-1-L.L.J.-page 501 at page 509, (Air-India Corporation, Bombay Vs. V. A. Rebellow and another) their lordships have held as follows :—

> "The fact that the employer is not fully satisfied with the overall result of the performance of his duties by his employee does not necessarily imply misconduct on his part."

So the learned counsel for the Union cannot invoke to its aid the observation made in 1966—I—L.L.J to the effect that the unsatisfactory work would amount to misconduct and apply to the facts of our case. In view of my discussion above. I held that there are absolutely no grounds to come to the conclusion that the termination of all the 9 workmen are not bona fide. Further the Union has failed to prove that the Management took action for their trade union activities and thus this is a case of victimication. In view of my discussion I find this issue against the claimants.

8. In the result, an award is passed holding that the termination of nine persons mentioned in the reference is justified. There will be no order as to costs.

Dated, this 25th day of September, 1975.

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer's Industrial Triubnal.

WITNESSES EXAMINED

For Workmen—

W.W.1 — Thiru C.T. Chelliah.

W.W.2 — Thirumathi S. Visalekshi

W.W.3 — Thirumathi A.Y. Rama

W.W.4 — Thiru S. Bangarajan

W.W.5 — Thiru P.I. Abraham

W.W.6 — Thirumathi T. Kalyani

W.W.7 — Thiru R. Mahelingam

W.W.8 — Thirumathi S. Aruna Devi

For management—

M.W.1. — Thiru K. Thiagarajan, Deputy Chief Officer, Staff Department.

DOCUMENTS MARKED

For workmen—

Ex.W-1/21-6-72 — Order of appointment issued to W.W.2. (copy).

Ex.W-2/2-4-73 — Order of discharge issued to W.W.2. (copy).

Ex.W-3/22-7-72 — Order of appointment issued to W.W.1 (copy).

Ex.W-4/26-7-73 — Order of discharge issued to W.W.1 (copy).

Ex.W-5/21-6-72 — Order of appointment issued to W.W.3 (copy).

Ex.W-6/2-4-73 — Order of discharge issued to W.W.3 (copy).

Ex.W-7/21-6-72 — Order of appointment issued to Thirumathi M.R. Harmatha (copy).

Ex.W-8/23-6-73 — Order of discharge issued to Thirumathi M.R. Narmatha (copy).

Ex.W-9/22-7-72 — Appointment order issued to W.W.4 (copy).

Ex.W-10/29-6-73 — Discharge order issued to W.W.4 (copy).

Ex.W-11/25-6-73 — Suspension order issued to W.W.4 (copy).

Ex.W-12/8-11-72 — Appointment order issued to W.W.7 (copy).

Ex.W-13/15-6-73 — Discharge order issued to W.W.7 (copy).

Ex.W-14/21-6-72 — Appointment order issued to W.W.8 (copy).

Ex.W-15/2-4-73 — Discharge order issued to W.W.8 (copy).

Ex.W-16/22-7-72 — Appointment order issued to W.W.5 (copy).

Ex.W-17/26-7-73 — Discharge order issued to W.W.5 (copy).

Ex.W-18/21-6-72 — Appointment order issued to W.W.6 (copy).

Ex.W-19/23-6-73 — Discharge order issued to W.W.6 (copy).

Ex.W-20/10-9-72 — Letter of authorisation by W.W.1 to the union to take steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-21/20-12-72 — Letter of authorisation by W.W.3 to the union to take steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-22/25-6-73 — Suspension order issued to W.W.4.

Ex.W-23/27-6-73 — Discharge order issued to W.W.4.

Ex.W-24/29-6-73 — Discharge order issued to W.W.4.

Ex.W-25/2-6-73 — Authorization letter by W.W.7 to the union for taking necessary steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-26/25-2-73 — Authorisation letter by W.W.2 to the union for taking necessary steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-27/17-6-73 — Authorisation letter by M.R. Warmatha to the union for taking necessary steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-28/25-8-72 — Authorisation letter by W.W.8 to the union for taking necessary steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-29/17-6-73 — Authorisation letter by W.W.4 to the union for taking necessary steps for getting full benefits (copy).

Ex.W-30/26-4-74 — Award in I.D. No. 1 of 1973 of the Industrial Tribunal, Madras (printed book).

For Management—

Ex.M-1/20-2-74 — Award in C. No. 2/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-2/20-2-74 — Award in C. No. 3/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-3/20-2-74 — Award in C. No. 4/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-4/20-2-74 — Award in C. No. 5/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-5/20-2-74 — Award in C. No. 6/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-6/20-2-74 — Award in C. No. 7/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-7/20-2-74 — Award in C. No. 8/73 in I.D. No. 1/73 of the Industrial Tribunal, Madras (copy).

Ex.M-8/24-5-73 — Report of the Agent, Tenkani Branch about W.W.7 (copy).

Ex.M-9/19-7-73 — Report of the Interviewing Officer about W.W.5 (copy).

Ex.M-10/24-5-73 — Original of Ex. M-8.

T. PALANIAPPAN, Presiding Officer, Industrial Tribunal.

NOTE : —Parties are directed to take return of their document's within six months from the date of the Award

[No. L 12012/120/74-LIII

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1975.